रजिस्ट्री सं० डी एल (एन) 04/0007/2003—05

REGD. No. DL (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, जनवरी 23—जनवरी 29, 2005, शनिवार/माघ 3—माघ 9, 1926

No. 5] NEW DELHI, JANUARY 23—JANUARY 29, 2005, SATURDAY/ MAGHA 3—MAGHA 9, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल

कार्यालय आदेश

लखनऊ, 19 नवम्बर, 2004

सेवा समाप्ति का नोटिस

का.आ. 304.—केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई नियमावली, 1965) के नियम 5 के उप-नियम (1) के साथ पठित के.रि.पु.बल नियमावली, 1955 की परिशिष्ठ एफ के अन्तर्गत नियम 16 एवं नोट-2 के अनुसरण में, मैं देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु.बल, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) इस ग्रुप केन्द्र की बल संख्या 047020094 हेड कांस्टेबल (मंत्रा.) मन्दोदरी सेठी को एतद्द्वारा इस आशय का नोटिस देता हूँ कि उसकी सेवाएं यह नोटिस जारी होने की तारीख से एक माह समाप्त होने की तारीख से समाप्त कर दी जाएगी।

[सं. पी आठ-18/2004-ग्रु. के.-स्था-2]

देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस उप महानिरीक्षक

OFFICE OF THE ADDL. DIGP. GROUP CENTRE, C.R.P.F.

OFFICE ORDER

Lucknow, the 19th November, 2004

Notice for Termination from Service

S.O. 304.—In pursuance of Sub rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Service (Temporary Rules, 1965) read with rule 16 and note 2 below Appendix 'F' to CRPF Rules, 1955, I, Devendra Kumar, Addl. DIGP, GC CRPF Lucknow (U.P)

hereby give notice to No. 047020094 HC (Min.) Mandodari Sethi of this GC, that her services shall stand terminated with effect from the date of expiry of one month from the date of issue of this notice.

[No. P. VIII-18/2004-GC-EC-II]

DEVENDRA KUMAR, Addl. DIGP

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पुणे-III के आयुक्त का कार्यालय)

पुणे, 5 जनवरी, 2005

संख्या 01/2005 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (नॉन-टैरिफ)

का.आ. 305.—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 1-7-94 को जारी की गई अधिसूचना संख्या 33/1994 सीमा शुल्क (नॉन-टैरिफ) के अधीन मुझे प्रदत्त अधिकारों को कार्यान्वित करते हुए, मैं, ए. एस.आर. नायर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क पुणे-III आयुक्तालय पुणे एतद्द्वारा महाराष्ट्र राज्य के गांव-भरे, तालुका-मुलशी जिला पुणे-412111 को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अधीन तथा 100% ई.ओ.यू. स्थापना हेतु, वेयरहाउसिंग स्टेशन के रूप में घोषित कर रहा हूँ।

[फा. सं. वी.जी.एन.(30)587/टीए/04]

ए. एस. आर. नायर, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS, PUNE-III)

Pune, the 5th January, 2005

No. 01/2005, C. Ex. (N.T.)

S.O. 305.—In exercise of the powers conferred on me by the Notification No. 33/1994 Cus. (N.T.), dated 1-7-1994, of the Government of India, Ministry of Finance, Department of evenue, I, A.S.R. Nair, Commissioner of Central Excise and Customs, Pune-III Commissionerate, Pune, hereby declare Village : Bhare, Taluka : Mulshi, Dist. Pune–412111, in the state of Maharashtra to be warehousing station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), for setting up of 100% EOU's.

[F. No. V.G.N. (30)587/TA/04]

A.S.R. NAIR, Commissioner

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2005

का. आ. 306.—सरकार ने यह निर्णय लिया है कि श्री पी. के. गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यभार संभालने की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए अथवा पंजाब एंड सिंध बैंक के नियमित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, अपने कार्यों के साथ-साथ पंजाब एंड सिंध बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार भी पूर्णरूपेण संभालेंगे।

[फा. सं. 9/31/2004-बीओ-I]

रमेश चन्द, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

ORDER

New Delhi, the 18th January, 2005

S.O. 306.—Government have decided that Shri P. K. Gupta, Chairman and Managing Director, National Housing Bank, will hold full additional charge of the post of Chairman and Managing Director, Punjab & Sind Bank, in addition to his own duties for a period of three months from the date of taking charge or until appointment of regular Chairman and Managing Director in Punjab & Sind Bank, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/31/2004-BO-I]

RAMESH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2005

का. आ. 307.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड 3 के उपखंड (1), खंड 5, खंड 6, खंड 7 और खंड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री एन. कांताकुमार, जो वर्तमान में केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं, को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31 मार्च, 2006 तक अर्थात् अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 9/23/2003-बीओ-I]

रमेश चन्द्र, अवर सचिव

New Delhi, the 19th January, 2005

S.O. 307.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-clause (1) of clause 3, clause 5, clause 6, clause 7 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri N. Kantha Kumar presently Executive Director, Canara Bank as Chairman and Managing Director, Syndicate Bank from the date of his taking charge of the post and upto 31-03-2006 i.e. date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/23/2003-BO-I]

RAMESH CHAND, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

(सी.पी.वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2004

का.आ. 308.—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का प्रधान कौंसलावास, जद्दा में श्री इमाम मेहदि हुसैन, सहायक को 22-12-2004 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2004]

नपेन्द्र सिंह रावत, अवर सचिव (कौंसुलर)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(C.P.V. DIVISION)

New Delhi, the 22nd December, 2004

S.O. 308.—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri Imam Mehdi Hussain, Assistant in the Consulate General of India, Jeddah to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 22-12-2004.

[F. No. T-4330/01/2004]

U. S. RAWAT, Under Secy. (Cons.)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2004

का.आ. 309.—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का प्रधान कौंसलावास, बर्मिंघम में श्री आर. के. चक्रबोरती, सहायक को 22-12-2004 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2004]

उपेन्द्र सिंह रावत, अवर सचिव (कौंसुलर)

New Delhi, the 22nd December, 2004

S.O. 309.—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri R.K. Chakraborty, Assistant in the Consulate General of India, Birmingham to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 22-12-2004

[F. No. T-4330/01/2004]

U. S. RAWAT, Under Secy. (Cons.)

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2004

का.आ. 310.—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का उच्चायोग, कैनबेरा में श्री विरेन्द्र देव, सहायक को 22-12-2004 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2004]

उपेन्द्र सिंह रावत, अवर सचिव (कौंसुलर)

New Delhi, the 22nd December, 2004

S.O. 310.—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government Shri Virender Dev, Assistant in the High Commission of India, Canberra has been authorised to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 03-11-2003.

[F. No. T-4330/01/2004]

U. S. RAWAT, Under Secy. (Cons.)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2005

का.आ. 311.—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41वां) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का राजदूतावास, वियतनाम में श्री शेशदेव डैश, सहायक को 06-01-2005 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. टी-4330/01/2004]

उपेन्द्र सिंह रावत, अवर सचिव (कौंसुलर)

New Delhi, the 6th January, 2005

S.O. 311.—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri Sheshadev Dash, Assistant in the Embassy of India, Vietnam to perform the duties of Assistant Consular Officer with effect from 06-01-2005.

[F. No. T-4330/01/2005]

U. S. RAWAT, Under Secy. (Cons.)

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2005

का.आ. 312.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम 4 के अनुसरण में पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित कार्यालय में 80% से अधिक कर्मचारियों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उसे एतद्द्वारा अधिसूचित करती है :—

मुरगांव पत्तन न्यास,
प्रशासनिक कार्यालय,
हेडलैण्ड सडा,
गोवा-403804

[फा. सं. ई-11011/1/2000-हिन्दी]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

New Delhi, the 20th January, 2005

S.O. 312.—In pursuance of the Sub rule (4) of the Rule 10 of the Official Language (use for the official purpose of the Union) Rules, 1976 (as amended 1987), the Central Government hereby notifies the following office under the administrative control of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, more than 80% of the staff of which have acquired working knowledge of Hindi :—

Mormugao Port Trust,
Administrative Office,
Headland Sada,
Goa–403804

[F. No. E-11011/1/2000-Hindi]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 313.—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), राजभाषा नियम 1976 (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुसरण में इण्डियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिजम कार्पोरेशन लिमि. नई दिल्ली, को, जहां 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को एतद्द्वारा अधिसूचित करता है।

[फा. सं. हिन्दी-2003/रा.भा. 1/12/3]

वी. एन. माथुर, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 313.—Ministry of Railways (Railway Board), in pursuance of Sub Rules (2) and (4) of Rule 10 of the Official Language Rules, 1976 (use for the official purposes of the Union) hereby, notify the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., New Delhi, where 80% or more Officers/Employees have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. Hindi-2003/O.L. 1/12/3]

V. N. MATHUR, Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 314.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स दिव्या मार्केटिंग कंपनी, 17 पी एंड टी कालोनी, राणा प्रताप नगर, नागपुर-440015 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग II) वाले ''डी जे'' शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित (टेबल टाप प्रकार) के तोलन उपकरण के माडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''डी एम सी'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/192 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित टेबल टाप प्रकार का अस्वचालित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 2 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि. ग्रा. तक ''ई'' मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान अन्तराल (एन) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यूएम-21(46)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 314.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of "DJ" series of high accuracy (Accuracy Class-II) and with brand name "DMC" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s Divya Marketing Company, 17, P&T Colony, Rana Pratap Nagar, Nagpur-440015 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/192;

The said model is a strain gauze type load cell based non automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30 kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 2g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for 'e' value of 1mg to 50 mg and with verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100mg or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(46)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 315.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स दिव्या मार्केटिंग कंपनी, 17 पी एंड टी कालोनी, राणा प्रताप नगर, नागपुर-440 015 द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग III) वाले "डी पी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित (प्लेटफार्म प्रकार) के तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "डी एम सी" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/193 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित प्लेटफार्म प्रकार का अस्वचालित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 4 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 200 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 5000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k} के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(46)/2003]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 315.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of "DP" series of medium accuracy (Accuracy Class-III) and with brand name "DMC" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Divya Marketing Company, 17, P&T Colony, Rana Pratap Nagar, Nagpur-440 015 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/193;

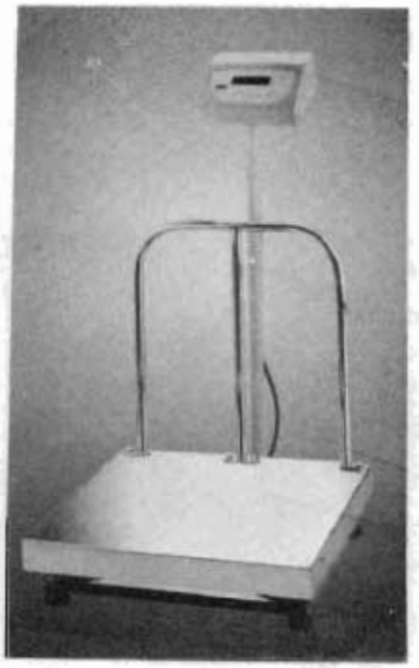

The said Model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 1000kg. and minimum capacity of 4kg. The verifiaction scale interval (e) is 200g. It has a tare device with a 100 per cent subtrative retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V,. 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg. and up to 5000kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k is a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(46)/2003]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 316.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एल्डर इन्स्ट्रूमेंट्स प्रा. लि., डब्ल्यू-345, टी टी सी इंडस्ट्रियल एरिया, राबेले, नवी मुंबई-400 701 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग II) वाले "एच आर" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "एल्डरपान" है (जिसे इसमें इसको उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/125 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

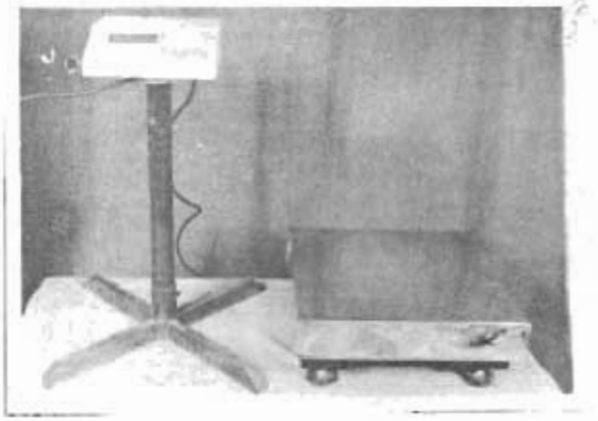

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार का) है। इसकी अधिकतम क्षमता 600 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2.5 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 50 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान (एन) अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. से 1000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k} के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(266)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 316.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of "HR" series of high accuracy (accuracy Class-II) and with brand name "ELDERPAN" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Elder Instruments Pvt. Ltd., W-345, TTC Industrial Area, Rabale, Navi Mumbai-400 701 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/125;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 600kg. and minimum capacity of 2.5kg. The verifiaction scale interval (e) is 50g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230volts and, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

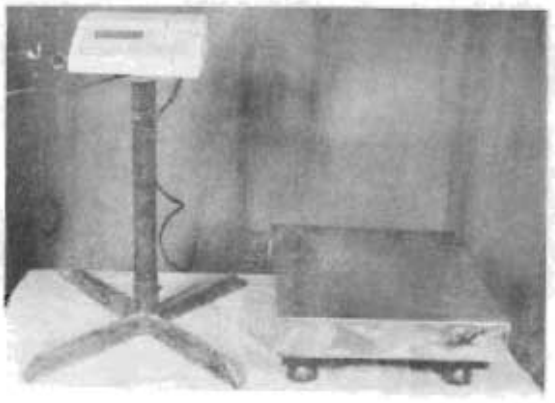

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of the said Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, and performance of same series with maximum capacity ranging above 50kg. to 1000kg. and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100mg or more and with 'e' value of 1×10^{k}, 2×10^{k} or 5×10^{k}, k bring the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(266)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 317.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रेसीजन इलैक्ट्रोनिक इन्स्ट्रूमेंट कम्पनी, 77, स्वर्ण पार्क, मुंडका, नई दिल्ली-110041 द्वारा विनिर्मित मध्यम यर्थाथता वर्ग (यर्थाथता वर्ग III) वाले "जी टी ई टी" शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबलटाप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "गोल्डटेक" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/143 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित (टेबलटाप प्रकार का) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्राम तक "ई" मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मान अन्तराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k} के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(337)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 317.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "GTET" series of medium accuracy (accuracy class-III) and with brand name "Goldtech" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s Precision Electronic Instruments Company, 77, Swaran Park, Mundaka, New Delhi-110041 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/143.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30kg and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100mg to 2g or with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, where k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(337)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 318.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स प्रेसीजन इलैक्ट्रोनिक इन्स्ट्रूमेंट कम्पनी, 77, स्वर्ण पार्क, मुंडका, नई दिल्ली-110041 द्वारा विनिर्मित मध्य यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग III) वाले "जी टी ई पी" शृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "गोल्डटेक" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/144 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

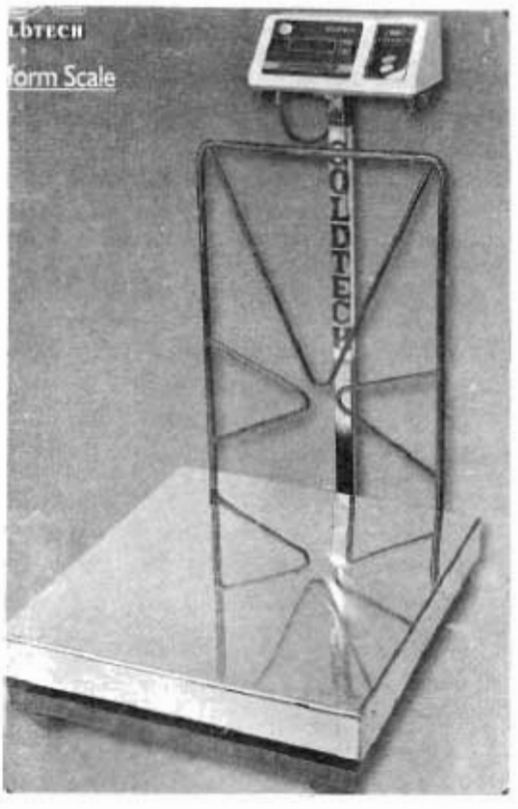

उक्त मॉडल एक विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित (प्लेटफार्म प्रकार का) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 2000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 500 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. से अधिक और 5000 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं० डब्ल्यू एम-21(337)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 318.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic (Platform type) weighing instrument with digital indication of "GTEP" series of medium accuracy (accuracy class-III) and with brand name "GOLDTECH" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s Precision Electronic Instruments Company, 77, Swaran Park, Mundaka, New Delhi-110041 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/144.

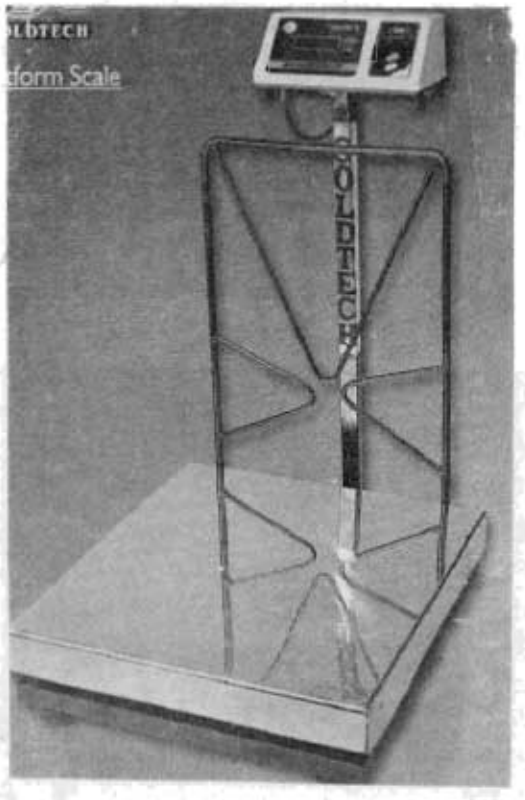

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 2000kg and minimum capacity of 10kg. The verification scale interval (e) is 500g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg and upto 5000kg with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g or more and with 'e' value of 1×10^{k}, 2×10^{k} or 5×10^{k}, where k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(337)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 319.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कुणाल इन्टरप्राइजिज, बी-3, निसर्ग श्रुष्ठी आपार्टमेंट, एस. नं. 29, निखिल मार्बल के सामने, कोंधवा रोड, कटराज, पुणे-46 (महाराष्ट्र) द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-II) वाले "टी टी एच" श्रृंखला के स्वतः सूचक, अस्वचालित, अंकक सूचन सहित (टेबल टॉप प्रकार) का तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "इलाईट" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/104 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप प्रकार का) है। इसकी अधिकतम क्षमता 22 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 2 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

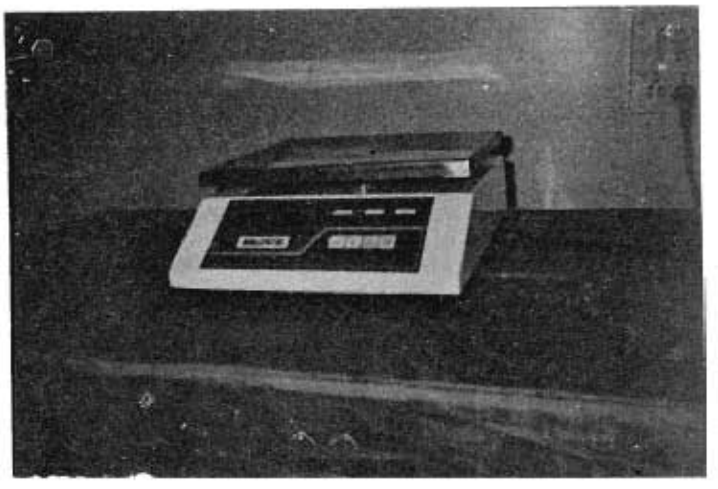

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील की जाएगी।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि. ग्रा. से 50 मि . ग्रा. तक के "ई" मान के लिए 100 से 50,000 तक की रेंज में, सत्यापन मापमान अन्तराल (एन) और 100 मि. ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 50000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(327)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 319.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of self-indicating, non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "TTH" series of high accuracy (Accuracy class-II) and with brand name "ELITE" (herein after referred to as the said model), manufactured by M/s Kunal Enterprises, B-3, Nisarg Srushti Apartment, S. No. 29, Opp. Nikhil Marbles, Kondhwa Road, Katraj, Pune-46 (Maharashtra) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/104.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 22 kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 2g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230Volts, 50Hz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with maximum capacity upto 50kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 100 to 50,000 for 'e' value of 1mg to 50mg and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100mg or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(327)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 320.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कुणाल इन्टरप्राइजिज, बी-3, निसर्ग श्रुष्ठी अपार्टमेंट, एस. नं. 29, निखिल मार्बल के सामने, कोंधवा रोड, कटराज, पुणे-46 (महाराष्ट्र) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता वर्ग (यथार्थता वर्ग-III) वाले "टी टी" श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित (टेबल टॉप प्रकार) का तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "इलाईट" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/105 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (टेबल टॉप प्रकार का) है। इसकी अधिकतम क्षमता 20 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

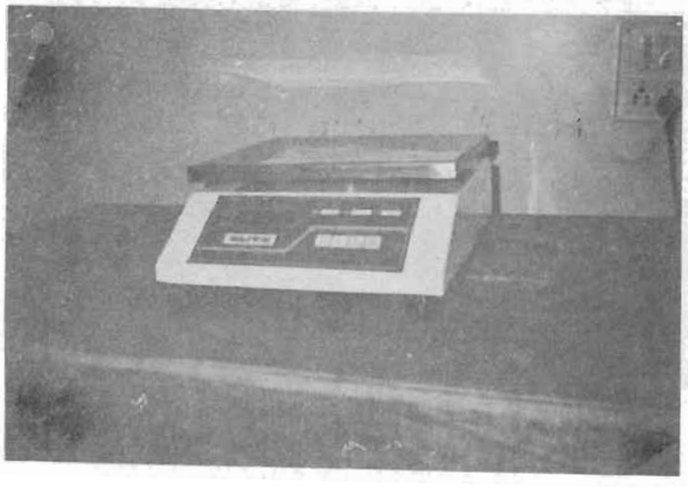

स्टाम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील की जाएगी।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक के "ई" मान के लिए 100 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अन्तराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अन्तराल सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^k, 2×10^k या 5×10^k, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(327)/2002]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 320.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of non-automatic (Table top type) weighing instrument with digital indication of "TT" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "ELITE" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s Kunal Enterprises, B-3, Nisarg Srushti Apartment, S. No. 29, Opp. Nikhil Marbles, Kondhwa Road, Katraj, Pune-46 (Maharashtra) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/105.

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 20kg. and minimum capacity of 100g. The verification scale interval (e) is 5g. It has a tare device with 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V, 50Hz alternative current power supply.

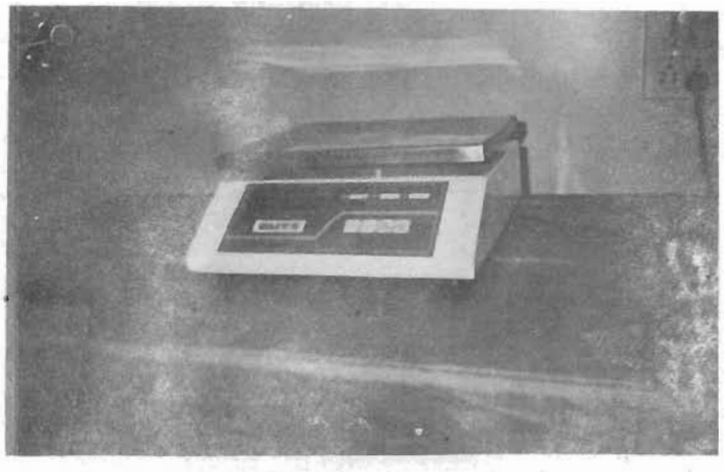

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity upto 50kg. and with verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100mg. to 2g. or with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of 1×10^{k}, 2×10^{k} or 5×10^{k}, k being a positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the said approved model have been manufactured.

[F. No. WM-21(327)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का०आ० 321.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स कुणाल इन्टरप्राइजिज, बी-3, निसर्ग श्रुष्ठी अपार्टमेंट, एस. नं. 29, विखिल मार्बल के सामने, कोंधवा रोड, कटराज, पुणे-46 (महाराष्ट्र), द्वारा विनिर्मित मध्य यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले ''पी एम'' श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित (प्लेटफार्म प्रकार) का तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''ईलाईट'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/106 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल विकृति गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) है। इसकी अधिकतम क्षमता 500 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 100 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है।

स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील की जाएगी।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 1000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(327)/2002]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 321.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic (Platform type) weighing instrument with digital indication of "PM" series of medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "ELITE" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Kunal Enterprises, B-3, Nisarg Srushti Apartment, S. No. 29, Opp. Nikhil Marbles, Kondhwa Road, Katraj, Pune-46 (Maharashtra) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/106;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 500 kg. and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50 kg. and up to 1000 kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5 g. or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, k is being positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(327)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का०आ० 322.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कुणाल इन्टरप्राइजिज, बी-3, निसर्ग श्रुष्टी अपार्टमेंट, एस. नं. 29, निखिल मार्बल के सामने, कोंधवा रोड, कटराज, पुणे-46 (महाराष्ट्र) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले "पी एम सी" शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित (प्लेटफार्म स्केल के लिए कंवर्जन किट प्रकार) का तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "इलाईट" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/107 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है;

उक्त मॉडल एक तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 300 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) मान 100 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है।

स्टापिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील की जाएगी।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि ग्रा. से 2 ग्रा. तक "ई" मान के लिए 100 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) और 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 1000 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(327)/2002]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 322.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of Model of non-automatic weighing instrument(Conversion kit for Platform Scale) with "PMC" series belonging to medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "ELITE" (hereinafter referred to as the said Model), manufactured by M/s. Kunal Enterprises, B-3, Nisarg Srushti Apartment, S. No. 29, Opp. Nikhil Marbles, Kondhwa Road, Katraj, Pune-46 (Maharashtra) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/107;

The said model is a weighing instrument with a maximum capacity of 300kg. and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the power conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with maximum capacity above 50kg. and up to 1000kg. and with number of verification scale interval (n) in the range of 100 to 10,000 for 'e' value of 100 mg. to 2g. and with number of verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5 g. or more and with 'e' value of 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(327)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का०आ० 323.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कुणाल इन्टर प्राइजिज, बी-3, निसर्ग श्रुष्टी अपार्टमेंट, एस नं. 29, निखिल मार्बल्स के सामने, कोंधवा रोड, कटराज पुणे-46 (महाराष्ट्र) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले ''डब्ल्यू बी'' शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (तोल सेतु प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''इलाईट'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/108 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 30,000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 200 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (इ) का मान 10 कि.ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है। इसका लोडसेल विकृति गेज प्रकार का है।

स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील की जाएगी।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 कि.ग्रा. या उससे अधिक के ''इ'' मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 5 टन से अधिक और 50 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''इ'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मकया ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(327)/2002]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 323.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of, non-automatic weighing instrument (weighbridge type) with digital indication belonging to medium accuracy (Accuracy class-III) of "WB" series with brand name "ELITE" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Kunal Enterprises, B-3, Nisarg Srushti Apartment, S. No. 29, Opp. Nikhil Marbles, Kondhwa Road, Katraj, Pune-46 (Maharashtra) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/108;

The said model is a non-automatic weighing instrument (weighbridge) with a maximum capacity of 30,000kg. and minimum capacity of 200kg. The verification scale interval (e) is 10kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts and 50 Hertz alternative current power supply. The load cell is of strain gauge type.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 5 tonne and up to 50 tonne with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5kg. or more and with 'e' value of 1×10^{k}, 2×10^{k} or 5×10^{k}, k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(327)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का०आ० 324.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कुणाल इन्टर प्राइजिज, बी-3, निसर्ग श्रुष्टी अपार्टमेंट, एस नं० 29, निखिल मार्वल के सामने, कोंधवा रोड, कटराज पुणे-46 (महाराष्ट्र) द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले ''डब्ल्यू बी सी'' श्रृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण (तोल सेतु हाईब्रीड के लिए कंवर्जन किट प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''इलाईट'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/109 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 25,000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 200 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 10 कि. ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत-प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है। इसका लोडसेल विकृति गेज प्रकार का है।

स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए भी सील की जाएगी।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 कि.ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' मान के लिए 500 से 10,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान (एन) अंतराल सहित 5 टन. से अधिक और 50 टन तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(327)/2002]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 324.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the **model described in the said** report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of, non-automatic weighing instrument (conversion kit for weighbridge-Hybrid type) with digital indication belonging to medium accuracy (Accuracy class-III) of "WBC" series with brand name "ELITE" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Kunal Enterprises, B-3, Nisarg Srushti Apartment, S. No. 29, Opp. Nikhil Marbles, Kondhwa Road, Katraj, Pune-46 (Maharashtra) and which is assigned the approval mark IND/09/2004/109;

The said model is a non-automatic weighing instrument (conversion kit for weighbridge-Hybrid type) with a maximum capacity of 25,000kg. and minimum capacity of 200kg. The verification scale interval (e) is 10kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternate current power supply. The load cell is of strain gauge type.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the power conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50tonne and upto 50 tonne with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of 1×10^{k}, 2×10^{k} or 5×10^{k}, k being the positive or negative whole number or equal to zero manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(327)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का०आ० 325.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अदितसन टेक्नोलोजिकल प्रोडक्ट्स, 102, साऊथ एक्स, प्लाजा-II, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली-110048 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-II) वाले ''बी एच'' श्रृंखला के अंकक सूचन सहित, अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''एक्सेल'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/118 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित अस्वचालित (प्लेटफार्म प्रकार का) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 110 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 500 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 10 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टॉपिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि.ग्रा. या उससे अधिक के ''ई'' मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से 300 कि.ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और ''ई'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(274)/2001]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 325.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of "BH" series of high accuracy (accuracy class-II) and with brand name "EXCELL" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Aditsan Technological Products, 102, South Ext., Plaza-II, Masjid Moth, New Delhi-110 048, and which is assigned the approval mark IND/09/2004/118;

The said model is strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 110kg and minimum capacity of 500 g. The verification scale interval (e) is 10g. It has a tare device with a 100 percent subtrative retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz alternate current power supply;

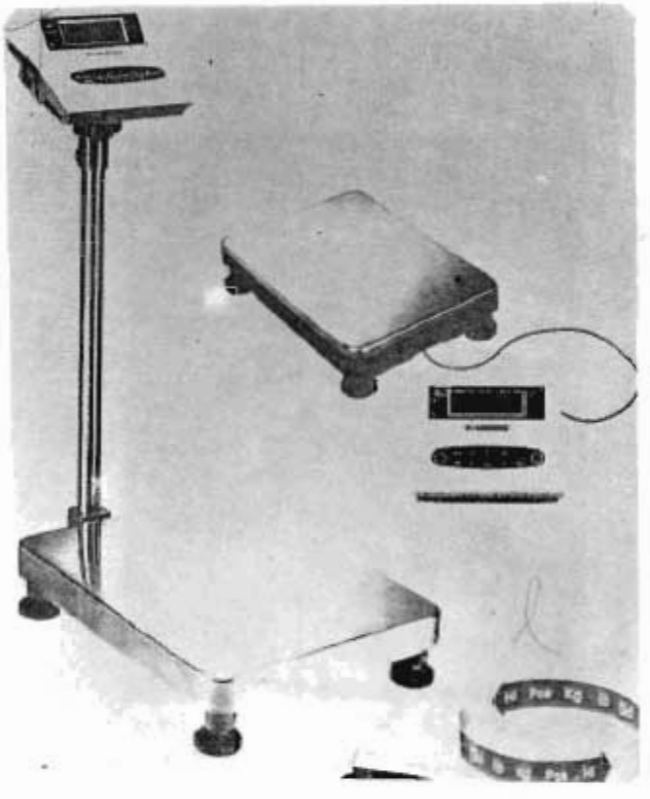

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government herby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with maximum capacity ranging above 50kg to 300kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 100mg or more and with 'e' value of 1×10^{k}, 2×10^{k} or 5×10^{k}, k being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(274)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का०आ० 326.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अलेक्जेंडर स्केल कम्पनी, 1151/1, पनकोरेनका, अहमदाबाद-380001, गुजरात द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग-II) वाले "ए एस पी-150" शृंखला के अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म के लिये कन्वर्शन किट प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "एस को" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/79 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का लोड सेल आधारित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 150 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 500 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (ई) का मान 10 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टॉपिंग प्लेट के मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।

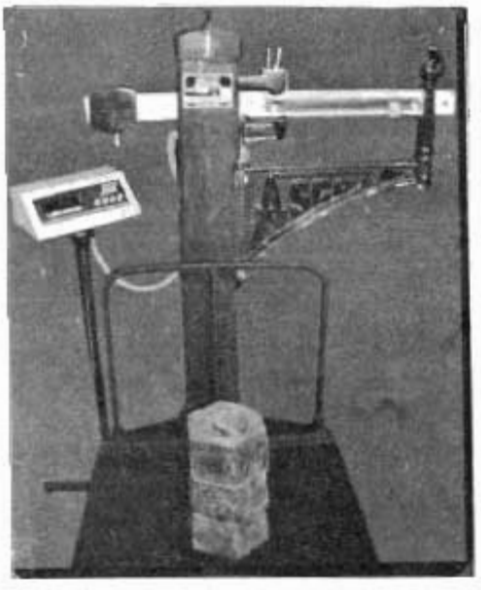

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 5000 से 50,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल सहित 50 कि.ग्रा. से अधिक और 300 कि.ग्रा. अधिकतम क्षमता वाले हैं और "ई" मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, क है, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(331)/2001]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 326.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model non-automatic (Platform Hybrid Conversion kit type) weighing instrument with digital indication of "ASP-150" series of high accuracy (accuracy class-II) and with brand name "ASCO" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Alexandra Scale Co., 1151/1, Pankorenaka, Ahmedabad-380 001, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/79;

The said model (see the figure given below) is strain gauge type load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 150 kg and minimum capacity of 500 g. The verification scale interval (e) is 10g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz alternate current power supply;

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

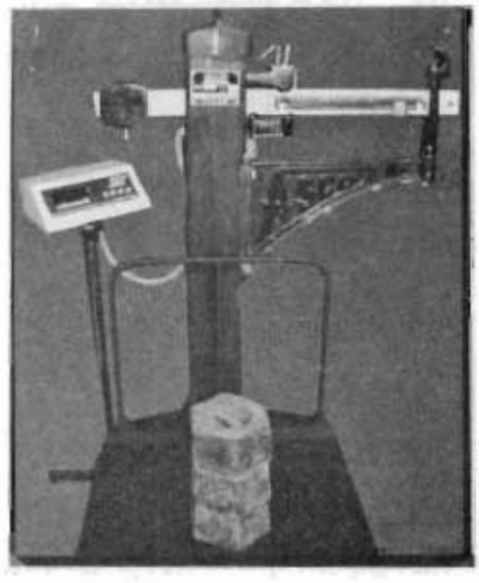

Further, in exercise of the power conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government herby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make and performance of same series with maximum capacity ranging above 50kg to 300 kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 50,000 for 'e' value of 1g or more and with 'e' value of 1×10^{k}, 2×10^{k} or 5×10^{k}, k being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(331)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का०आ० 327.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स अलेक्जेंडर स्केल कम्पनी, 1151/1, पनकोरेनका, अहमदाबाद-380001, गुजरात द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले ''ए एस पी-1 टी'' श्रृंखला के अस्वचालित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म के लिये कंवर्जन किट) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम ''एस को'' है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/80 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 4 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल (इ) का मान 200 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टापिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोलने से रोकने के लिए सीलबन्द भी किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 1 मि.ग्रा. से 50 मि.ग्रा. तक ''इ'' मान के लिए 100 से 1,00,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल (एन) और 1 ग्रा. या उससे अधिक के ''इ'' मान के लिए 5000 से 100,000 तक की रेंज में सत्यापन मान अंतराल सहित 5000 कि.ग्रा. तक अधिकतम क्षमता वाले है और ''इ'' मान 1×10^{k}, 2×10^{k} या 5×10^{k}, के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(331)/2001]

पी० ए० कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 327.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below), is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of non-automatic weighing instrument (Conversion kit for Platform) with "ASP-1T" series belonging to medium accuracy (Accuracy class-III) and with brand name "ASCO" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Alexandra Scale Co., 1151/1, Pankorenaka, Ahmedabad-380 001, Gujarat and which is assigned the approval mark IND/09/2004/80.

The said model (see the figure given below) is a weighing instrument with a maximum capacity of 1000 kg and minimum capacity of 4 kg. The verification scale interval (e) is 200g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz alternate current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with maximum capacity up to 5000kg and with number of verification scale interval (n) in the range of 100 to 1,00,000 for 'e' value of 1mg to 50mg and with number of verification scale interval (n) in the range of 5000 to 100,000 for 'e' value of 1g or more and with 'e' value 1×10^k, 2×10^k or 5×10^k, k being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(331)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का०आ० 328.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स क्वासको इंडस्ट्रीज, वडकल (गांव), एन आई टी, फरीदाबाद 121001 हरियाणा द्वारा विनिर्मित 'ऑगर' श्रृंखला के स्वतः सूचक, स्वचालित भरण मशीन (ओगर फिलर प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "क्वास्को" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/116 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक स्वचालित भरण मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 500 ग्रा. है। इसका उपयोग दूध, पाउडर, मसाले, काफी पाउडर, चाय पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, नमकवार, मेंहदी पाउडर इत्यादि जैसे मुक्त बहाव वाले उत्पादों को भरने के लिए किया जाता है। यह 15-50 पाउच प्रति मिनट करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है।

स्टैम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन को खोले जाने को रोकने के लिए भी सील की जाएगी।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है से विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी क्षमता 50 ग्रा. से 1000 ग्रा. तक की रेंज में है।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(279)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 328.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of self indicating, Automatic Filling Machine (Auger Filler) of "Q Auger" series with brand name "QASCO" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s Qasco Industries, Badkal (Village) N.I.T. Faridabad—121 001, Haryana and which is assigned the approval mark IND/09/2004/116;

The said model is an automatic filling machine (Auger Filler) with a maximum capacity of 500g. It is used for filling the free flowing products like milk powder, spices, coffee powder, tea powder, detergent powder, snuff, mehandi powder etc. It fills 15-50 pouches per minutes. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further in exercise of the the powers conferred by Sub-section (12) of the Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with capacity in the range of 50g to 1000g, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design, accuracy and with the same materials with which the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(279)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का.आ. 329.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स क्वासको इंडस्ट्रीज, बडकल (गांव), एन आई टी, फरीदाबाद 121001 हरियाणा द्वारा विनिर्मित "क्यूकप" श्रृंखला के स्वतः सूचक, स्वचालित भरण मशीन (कप फिलर प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "क्वास्को" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/617 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक स्वचालित भरण मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 500 ग्रा. है। इसका उपयोग दूध, पाउडर, मसाले, काफी पाउडर, चाय पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, तम्बाकू, गुटका, मेंहदी पाउडर इत्यादि जैसे मुक्त बहाव वाले उत्पादों को भरने के लिए किया जाता है। यह 15-50 पाउच प्रति मिनट करती है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर कार्य करता है।

स्टैम्पिंग प्लेट को मुद्रांकित करने के अतिरिक्त, कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन खोले जाने को रोकने के लिए भी सील की जाएगी।

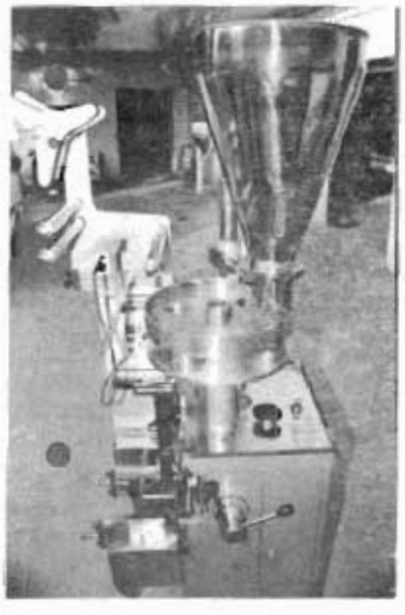

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है से विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी क्षमता 1 ग्रा. से 1000 ग्रा. तक की रेंज में है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(279)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 329.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (See the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of self indicating, Automatic Filling Machine (Cup Filler) of "QCUP " series with brand name "QASCO" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s Qasco Industries, Badkal (Village) N.I.T. Faridabad—121 001, Haryana and which is assigned the approval mark IND/09/2004/617;

The said model (see the figure given below) is an automatic filling machine (Cup Filler) with a maximum capacity of 500g. It is used for filling the free flowing products like milk powder, spices, coffee powder, tea powder, detergent powder, snuff, tobacco, gutakha, mehadi powder etc. It fills 15-50 pouches per minutes. The instrument operates on 230 Volts, 50 Hertz alternate current power supply.

In addition to sealing stamping plate, sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices.

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section, 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make and performance of same series with capacity in the range of 1g to 1000g, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design, accuracy and with the same materials with which, the said approved model have been manufactured.

[F. No. WM-21(279)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का.आ. 330.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एन एस एल फेब्रिकेटर्स, प्लाट सं. 206/6, फेज-II, आई डी ए चेरापल्ली, हैदराबाद-500051 द्वारा विनिर्मित "एन एस एल-एस बी" श्रृंखला के भरण मशीन (अनुमापी प्ररूप की भरण और सील मशीन प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "सन-बीम" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/110 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल एक स्वचालित भरण मशीन (अनुमापी प्ररूप की भरण और सील मशीन) है। इसकी अधिकतम क्षमता 1000 ग्रा. या समतुल्य आयतन की है। इसकी अधिकतम भरण दर 15-35 पैक प्रति मिनट है। मशीन को मिनरल वाटर, दुग्ध, बेवरीज, जूस इत्यादि जैसे मुक्त बहाव वाले अविस्कस द्रव उत्पादों के लिए डिजाइन किया गया है।

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है विनिर्मित उसी श्रृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन की भरण मशीन भी होंगी जो 2 ग्रा. से 1000 ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता की रेंज में हैं।

[फा.सं० डब्ल्यू एम-21(08)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 330.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (See the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of filling machine (Volumetric form fill and seal machine) of "NSL-SB" series with brand name "SUN-BEAM" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s NSL Febricators, Plot No. 206/6, Phase-II, IDA Cherapally, Hyderabad-500 051 and which is assigned the approval mark IND/09/2004/110;

The said model is an automatic filling machine (Volumetric form fill and seal machine type). Its maximum capacity is 1000g or equivalent volume. It has a maximum fill rate of 15-35 packs per minute. The machine is designed for filling free flowing non-viscous liquid products like mineral water, milk, beverage, juice, etc.

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the automatic filling machine of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 2g to 1000g, equivalent volume manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(08)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का.आ. 331.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सोहन एण्ड संस, 1211/3, स्कीम नं. 7, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश द्वारा विनिर्मित काउण्टर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्राण्ड का नाम "सोहन" है (जिसे इसमें इसको उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2004/208 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी और प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक काउण्टर मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है।

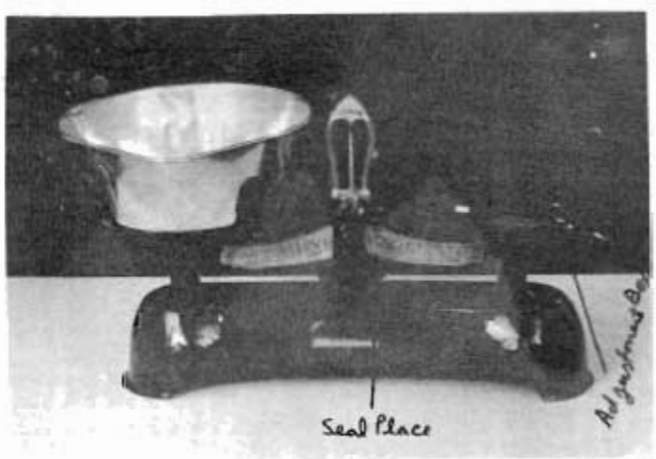

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित मॉडल विनिर्मित किया गया है। विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के काउण्टर मशीन भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि.ग्रा. तक की रेंज की अधिकतम क्षमता वाले हैं।

[फा.सं० डब्ल्यूएम-21(97)/2004]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 331.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of counter machine (herein referred to as the said Model), with brand name 'SOHAN' manufactured by M/s Sohan & Sons, 1211/3, Scheme No. 7, Shastri Nagar, Meerut, Uttar Pradesh and which is assigned the approval mark IND/09/2004/208;

The said model (see the figure given below) is a counter machine with maximum capacity of 10 kg.

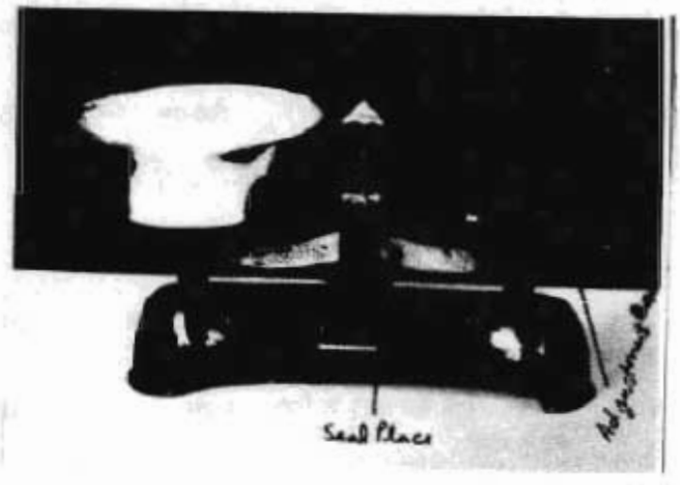

Further in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the counter machine of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500g to 50 kg. manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the said approved model have been manufactured

[F. No. WM-21(97)/2004]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

176 GI/05-6

(भारतीय मानक ब्यूरो)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2005

का.आ. 332.— भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 6 के उपविनियम (3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा नीचे अनुसूची में दिए गये उत्पादों की मुहरांकन शुल्क अधिसूचित करता है :—

अनुसूची

भारतीय मानक सं.	भाग	अनु.	वर्ष	उत्पाद	इकाई	न्यूनतम मुहरांकन शुल्क बड़े पैमाने पर	छोटे पैमाने पर	इकाई दर	प्रचालन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8151	0	0	1976	ड्राइविंग लिफ्टों के लिए एकल गति तीन फेजीय प्रेरण मोटरें	1 अदद	42000	35000	5	20020724
2641	0	0	1989	इलैक्ट्रोड होल्डर (इलैक्ट्रिक वेल्डिंग में सहायक सामग्री)	1 अदद होल्डर या क्लेम्प	31000	25000	0.6	20020819
3055	2	0	2002	चिकित्सा में प्रयुक्त थर्मामीटर : भाग 2 बन्द स्केलनुमा	1 थर्मामीटर	31000	25000	0.4	20020819
14724	0	0	1999	जल परिशोधक यंत्र-पराबैंगनी रोगाणुनाशक सहित	1 अदद	39000	32000	8	20020819
14927	2	0	2001	विद्युत संस्थापन के लिए केबल तनाव और वाहिनी पद्धति भाग 2 केबल तनाव एवं वाहिनी पद्धति-दीवारों पर या सीलिंग पर लगाने के लिए वांछित	100 एम	42000	35000	1.75	20020819
1030	0	0	1998	सामान्य इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए कार्बन इस्पात ढलाइयाँ	1 मीटरी टन	33000	26000	30	20020823
15138	0	0	2002	50 किग्रा चीनी पैक करने के लिए जूट के बोरे	1 टन	36000	29000	15	20020823
2708	0	0	1993	सामान्य इंजीनियरी प्रयोजनों के लिए 1.5% मैंगनीज इस्पात ढलाइयाँ	1 मीटरी टन	30000	24000	30	20020824
1470	0	0	1990	सिलिको मैंगनीज	1 मीटरी टन	39000	32000	5	20020831
13071	0	0	1991	बालू तथा रोड़ी चूषण डिस्चार्ज के लिए रबड़ हौज, तार प्रबलित	100 मीटर	36000	29000	40	20020927
14862	0	0	2000	फाइबर सीमेंट की सपाट चद्दरें	1 मीटरी टन	33000	26000	1.45	20021016
1862	0	0	1975	स्टड्स	1 मीटरी टन	36000	29000	100	20021021
14953	0	0	2001	वस्त्रादि-पोलिएस्टर अथवा पोलिएमाइड की मच्छरदानियाँ	1 मच्छरदानी	36000	29000	0.7	20021108
2269	0	0	1995	फास्टनर्स - षटकोणी सॉकेट शीर्ष टोपी वाले पेंच	1 मीटरी टन	45000	38000	21.6	20021112
11737	0	0	1996	औद्योगिक थैले सिलने की मशीन	एक मशीन	39000	32000	7	20021113
3802	0	0	1992	भुना हुआ कॉफी चिकोरी पाउडर	1000 कि.ग्रा.	30000	24000	100	20021114
10276	3	0	1982	एडीसन स्क्रू लैम्प होल्डर	100 अदद	36000	29000	2	20021115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13183	0	0	1991	एल्युमीनियम रंग रोगन ताप. प्रतिरोधी	1 लिटर/किग्रा.	45000	38000	0.22	20021125
14933	0	0	2001	उच्च दाब अग्नि शामक हौज	1 मीटरी	55000	47000	1.5	20021209
5137	0	0	1990	सीमेंट ग्राउटिंग के लिए रबड़ के हौज	100 मीटरी	55000	47000	21.6	20021210
13429	1	0	2000	सोलर कुकर बॉक्स टाइप	1 कुकर	27000	20000	5	20021211
13340	0	0	1993	650 वो तक रेटित वोल्टता वाले एसी पॉवर सिस्टम के लिए स्वत: हीलिंग टाइप पॉवर संधारित्र	1 केवीएआर [आईएस 13585(1) और 13925(1) के उत्पाद सहित]	42000	35000	0.75	20020401
13585	1	0	1994	ए सी विद्युत तंत्रों के लिए स्वत: धारिता पुर्नप्राप्त न करने वाले 650 वोल्ट की रेटित वोल्टता के शंट संधारित्र भाग 1 विशिष्टि	1 केवीएआर [आईएस 13340 और 13925(1) के उत्पाद सहित]	42000	35000	0.75	20020401
13925	1	0	1998	1000 वो. वोल्टता से अधिक रेटित वोल्टेज वाले ए.सी. पावर प्रणाली के लिए शंट संधारित्र भाग 1 सामान्य कार्यकारिता, परीक्षण और रेटिंग सुरक्षा अपेक्षाएं- संस्थापन और प्रचालन के लिए मार्गदर्शिका	1 केवीएआर [आईएस 13585(1) और 13340 के उत्पाद सहित]	42000	35000	0.75	20020401
14101	0	1	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक ढलवां लोहा (सेक्शन 4) (सभी 4 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद	24000	17000	8.65	20020401
14101	0	2	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक ढलवां लोहा (सेक्शन 4) (सभी 4 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			11.55	20020401
14101	0	3	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक ढलवां लोहा (सेक्शन 4) (सभी 4 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			14.4	20020401
14101	0	4	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक ढलवां लोहा (सेक्शन 4) (सभी 4 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			36	20020401
14102	0	1	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 4 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद	29000	22000	7.2	20020401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14102	0	2	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			2.9	20020401
14102	0	3	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			2.9	20020401
14102	0	4	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			5.8	20020401
14102	0	5	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			5.8	20020401
14102	0	6	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			17.3	20020401
14102	0	7	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			5.8	20020401
14102	0	8	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			4.35	20020401
14102	0	9	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			8.65	20020401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14102	0	10	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			13	20020401
14102	0	11	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			11.55	20020401
14102	0	12	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			2.2	20020401
14102	0	13	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक सीसायुक्त टिन काँसा (13 सेक्शन) (सभी 13 सेक्शनों के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुल्क)	100 अदद			14.4	20020401
14103	0	0	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (18 सेक्शन), यह न्यूनतम मुहरांकन शुल्क एक उप-समूह से अधिक में कवर किये गये लाइसेंसों पर लागू होता है (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	देखें अलग-अलग खंड सभी खंडों का इकट्ठा उत्पादन	49000	41000	—	20020401
14103	0	1	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (1, 5, 17 और 18 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद	24000	17000	8.65	20020401
14103	0	2	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (2, 4, 6 और 15 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद	29000	22000	93.6	20020401
14103	0	3	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (3, 7, 8, 9 और 16 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद	24000	17000	93.6	20020401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14103	0	4	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (2, 4, 6 और 15 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			8.65	20020401
14103	0	5	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (1, 5, 17 और 18 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			11.55	20020401
14103	0	6	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (2, 4, 6 और 15 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			28.8	20020401
14103	0	7	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (3, 7, 8, 9 और 16 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			34.6	20020401
14103	0	8	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (3, 7, 8, 9 और 16 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			10.1	20020401
14103	0	9	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (3, 7, 8, 9 और 16 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			21.6	20020401
14103	0	10	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (10 सेक्शन के लिए)	100 अदद	24000	17000	11.55	20020401
14103	0	11	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (11, 12, 13, 14 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद	24000	17000	3.6	20020401
14103	0	12	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (11, 12, 13, 14 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			6.5	20020401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14103	0	13	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (11, 12, 13, 14 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			57.6	20020401
14103	0	14	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (11, 12, 13, 14 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			57.6	20020401
14103	0	15	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (2, 4, 6, और 15 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			100.8	20020401
14103	0	16	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (3, 7, 8, 9 और 16 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			100.8	20020401
4103	0	17	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (1, 5, 17 और 18 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			1.45	20020401
4103	0	18	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक मृदु इस्पात (1, 5, 17 और 18 सेक्शन के लिए) (इकाई दर के लिए अलग सेक्शन का रिकार्ड देखें)	100 अदद			5.8	20020401
4104	0	1	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन) (सभी 7 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	1000 अदद	24000	17000	1.45	20020401
4104	0	2	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन) (सभी 7 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	1000 अदद			2.9	20020401
4104	0	3	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन) (सभी 7 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	1000 अदद			2.9	20020401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14104	0	4	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन) (सभी 7 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	1000 अदद			5.8	20020401
14104	0	5	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन) (सभी 7 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	1000 अदद			8.65	20020401
14104	0	6	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन) (सभी 7 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	1000 अदद			5.8	20020401
14104	0	7	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे घटक नाइट्रिल रबड़ (7 सेक्शन) (सभी 7 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	1000 अदद			4.35	20020401
14105	0	1	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे अवयव स्टेनलेस स्टील (5 सेक्शन) (सभी 5 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	100 अदद	29000	22000	86.4	20020401
14105	0	2	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे अवयव स्टेनलेस स्टील (5 सेक्शन) (सभी 5 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	100 अदद			13	20020401
14105	0	3	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे अवयव स्टेनलेस स्टील (5 सेक्शन) (सभी 5 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	100 अदद			15.85	20020401
14105	0	4	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे अवयव स्टेनलेस स्टील (5 सेक्शन) (सभी 5 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	100 अदद			17.3	20020401
14105	0	5	1994	गहराई से पानी निकालने के हथ-बरमे अवयव स्टेनलेस स्टील (5 सेक्शन) (सभी 5 सेक्शन के लिए न्यूनतम मुहरांन शुल्क)	100 अदद			1.45	20020401
14106	0	0	1994	सीधा कार्य करने वाले हथबरमे	1 हथबरमा	42000	35000	7.2	20020401

[सं. सीएमडी-4 /13 : 10]

बलवंत राय, उप महानिदेशक (मुहर)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 13th January, 2005

S. O. 332.—In pursuance of sub-regulation (3) of regulation 6 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the Marking fee for the products given in the schedule :

SCHEDULE

IS. No.	PT.	Sec.	Year	Product	Unit	Min. Marking Fee		Unit Rate	Enforcement Date
						Large Scale	Small Scale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8151			1976	Single Speed Three Phase Induction Motors for Driving Lifts	1 Piece	42000	35000	5	20020724
2641	0	0	1989	Electric Welding Accessories	1 Piece of Holder or Clamp	31000	25000	0.6	20020819
3055	2	0	2002	Clinical Thermometers: Part 2 Enclosed Scale Type	1 Thermometer	31000	25000	0.4	20020819
14724	0	0	1999	Water Purifiers Withy Ultra-Voilet Disinfection	1 Piece	39000	32000	8	20020819
14927	2	0	2001	Cable Trunking and Ducting systems for Electrical Installation : Part 2 Cable Trunking and Ducting Systems intended for Mounting on Walls or Ceiling	100 M.	42000	35000	1.75	20020819
1030	0	0	1998	Carbon Steel Castings for General Engineering purposes	1 MT	33000	26000	30	20020823
15138	0	0	2002	Jute bag for packing 50 kg Sugar	1 Tonne	36000	29000	15	20020823
2708	0	0	1993	1.5% Manganese Steel Castings for General Engineering purposes	1 MT.	30000	24000	30	20020824
1470	0	0	1990	Silico Manganese	1 MT.	39000	32000	5	20020831
13071	0	0	1991	Rubbor Hose, Wire Reinforced for Sand and Graval suction discharge services	100 Meter	36000	29000	40	20020927
14862	0	0	2000	Fibre Cement Flat Sheets	1 MT.	33000	26000	1.45	20021016
1862	0	0	1975	Studs	1 MT.	36000	29000	100	20021021
14953	0	0	2001	Textiles-Polymide Mosquito Nets	1 Mosquito Net	36000	29000	0.7	20021108
2269	0	0	1995	Fasterners-Hexagon Socket Head Cap Screw	1MT	45000	38000	21.6	20021112
11737	0	0	1996	Industrial Bag Stitching Machine	One Machine	39000	32000	7	20021113
3802	0	0	1992	Roasted Coffee Chicory Powder	1000 Kgs.	30000	24000	100	20021114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10276	1	0	1982	Edison Screw Lamp Holders	100 Pieces	36000	29000	2	20021115
13183	0	0	1991	Aluminium Paint, Heat Resistant	1 Liter/Kg.	45000	38000	0.22	20021125
14933	0	0	2001	High Pressure Fire Fighting Hose	1 Meter	55000	47000	1.5	20021209
5137	0	0	1990	Rubber Hose for Cement Crouting	100 Meter	55000	47000	21.6	20021210
13429	1	0	2000	Solar Cooker—Box Type	1 Cooker	27000	20000	5	20021211
13340	0	0	1993	Power Capacitors for the self-healing Type for AC Power Systems Having Rated Voltage up to 650V	1 KVAR Club Prod with IS 13585 (1) and 13925 (1)	42000	35000	0.75	20020401
13585	1	0	1994	Shunt Capacitors for Non-self Heating Type for AC Power Systems Having a Rated Voltage upto and Including 650V : Part 1 Specification	1 KVAR Club Prod with IS 13340 and 13925 (1)	42000	35000	0.75	20020401
13925	1	0	1998	Shunt Capacitors for AC Power Systems Having a Rated Voltage Above 1000V:PART 1 General Performance, Testing and Rating—safety Requirements-Guide for Installation and Operation Quirements—Guide for Installation and Operation	1 KVAR Club Prod with IS 13585 (1) and 13340	42000	35000	0.75	20020401
14101	0	1	1994	Deepwell Handpumps Components Cast Iron (4 Sections) Common MMFEE for All 4 Sections)	100 pieces	24000	17000	8.65	20020401
14101	0	2	1994	Deepwell Handpumps Components Cast Iron (4 sections) Common MMFEE for all 4 sections)	100 pieces			11.55	20020401
14101	0	3	1994	Deepwell Handpumps Components Cast Iron (4 Sections) Common MMFEE for All 4 Sections)	100 pieces			14.4	20020401
14101	0	4	1994	Deepwell Handpumps Components Cast Iron (4 sections) Common MMFEE for all 4 sections)	100 pieces			36	20020401
14102	0	1	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces	29000	22000	7.2	20020401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14102	0	2	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			2.9	20020401
14102	0	3	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			2.9	20020401
14102	0	4	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			5.8	20020401
14102	0	5	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			5.8	20020401
14102	0	6	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			17.3	20020401
14102	0	7	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			5.8	20020401
14102	0	8	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			4.35	20020401
14102	0	9	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			8.65	20020401
14102	0	10	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			13	20020401
14102	0	11	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			11.55	20020401
14102	0	12	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			2.2	20020401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14102	0	13	1994	Deepwell Handpumps Components Leaded Tin Bronze (13 Sections) (Common MMFEE for all 13 Sections)	100 pieces			14.4	20020401
14103	0	0	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (18 Sections). This MMF applies to licences covering more than 1 Sub Group. [For Unit rates See Individual Section's record]	See Indivdl. Sec. Club Prod of all Sections	49000	41000	–	20020401
14103	0	1	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 1,5,17 & 18 Section) [For Unit rates See Individual Section's record]	100 Pieces	24000	17000	8.65	20020401
14103	0	2	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 2,4,6 & 15 Sections) [For Unit rates See Individual Section's record]	100 Pieces	29000	22000	93.6	20020401
14103	0	3	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 3,7,8,9, 16 Sections) [For Unit rates See Individual Section's record]	100 Pieces	24000	17000	93.6	20020401
14103	0	4	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 2,4,6 & 15 Sections) [For Unit rates See Individual Section's record]	100 Pieces			8.65	20020401
14103	0	5	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 1,5,17 & 18 Section) [For Unit rates See Individual Section's record]	100 Pieces			11.55	20020401
14103	0	6	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 2,4,6 & 15 Sections) [For Unit rates See Individual Section's record]	100 Pieces			28.8	20020401
14103	0	7	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 3,7,8,9, 16 Sections) [For Unit rates See Individual Section's record]	100 Pieces			34.6	20020401
14103	0	8	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 3,7,8,9, 16 Sections) [For Unit rates See Individual Section's record]	100 Pieces			10.1	20020401
14103	0	9	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 3,7,8,9, 16 Sections) [For Unit rates See Individual Section's record]	100 Pieces			21.6	20020401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14103	0	10	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For Section 10)	100 Pieces	24000	17000	11.55	20020401
14103	0	11	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 11,12,13,14 Section) [For Unit Rates See Individual Section's record]	100 Pieces	24000	17000	3.6	20020401
14103	0	12	1994	Deepwell Handpumps Componensts Mild Steel (For 11,12,13,14 Sections) [For Unit Rates See Individual Section's record]	100 Pieces			6.5	20020401
14103	0	13	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 11,12,13,14 Sections) [For Unit Rates See Individual Section's record]	100 Pieces			57.6	20020401
14103	0	14	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 11,12,13,14 Sections) [For Unit Rates See Individual Section's record]	100 Pieces			57.6	20020401
14103	0	15	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 2,4,6 & 15 Sections) [For Unit Rates See Individual Section's record]	100 Pieces			100.8	20020401
14103	0	16	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 3,7,8,9, 16 Sections) [For Unit Rates See Individual Section's record]	100 Pieces			100.8	20020401
14103	0	17	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 1,5,17 & 18 Sections) [For Unit Rates See Individual Section's record]	1000 Pieces			1.45	20020401
14103	0	18	1994	Deepwell Handpumps Components Mild Steel (For 1,5,17 & 18 Sections) [For Unit Rates See Individual Section's record]	1000 Pieces			5.8	20020401
14104	0	1	1994	Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]	100 Pieces	24000	17000	1.45	20020401
14104	0	2	1994	Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]	1000 Pieces			2.9	20020401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14104	0	3	1994	Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]	1000 Pieces			2.9	20020401
14104	0	4	1994	Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]	1000 Pieces			5.8	20020401
14104	0	5	1994	Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]	1000 Pieces			8.65	20020401
14104	0	6	1994	Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]	1000 Pieces			5.8	20020401
14104	0	7	1994	Deepwell Handpumps Components Nitril Rubber (7 Sections) [Minimum Marking Fee for all 7 Sections]	1000 Pieces			4.35	20020401
14105	0	1	1994	Deepwell Handpumps Components Stainless Steel (5 Sections) [Minimum Marking Fee for all 5 Sections]	100 Pieces	29000	22000	86.4	20020401
14105	0	2	1994	Deepwell Handpumps Components Stainless Steel (5 Sections) [Minimum Marking Fee for all 5 Sections]	100 Pieces			13	20020401
14105	0	3	1994	Deepwell Handpumps Components Stainless Steel (5 Sections) [Minimum Marking Fee for all 5 Sections]	100 Pieces			15.85	20020401
14105	0	4	1994	Deepwell Handpumps Components Stainless Steel (5 Sections) [Minimum Marking Fee for all 5 Sections]	100 Pieces			17.3	20020401
14105	0	5	1994	Deepwell Handpumps Components Stainless Steel (5 Sections) [Minimum Marking Fee for all 5 Sections]	100 Pieces			1.45	20020401
14106	0	0	1996	Direct Action Handpumps	1 Pumps	42000	35000	7.2	20020401

[No. CMD-IV/13:10]

BALWANT RAI, Dy. Director General (Marks)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2005

का०आ० 333.—केन्द्रीय सरकार को, लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मध्यप्रदेश राज्य में मांगल्या (इंदौर) संस्थापन से हरियाणा राज्य में पियाला तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजवासन तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक विस्तार पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री वी. पी. पाठक, सक्षम प्राधिकारी, मुम्बई—मांगल्या पाइपलाइन विस्तार परियोजना, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, एम. बी.-7 महाश्वेता नगर, महेन्द्र भटनागर मार्ग, उज्जैन-456010 (मध्यप्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : तराना जिला : उज्जैन राज्य : मध्यप्रदेश

क्र.	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	2	3	4
1.	भेरूपुरा	2	0.4043
		3	0.3724
		19	0.1254
		20	0.1402
		21	0.1643
		22	0.4903
		76	0.4970
		78	0.0209
		77	0.2427
		91 (शा. भूमि)	0.0100
2.	शिवपुरा	1	0.2372
		3	0.1957
		4	0.2561
		5	0.2193
3.	बिंजल	22	0.3050
		23	0.0348
		20	0.1474
		19	0.2504
		15	0.0100
		24 (शा. रास्ता)	0.0269
		50	0.0825
		50/322	0.0535
		51 (शा. रास्ता)	0.0100
		52	0.0472
		57	0.1500
		59	0.0100
		58	0.0770
		56	0.1118
		125	0.2410
		144 (शा. रास्ता)	0.0721
		145 (शा. भूमि)	0.0514
		143	0.2874
		141	0.0767
		142	0.0137
		124	0.0107
		147	0.0105
		150	0.0109
		151	0.0105
		21	0.0108
4.	भूखी इतवारपुर	6	0.2310
		7	0.1347
		8	0.0900
		35 (शा. रास्ता)	0.0129
		36	0.0100
5.	काँवली खेडा	276 (शा. नाला)	0.0706
		282	0.0521
		281	0.0478
		280	0.0710
		283	0.0110
		284	0.1474
		285	0.0523
		290	0.0120
		551 (शा. भूमि)	0.0200
		552	0.0475
		554(शा. रास्ता)	0.0274
		555 (शा. भूमि)	0.0165
		562	0.0908
		563	0.3834
		572	0.2458
		573 (शा. भूमि)	0.0564

1	2	3	4
6.	भड़सिम्बा	436 (नदी)	0.0951
		298	0.0195
		299	0.1128
		300	0.1437
		311	0.1178
		312	0.1358
		314	0.0187
		315	0.1806
		318	0.1361
		317	0.0342
		378	0.1785
		377	0.0100
		270	0.0100
		379 (शा. रास्ता)	0.0310
		385	0.1234
		386 (शा. रास्ता)	0.0188
		387	0.0732
		388	0.1579
		389	0.1700
		399	0.1025
		400	0.0140
		307	0.0437
		517	0.3486
		737	0.3161
		736	0.1378
		735	0.2008
		601	0.0120
		734	0.0239
		602	0.3850
		606	0.2700
		605	0.1700
		608	0.0700
		613	0.4256
		612	0.1500
		615	0.0100
		651	0.1800
		618	0.0200
		648	0.2306
		661 (शा. नाला)	0.0538
		664	0.0546
		663	0.0434
		662	0.3969
		663	0.1371
		647	0.0310
		636 (शा. नाला)	0.0450
		609	0.0100
7.	गांवड़ी	17	0.1401
		16 (शा. नाला)	0.0184
		14	0.0183
		13	0.3599
		15	0.0486
		11	0.3680
		8	0.0116
		67	0.1804
		79 (शा. रास्ता)	0.0580
		103	0.7133
		104	0.0212
		109 (शा. भूमि)	0.1987
		108	0.2877
		107	0.0281
		111 (नदी)	0.1600
		81	0.0800
8.	नौगांवा	483	0.2891
		481	0.1119
		480	0.2201
		50	0.1403
		478	0.0735
		51	0.0290
		477(शा. नाला)	0.1022
		472 (शा. भूमि)	0.0436
		59	0.4409
		60	0.0350
		87 (शा. नाला)	0.0252
		391	0.0399
		394	0.1864
		393	0.2344
		377 (शा. रास्ता)	0.0490
		376	0.2152
		374	0.1547
		362	0.3273
		373	0.1361
		363	0.0297
		330	0.0154
		364	0.0356
		329	0.1257
		328	0.0102
		325	0.0270

1	2	3	4
	नौगांवा (जारी)	324	0.0372
		319	0.0811
		320	0.1440
		302	0.0451
		300	0.1887
		301	0.0428
		299 (शा. रास्ता)	0.0320
		286	0.0466
		283	0.0262
		285	0.0106
		284	0.1257
		241	0.0968
		240 (शा. नाला)	0.0181
		237	0.1357
		238	9.1189
		236	0.0352
		638	0.1524
		637	0.3685
		661 (शा. रास्ता)	0.0326
		659	0.2438
		658	0.0789
		671	0.0619
		676	0.0242
		672	0.1193
		675	0.1653
		676	0.0100
		676/708	0.2496
		685	0.1530
		684	0.0769
		688	0.0757
		689	0.2040
		693 (शा. भूमि)	0.0710
		358	0.0310
		355	0.0320
		361	0.0200
		322	0.0100
		58	0.0100
		372	0.0200
		331 (शा. रास्ता)	0.0360
9.	बिसनखेड़ी	108 (शा. भूमि)	0.0246
		112	0.1855
		123	0.1523
		124	0.0362
		125	0.1265
		126	0.0878
		127	0.1907
		291	0.1169
		303	0.2867
		308	0.3559
		309	0.0337
		311	0.2091
10.	बिसनखेड़ा	287 (शा. नाला)	0.0150
		288	0.0296
		280	0.1396
		281	0.1900
		279	0.1892
		274(शा. रास्ता)	0.0805
		200	0.2074
		256	0.0716
		255	0.2347
		260	0.0223
		259 (शा. रास्ता)	0.0151
		268	0.2448
10.	बिसनखेड़ा	312	0.020
		326	0.1900
		324	0.0249
		327	0.1289
		325	0.2669
		338	0.4348
		317 (शा. भूमि)	0.0332
		311	0.2000
		269	0.0800
11.	इटावा	2	0.0455
		1	0.3026
		5	0.1176
		6	0.2868
		7	0.1661
		9	0.1671
		19	0.1471
		20	0.1727

1	2	3	4
11.	इटावा (जारी)	21	0.1460
		22	0.1627
		40	0.0449
		41	0.1264
		42	0.0983
		43	0.1912
		57	0.2852
		58	0.0281
		61 (शा. रास्ता)	0.0176
		63	0.1200
		71	0.0634
		64	0.0398
		65	0.1199
		65/1229	0.0468
		70 (शा. रास्ता)	0.0497
		66	0.1757
		67	0.1807
		671	0.0885
		672	0.0997
		673	0.0639
		674	0.0680
		675	0.0756
		676	0.0733
		677	0.3701
		685 (शा. नाला)	0.0300
		3	0.0100
		68	0.0500
12.	खांकरी सुल्तान	213	0.0186
		218	0.3252
		220 (शा. भूमि)	0.0127
13.	लोध	57	0.0280
		58	0.4219
		62	0.2759
		65	0.1308
		66	0.1018
		67	0.0508
		68	0.0449
		69	0.514
		70	0.0539
		72	0.2942
		205 (शा. रास्ता)	0.0193

1	2	3	4
13.	लोध (जारी)	274	0.0655
		270	0.0834
		275	0.2893
		276	0.1446
		368	0.1945
		367	0.0535
		366	0.0521
		364	0.0517
		365	0.1404
		376	0.2035
		377	0.1214
		352 (शा. भूमि)	0.0188
		649	0.0133
		648 (शा. भूमि)	0.3554
		647 (शा. नाला)	0.0259
		705	0.0259
		645	0.1343
		644	0.0885
		643	0.0225
		642	0.0182
		639	0.0879
		640	0.0231
		638	0.1209
		713	0.0222
		629	0.1212
		628	0.1005
		627	0.0876
		626	0.0712
		773/882	0.1838
		774	0.0726
		775	0.3296
		624	0.0117
		623	0.1426
		622	0.1051
		621	0.0115
		614	0.1928
		613	0.1109
		612	0.1486
		611 (शा. भूमि)	0.0364
		835	0.0100
		277	0.0300

1	2	3	4
14.	नांदेड	966 (शा. भूमि)	0.0985
		995	0.0670
		1003	0.1625
		1002	0.0105
		1006	0.3462
		1005	0.0633
		1045	0.2835
		1043	0.2908
		1040	0.1800
		1062	0.1248
		1041	0.0139
		1061	0.0275
		1063	0.1174
		1080	0.1825
		1079	0.1562
		1083	0.0476
		1078	0.0250
		1094 (शा. नाला)	0.0229
		1104	0.0757
		1105	0.2731
		1103	0.0111
		1116	0.1238
		1117	0.1332
		1118	0.0471
		1119	0.0455
		1120	0.0517
		1130	0.2293
		1144	0.0420
		1143	0.1566
		1142	0.0397
		1155	0.1031
		1156	0.3276
		1157	0.0493
		1167	0.2749
		1166	0.2308
		1176	0.1674
		1175	0.0629
		1179	0.1744
		1180 (शा. रास्ता)	0.0140
		1184	0.2055
		1190	0.1596

1	2	3	4
14.	नांदेड (जारी)	1193	0.1262
		1195	0.2232
		1201	0.1828
		1203	0.1626
		1206	0.3805
		1192	0.0100
		1145	0.1950
		1146	0.1200
		1581 (शा. नाला)	0.0460
		1147	0.0110
15.	खेड़ा पचोला	266 (शा. भूमि)	0.0513
		264	0.1480
		263	0.1368
		262 (शा. रास्ता)	0.0102
		259	0.2381
		249	0.4515
		250	0.0117
		233	0.7431
		412 (शा. रास्ता)	0.0470
		481	0.1105
		494	0.1652
		495	0.0529
		492	0.0242
		493	0.0969
		518	0.1462
		517	0.1448
		519	0.0103
		528	0.1898
		533	0.1453
		532	0.1885
		536	0.0733
		535	0.1380
		557	0.0182
		556	0.1574
		523	0.0330
		261	0.1700
		506 (शा. नाला)	0.0200
		258	0.0200
16.	कढ़ाई	232 (शा. भूमि)	0.0249
		758	0.1328
		760	0.1869

1	2	3	4
16.	कढ़ाई (जारी)	762	0.1358
		769	0.3964
		791	0.1816
		792	0.1030
		796	0.0578
		797	0.2951
		800	0.3031
		819 (शा. रास्ता)	0.0491
		793	0.0410
		789	0.0105
17.	चिकली	369(शा. भूमि)	0.0188
		368	0.1716
		370	0.0163
		367	0.2313
		366	0.0731
		356	0.1100
		357	0.1205
		354	0.1400
		335 (शा. नाला)	0.0348
		353	0.0522
		96	0.0154
		98	0.1908
		99	0.1340
		100	0.0559
		102	0.2256
		107	0.0200
		106	0.0662
		112	0.0700
		113	0.0775
		130	0.0858
		131	0.0857
		132	0.0939
		135	0.1763
		136 (शा. रास्ता)	0.0659
		137	0.0754
		138	0.1514
		139	0.0101
		148	0.1710
		149 (शा. रास्ता)	0.0171
		154	0.3000
		170	0.1343

1	2	3	4
17.	चिकली (जारी)	169	0.1383
		550	0.2350
		549	0.0525
		571	0.0600
		572	0.2664
		570	0.0432
		577	0.2178
		578	0.0642
		559 (शा. भूमि)	0.0325
		548	0.0140
		350 (शा. रास्ता)	0.0400
		111	0.0100
		171	0.0100
18.	खेड़ाचितावल्या	405	0.0622
		406	0.2210
		407	0.2350
		412	0.4003
		444 (शा. भूमि)	0.3681
		442	0.1051
		498 (शा. नाला)	0.0407
		446	0.1117
		447	0.3557
		453	0.2554
		454	0.1117
		457	0.1127
		455	0.0498
		456	0.0319
		505	0.0325
		506	0.2126
		508	0.1680
		510	0.4287
		512	0.1600
		445	0.0327
		513	0.0200
		514 (शा. भूमि)	0.0100
		515 (शा. भूमि)	0.0400
		412/677	0.0600
		516	0.0100

1	2	3	4
19.	रावणखेड़ी	187 (शा. भूमि)	0.0185
		189	0.0548
		214	0.0142
		190	0.0680
		208	0.1590
		207	0.0174
		206	0.0772
		205	0.0174
		204	0.0582
		203	0.0534
		202	0.0571
		201	0.0517
		200	0.0110
		182	0.0800
		183	0.1000
		176	0.1551
		177	0.0216
		175	0.1915
		178	0.0306
		158 (शा. नाला)	0.0202
		35	0.1064
		36	0.0752
		37	0.1447
		38	0.2447
		67	0.1321
		68	0.2305
		69	0.0441
		73	0.2951
		72	0.2961
		91 (शा. भूमि)	0.0140
		213	0.0100
		174	0.0100
		173	0.0300
		199	0.0100
		181	0.0100
		209	0.0100
20.	खोकरिया	44	0.0139
		45	0.3339
		43	0.0685
		20	0.2168
		1	0.0184
20.	खोकरिया (जारी)	3	0.4007
		4	0.2229
		5	0.0421
		9	0.1123
		8	0.2514
		15	0.0949
		17	0.1859
		20	0.2186
		21	0.0854
		22	0.0102
		23	0.1217
		241	0.0263
		245	0.1980
		242	0.0180
		246	0.0607
		252	0.0867
		249	0.0714
		258	0.0528
		261	0.1729
		260	0.0329
		262	0.0408
		314	0.2729
		315	0.3631
		322	0.0373
		317	0.2439
		318 (शा. रास्ता)	0.0306
		264 (शा. नाला)	0.0200
		26	0.0100
		243	0.0200
		244	0.0100

[फा. सं. आर-31015/67/2004-ओ आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 20th January, 2005

S. O. 333.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Manglya (Indore) terminal in the State of Madhya Pradesh, an extension pipeline to Piyala in the State of Haryana and Bijwasan in the NCT of Delhi should be laid by Bharat Petroleum Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri V.P. Pathak, Competent Authority, Mumbai-Manglya Pipeline Extension Project, Bharat Petroleum Corporation Limited, MB-7, Mahashweta Nagar, Mahendra Bhatnagar Road, Ujjain-456010 (Madhya Pradesh).

SCHEDULE

Tehsil : Tarana District : Ujjain State : Madhya Pradesh

S.No.	Name of Village	Survey No.	Area in Hectare
1	2	3	4
1.	Bherupura	2	0.4043
		3	0.3724
		19	0.1254
		20	0.1402
		21	0.1643
		22	0.4903
		76	0.4970
		78	0.0209
		77	0.2427
		91 (Govt. Land)	0.0100
2.	Shivpura	1 (Govt. Land)	0.2372
		3	0.1957
		4	0.2561
		5	0.2193
3.	Binjal	22	0.3050
		23	0.0348
		20	0.1474
		19	0.2504
		15	0.0100
		24 (Govt. Road)	0.0269
		50	0.0825
		50/322	0.0535
		51 (Govt. Road)	0.0100
3.	Binjal *(Contd.)*	52	0.0472
		57	0.1500
		59	0.0100
		58	0.0770
		56	0.1118
		125	0.2410
		144 (Govt. Road)	0.0721
		145 (Govt. Land)	0.0514
		143	0.2874
		141	0.0767
		142	0.0137
		124	0.0107
		147	0.0105
		150	0.0109
		151	0.0105
		21	0.0108
4.	Bhukhi Itwarpur	6	0.2310
		7	0.1347
		8	0.0900
		35 (Govt. Road)	0.0129
		36	0.0100
5.	Kawali Khera	276 (Govt. Nala)	0.0706
		282	0.0521
		281	0.0478
		280	0.0710
		283	0.0110
		284	0.1474
		285	0.0523
		290	0.0120
		551 (Govt. Land)	0.0200
		552	0.0475
		554(Govt. Road)	0.0274
		555 (Govt. Land)	0.0165
		562	0.0908
		563	0.3834
		572	0.2458
		573 (Govt. Land)	0.0564
6.	Bhadsimba	436 (River)	0.0951
		298	0.0195
		299	0.1128
		300	0.1437
		311	0.1178

1	2	3	4
6.	Bhadsimba	312	0.1358
	(Contd.)	314	0.0187
		315	0.1806
		318	0.1361
		317	0.0342
		378	0.1785
		377	0.0100
		270	0.0100
		379 (Govt. Road)	0.0340
		385	0.1234
		386	0.0188
		387	0.0732
		388	0.1579
		389	0.1700
		399	0.1025
		400	0.0140
		307	0.0437
		517	0.3486
		737	0.3161
		736	0.1378
		735	0.2008
		601	0.0120
		734	0.0239
		602	0.3850
		606	0.2700
		605	0.1700
		608	0.0700
		613	0.4256
		612	0.1500
		615	0.0100
		651	0.1800
		618	0.0200
		648	0.2306
		661 (Govt. Nala)	0.0538
		664	0.0546
		663	0.0434
		662	0.3969
		663	0.1371
		647	0.0310
		636 (Govt. Nala)	0.0450
		609	0.0100
7.	Gavadi	17	0.1401
		16 (Govt. Nala)	0.0184
		14	0.0183
		13	0.3599
		15	0.0486
		11	0.3680
		8	0.0116
		67	0.1804
		79 (Govt. Road)	0.0580
		103	0.7133
		104 (Govt. Nala)	0.0212
		109 (Govt. Land)	0.1987
		108	0.2877
		107	0.0281
		111 (River)	0.1600
		81	0.0800
8.	Naugava	483	0.2891
		481	0.1119
		480	0.2201
		50	0.1403
		478	0.0735
		51	0.0290
		477(Govt. Nala)	0.1022
		472 (Govt. Land)	0.0436
		59	0.4409
		60	0.0350
		87 (Govt. Nala)	0.0252
		391	0.0399
		394	0.1864
		393	0.2344
		377 (Govt. Road)	0.0490
		376	0.2152
		374	0.1547
		362	0.3273
		373	0.1361
		363	0.0297
		330	0.0154
		364	0.0356
		329	0.1257
		328	0.0102
		325	0.0270
		324	0.0372

1	2	3	4
8.	Naugava *(Contd.)*	319	0.0811
		320	0.1440
		302	0.0451
		300	0.1887
		301	0.0428
		299 (Govt. Road)	0.0320
		286	0.0466
		283	0.0262
		285	0.0106
		284	0.1257
		241	0.0968
		240 (Govt. Nala)	0.0181
		237	0.1357
		238	0.1189
		236	0.0352
		638	0.1524
		637	0.3685
		661 (Govt. Road)	0.0326
		659	0.2438
		658	0.0789
		671	0.0619
		676	0.0242
		672	0.1193
		675	0.1653
		676	0.0100
		676/708	0.2496
		685	0.1530
		684	0.0769
		688	0.0757
		689	0.2040
		693 (Govt. Land)	0.0710
		358	0.0310
		355	0.0320
		361	0.0200
		322	0.0100
		58	0.0100
		372	0.0200
		331 (Govt. Road)	0.0360
9.	Bisankheri	108 (Govt. Land)	0.0246
		112	0.1855
		123	0.1523
		124	0.0362
9.	Bisankheri *(Contd.)*	125	0.1265
		126	0.0878
		127	0.1907
		291	0.1169
		303	0.2867
		308	0.3559
		309	0.0337
		311	0.2091
10.	Bisankhera	287 (Govt. Nala)	0.0150
		288	0.0296
		281	0.1396
		280	0.1900
		279	0.1892
		274(Govt. Road)	0.0805
		200	0.2074
		256	0.0716
		255	0.2347
		260	0.0223
		259 (Govt. Road)	0.0151
		268	0.2448
		312	0.0200
		326	0.1900
		324	0.0249
		327	0.1289
		325	0.2669
		338	0.4348
		317 (Govt. Land)	0.0332
		311	0.2000
		269	0.0800
11.	Itawa	2	0.0455
		1	0.3026
		5	0.1176
		6	0.2868
		7	0.1661
		9	0.1671
		19	0.1471
		20	0.1727
		21	0.1460
		22	0.1627
		40	0.0449
		41	0.1264
		42	0.0983

1	2	3	4
11.	Itawa *(Contd.)*	43	0.1912
		57	0.2852
		58	0.0281
		61 (Govt. Road)	0.0176
		63	0.1200
		71	0.0634
		64	0.0398
		65	0.1199
		65/1229	0.0468
		70 (Govt. Road)	0.0497
		66	0.1757
		67	0.1807
		671	0.0885
		672	0.0997
		673	0.0639
		674	0.0680
		675	0.0756
		676	0.0733
		677	0.3701
		685 (Govt. Nala)	0.0300
		3	0.0100
		68	0.0500
12.	Khakari Sultan	213	0.0186
		218	0.3252
		220 (Govt. Land)	0.0127
13.	Lodh	57	0.0280
		58	0.4219
		62	0.2759
		65	0.1308
		66	0.1018
		67	0.0508
		68	0.0449
		69	0.514
		70	0.0539
		72	0.2942
		205 (Govt. Road)	0.0193
		274	0.0655
		270	0.0834
		275	0.2893
		276	0.1446
		368	0.1945
		367	0.0535
13.	Lodh *(Contd.)*	366	0.0521
		364	0.0517
		365	0.1404
		376	0.2035
		377	0.1214
		352 (Govt. Land)	0.0188
		649	0.0133
		648 (Govt. Land)	0.3554
		647 (Govt. Nala)	0.0259
		705	0.0259
		645	0.1343
		644	0.0885
		643	0.0225
		642	0.0182
		639	0.0879
		640	0.0231
		638	0.1209
		713	0.0222
		629	0.1212
		628	0.1005
		627	0.0876
		626	0.0712
		773/882	0.1838
		774	0.0726
		775	0.3296
		624	0.0117
		623	0.1426
		622	0.1051
		621	0.0115
		614	0.1928
		613	0.1109
		612	0.1486
		611 (Govt. Land)	0.0364
		835	0.0100
		277	0.0300
14.	Nanded	966 (Govt. Land)	0.0985
		995	0.0670
		1003	0.1625
		1002	0.0105
		1006	0.3462
		1005	0.0633
		1045	0.2835

1	2	3	4
14.	Nanded *(Contd.)*	1043	0.2908
		1040	0.1800
		1062	0.1248
		1041	0.0139
		1061	0.0378
		1063	0.1174
		1080	0.1825
		1079	0.1562
		1083	0.0476
		1078	0.0250
		1094 (Govt. Nala)	0.0229
		1104	0.0757
		1105	0.2731
		1103	0.0111
		1116	0.1238
		1117	0.1332
		1118	0.0471
		1119	0.0455
		1120	0.0517
		1130	0.2293
		1144	0.0420
		1143	0.1566
		1142	0.0397
		1155	0.1031
		1156	0.3276
		1157	0.0493
		1167	0.2749
		1166	0.2308
		1176	0.1674
		1175	0.0629
		1179	0.4744
		1180 (Govt. Road)	0.014
		1184	0.2055
		1190	0.1596
		1193	0.1262
		1195	0.2232
		1201	0.1828
		1203	0.1626
		1206	0.3805
		1192	0.0100
		1145	0.1950
		1146	0.1200
		1581 (Govt. Nala)	0.0460
		1147	0.0110

1	2	3	4
15.	Khera Pachola	266 (Govt. Land)	0.0513
		264	0.1480
		263	0.1368
		262 (Govt. Road)	0.0102
		259	0.2381
		249	0.4515
		250	0.0117
		233	0.7431
		412 (Govt. Road)	0.0470
		481	0.1105
		494	0.1652
		495	0.0529
		492	0.0242
		493	0.0969
		518	0.1462
		517	0.1448
		519	0.0103
		528	0.1898
		531	0.0634
		533	0.1453
		532	0.1885
		536	0.0733
		535	0.1380
		557	0.0182
		556	0.1574
		523	0.0330
		261	0.1700
		506 (Govt. Nala)	0.0200
		258	0.0200
16.	Kadhai	232 (Govt. Land)	0.0249
		758	0.1328
		760	0.1869
		762	0.1358
		769	0.3964
		791	0.1816
		792	0.1030
		796	0.0578
		797	0.2951
		800	0.3031
		819 (Govt. Road)	0.0491
		793	0.0410
		789	0.0105

1	2	3	4
17.	Chikali	369(Govt. Land)	0.0188
		368	0.1716
		370	0.0163
		367	0.2313
		366	0.0731
		356	0.1100
		357	0.1205
		354	0.1400
		335 (Govt. Nala)	0.0348
		353	0.0522
		96	0.0154
		98	0.1908
		99	0.1480
		100	0.0559
		102	0.2256
		107	0.0200
		106	0.0662
		112	0.0700
		113	0.0775
		130	0.0858
		131	0.0857
		132	0.0939
		135	0.1763
		136 (Govt. Road)	0.0659
		137	0.0754
		138	0.1514
		139	0.0101
		148	0.1710
		149 (Govt. Road)	0.0171
		154	0.3000
		170	0.1343
		169	0.1383
		550	0.2350
		549	0.0525
		571	0.0600
		572	0.2664
		570	0.0432
		577	0.2178
		578	0.0642
		559 (Govt. Land)	0.0325
		548	0.0140
		350 (Govt. Road)	0.0400
		111	0.0100
		171	0.0100
18.	Kheda Chitawaliya	405	0.0622
		406	0.2210
		407	0.2350
		412	0.4003
		444 (Govt. Land)	0.3681
		442	0.1051
		498 (Govt. Nala)	0.0407
		446	0.1117
		447	0.3557
		453	0.2554
		454	0.1117
		457	0.1127
		455	0.0498
		456	0.0319
		505	0.0325
		506	0.2126
		508	0.1680
		510	0.4287
		512	0.1600
		445	0.0327
		513	0.0200
		514 (Govt. Land)	0.0100
		515 (Govt. Land)	0.0400
		412/677	0.0600
		516	0.0100
19.	Rawankheri	187 (Govt. Land)	0.0185
		189	0.0548
		214	0.0142
		190	0.0680
		208	0.1590
		207	0.0174
		206	0.0772
		205	0.0174
		204	0.0582
		203	0.0534
		202	0.0571
		201	0.0517
		200	0.0100
		182	0.0800
		183	0.1000
		176	0.1551
		177	0.0216

1	2	3	4
19.	Rawankheri	175	0.1915
	(Contd.)	178	0.0306
		158 (Govt Nala)	0.0202
		35	0.1064
		36	0.0752
		37	0.1447
		38	0.2447
		67	0.1321
		68	0.2305
		69	0.0441
		73	0.2951
		72	0.2961
		91 (Govt. Land)	0.0140
		213	0.0100
		174	0.0100
		173	0.0300
		199	0.0100
		181	0.0100
		209	0.0100
20.	Khokariya	44	0.0139
		45	0.3339
		43	0.0685
		20	0.2168
		1	0.0184
		3	0.4007
		4	0.2229
		5	0.0421
		9	0.1123
		8	0.2514
		15	0.0949
		17	0.1859
		20	0.2186
		21	0.0854
		22	0.0102
		23	0.1217
		241	0.0263
		245	0.1980
		242	0.0180
		246	0.0607
		252	0.0867
		249	0.0714
		258	0.0528
20.	Khokariya	261	0.1729
	(Contd.)	260	0.0329
		262	0.0408
		314	0.2729
		315	0.3631
		322	0.0373
		317	0.2439
		318 (Govt. Road)	0.0306
		264 (Govt. Nala)	0.0200
		26	0.0100
		243	0.0200
		244	0.0100

[F. N. R-31015/67/2004-OR-II]

HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005

का०आ० 334.—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2004 के अधिक्रमण में श्री बी० साम बाब, आई० ए० एस० (एपी:83) निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को तेल उद्योग विकास बोर्ड में सचिव, संयुक्त सचिव के स्तर के पद पर 5 फरवरी 2004 अपराह्न से 31-3-2005 तक के कार्यकाल को अगले आदेश जारी होने तक या जो भी पहले हो, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की खण्ड (ई) धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा श्री बी० साम बाब को दिनांक 24-7-2007 तक तेल उद्योग विकास बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. जी 35012/2/03-वित्त.-II]

के० पी० के० नम्बीसन, अवर सचिव

New Delhi, the 24th January, 2005

S. O. 334.—In supersession of Ministry of Petroleum & Natural Gas notification dated 5th February, 2004 appointing Shri B. Sam Bob, IAS (AP:83) Director, Ministry of Petroleum and Natural Gas, as Secretary, Oil Industry Development Board at the level of Joint Secretary with effect from forenoon of 5th February, 2004 for the balance period of his tenure i.e. up to 31-3-2005 or until further orders, whichever event takes place earlier, Government of India, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974) hereby appoint Shri B. Sam Bob as Secretary, OIDB upto 24-7-2007.

[No. G-35012/2/03-Fin-II]

K. P. K. NAMBISSAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005

का०आ० 335.— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के का० आ० 1430 दिनांक 14 जुन, 2004 द्वारा पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना प्रकाशित कर, सलाया-मथुरा पाइपलाइन प्रणाली के विरमगाम-कोयली सेक्शन की संवर्द्धन परियोजना हेतु, अपरिष्कृत तेल का परिवहन करने के प्रयोजन के लिए, विरमगाम से कोयली तक पाइपलाइन बिछाने हेतु उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिट की भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को दिनांक 21-08-2004 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिर्पोट दे दी है।

और, केन्द्रीय सरकार को उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए। अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जन किया जाता है।

यह और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका : पेटलाद जिला : आणंद राज्य : गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे. संख्या	उप-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर मीटर	एयर	वर्ग
1	2	3	4	5	6
बामरोली	854		0	16	30

[फा० सं० आर०-25011/3/2001-ओ० आर०- I]

रेणुका कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 24th January, 2005

S.O. 335.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas number S. O. 1430 dated 14th June, 2004 issued under Sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (herein after referred to as the said Act) the Central Govermment declared its intention to acquire the right of user in the lands specificd in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Crude Oil from Viramgam to Koyli in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the Augmentation of Viramgam-Koyli Section of Salaya-Mathura Pipeline System;

And, whereas, copies of the said notification were made available to the public on 21-08-4,

and whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act has submitted the report to the central Government;

And whereas, the central Government, after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this Notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification area hereby acquired;

And further, in the exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vest from the date of publication of this declaration, in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Taluka : Petlad District : Anand State: Gujarat

Name of the Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5	6
Bamroli	854		0	16	30

[F. No. R-25011/3/2001-OR-I]

RENUKA KUMAR, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

का. आ. 336.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, एफ. सी. आई. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली नं. 1 (संदर्भ संख्या 42/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/209/2003-आई. आर. (सीएम-II)]
एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 28th December, 2004

S.O. 336.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 42/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workman, which was received by the Central Government on 27-12-2004.

[No. L-22012/209/2003-IR(CM-II)]
N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

Shri S. S. Bal, Presiding Officer.

I. D. No. 42/2004

In the matter of dispute between :

Shri Ghulam Hasan Bhatt,
through Food Corporation of India Workers' Union,
58/1, Diamond Harbour Road,
Kolkata-700023. . . . Workman

Versus

The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
17, Prabhat Building,
Rajendra Place, New Delhi. . . . Management

APPEARANCES :

None for the workman.

Shri Dharam Dass, Assistant Manager,
Food Corporation of India for mgt.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its order No. L-22012/209/2003 IR (CM-II) dated 9-8-2004 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication .—

"Whether the action of the Management of Food Corporation of India, New Delhi in not promoting Shri Ghulam Hasan Bhatt as Sardar as per the agreement dated 24-5-1984 is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The reference was received and registered on 10-9-2004 and notices to workman and management were issued and case was posted for filing claim on 25-10-04 by the workman. On 25-10-04 none for the workman appeared despite notice. Shri Dharam Dass, Assistant Manager for the management appeared and case was adjourned to 16-12-2004. Today also none is present for the workman and Shri Dharam Dass appeared for the management and gave statement that since the worker has been superannuated from 30-6-2003 and no further pursuance have been obtained from his side, the case should be closed The fact is that at the time of his superannuation there was no vacancy for the post of Sardar and as such he had not been given benefit of promotion from Mandal to Sardar

3. In view of the statement of Shri Dharam Dass, Assistant Manager, Food Corporation of India that the petitioner has since retired and there is no post of Sardar in the respondent Corporation (F. C. I.) as such I have no reason to disbelieve the statement made today in the court by Shri Dharam Dass on oath, the claim of the petitioner has become infructuous and he is not entitled to the same. Case is, therefore, disposed of. In case the workman has any grievance he may take steps for revival of the reference according to law as advised. Hence 'No dispute Award' is accordingly passed. File be consigned to Record Room.

Dated : 16-12-2004 S. S. BAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

का. आ. 337.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, ई.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल (संदर्भ संख्या 11/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/193/2002-आई. आर. (सीएम-II)]
एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th December, 2004

S.O. 337.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 11/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure in the

Industrial Dispute between the management of M/s. Eastern Coalfields Limited and their workman, received by the Central Government on 27-12-2004.

[No. L-22012/193/2002-IR(CM-II)]
N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT :

Sri Md. Sarfaraz Khan, Presiding Officer.

Reference No. 11 of 2003

PARTIES :

The Agent,
Kalidaspur Project,
M/s. Eastern Coalfield Ltd.,
P. O. Bharakalibari,
Dist. Bankura . . . Management.

Vrs.

Sri Md. Jabir, Trammer,
Represented by the General Secretary,
Koyala Mazdoor Congress,
Gorai Mansion, P. O. Asansol.
Dist. Burdwan (WB). . . . Workman.

REPRESENTATIVES :

For the Management : Sri P. K. Das, Advocate.

For the Workman General (Union) : Sri Rakesh Kumar, General Secretary of K. M. C.

Industry : Coal State : West Bengal

Dated : 9-11-2004

AWARD

In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-Section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its letter No. L-22012/193/2002 IR (CM-II) dated 12-5-2003 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kalidaspur Project under Satgram Area in dismissing Md. Jabir, Trammer w.e.f. 19-4-1995 is justified ? If not, to what relief he is entitled to ?"

2. In pursuance to summons issued to the respective parties through the registered post after the receipt of the said reference, both the concerned parties appeared through their respective representatives and filed their written statement separately in support of their claim.

3. The case of the workman in brief compass as setforth in the written statement filed on behalf of the workman concerned is that Md. Jabir, Trammer of Kalidaspur Project is a permanent employee of the company who has been charged for the absence from his duty on 6-9-94 under clause 17(1)(n) of the Model Standing Orders applicable to the establishment.

4. The main case of the workman is that Md. Jabir had submitted the reply to the charge-sheet mentioning therein that he was sick and was under the treatment of a Doctor and for that effect the treatment paper and certificate of the Doctor was submitted to the management but even then he was not allowed to join his duty.

5. The further case of the workman is that the workman duly participated in the enquiry proceeding and in support of his claim treatment papers and the medical certificate were submitted during the proceeding which finds place in the enquiry report and the E. O. has mentioned in his report and findings that the absence of the workman is proved but his absence was due to his sickness. The agent of the Kalidaspur Project on the basis of the enquiry report recommended for allowing him to join his duty with stoppage of two annual increments from the basic pay vide his note sheet dated 9/10-3-95 but the Dy. C. P. M. of the Area recommended for his dismissal which was approved by the General Manager of the Area.

6. It is also the case of the workman that before imposing any penalty against the workman, no second show cause notice was ever issued to the workman which amounts denial of natural justice and violation of the directives of the Hon'ble Apex Court. The management is claimed to have taken a harsh decision and awarded extreme punishment of dismissal. The management should have taken a lenient view and some lighter punishment in the light of the recommendation of the Agent should have been imposed. The dismissal of the workman has been challenged to be unjust and illegal. So relief for his re-instating with full back wages has been sought.

7. On the other hand in brief the defence case of the management according to its written statement is that the dispute for the first time was raised before the Assistant Labour Commissioner after lapse of seven years.

8. The main defence of the management is that the Agent of Kalidaspur Project is not the disciplinary authority and the General Manager is not bound to accept the recommendation of the Agent and before imposing the penalty of dismissal the past records of the workman was called for to judge the recommendation of the Agent but the past record was very dismisal and on the earlier occasion he was charge-sheeted for the offence of unauthorised absence and was accordingly punished. The

punishment awarded is claimed to be just and proper in view of his previous conduct in respect of an unauthorised absence. The concerned workman has been earning his livelihood from other sources and hence he is not entitled to any monetary relief.

9. The record goes to show that a hearing on the preliminary point was also made on 9-11-2004. Both the parties were heard on this point. The enquiry proceeding was not challenged by the side of the workman. The management has also concede to the submission of the union. The record was also perused and it was found that the workman had duly participated in the enquiry proceeding and sufficient opportunity to defend himself was given and accordingly it was held that enquiry proceeding was valid and fair. The case was accordingly heard finally on merit and the award was reserved for order.

10. Before entering into the discussion of the merit of the case I would like to mention the facts which are admitted one.

11. It is the admitted fact that Md. Jabir, Trammer is the permanent employee of Kalidaspur Project under Satgram Area.

12. It is further admitted fact that the concerned workman was absent from his duty since 16-3-94 without any prior permission in and information to the management and the workman was dismissed followed by an enquiry in which he duly participated.

13. It is also the admitted fact that workman was chargesheeted only for an unauthorised absence w.e.f. 16-3-94 and he was held guilty only for the misconduct under clause 17(1)(n) of the Model Standing Order and there is no change for the habitual absence of the workman.

14. In view of the pleadings of the parties it is also admitted fact that Agent, Kalidaspur Project having regards to the findings of the enquiry officer, had recommended to allow the workman to join his duty with certain proposed punishment vide his note-sheet No. ECL/KDP/DXCME/30/95/1213 dated 9/10-3-95. So as per the settled principles of law the facts admitted one need note he proved and accordingly these admitted facts are not required to be discussed in detail.

15. From the perusal of the records it transpires that none of the parties has examined any oral witness in support of their case rather both the parties have tendered some Xerox copies of the document on their behalf.

16. The management has filed the copy of the charge-sheet under Ref. ECL/KDP/PO/WO(T) per/2764 dated 6-9-94. Copy of findings of Enquiry Officer Notices of Enquiry. Appointment letter of the Enquiry Officer. Attendance sheet of last three years called for by the management dated 18th March, 1995. These all documents excepting the last one are the admitted documents as their genuineness and legality has not been challenged by the union.

17. Likewise the union has also filed certain documents in support of its claim. Xerox copy of the application of the workman to allow him to join his duty dated 9-1-95, Xerox copies of the treatment papers alongwith the Medical Certificate granted by one Dr. Manish Kumar Sinha, Psychiatrist, R. M. A. Kanke, Ranchi dated 6-1-95 and the last one the Xerox copy of the note-sheet of the management in which Agent had recommended for allowing the delinquent workman to join his duty. These all documents appear to be relevant and admissible as their correctness genuineness and legality has not been challenged by the management.

18. On perusal of the enquiry proceedings I find that the delinquent workman had categorically admitted in his statement that due to the sudden death of his mother he became mentally abnormal and his father took him to Ranchi for his treatment with Dr. Mukesh Kumar Sinha at Ranchi where he was under the treatment w.e.f. 5-3-94 to 6-1-95. It has also come in his statement during the enquiry proceedings that his father was busy in his treatment at Ranchi, so no information about his absence could be sent to the management. The enquiry officer has also admitted these facts in his findings that in support of the aforesaid contention the workman had filed the Medical Certificate and the prescription of his treatment granted by the Doctor Mukesh Kumar Sinha, Psychiatrist at R. M. A. Kanke, Ranchi. The enquiry officer has categorically mentioned in his findings that the charges levelled against Sri Jabir Mian for unauthorised absence for 16-3-94 is proved but without sufficient cause is not proved because he has produced medical prescriptions as well as certificates in which it appears that he was suffering with mental disease.

19. The workman has filed a copy of note-sheet No. ECL/KDP/DYCME/30/95/1213 dated 9/10-3-95 issued by Dy. C. M. E./Agent Office recommending to consider the case of allowing the workman to join his duty. Considering all the facts report of the enquiry officer the findings therein the evidence recorded and other connected papers the Agent had recommended the punishment (i) For treating the period of absence as No Work No Pay, (ii) Stoppage of two annual increment. But the reason for not accepting the recommendation by the General Manager of the company does not appear to be reasonable and convincing.

20. In view of the above facts circumstances and the material available on the record I find that the workman was absenting himself from his duty with effect from 16-3-94 to 6-9-94 i.e. near about six months continuously without any information and prior permission of the management. The enquiry officer has

rightly held him guilty for unauthorised absence. But the enquiry officer has also given in his findings that the unauthorised absence of the workman without sufficient cause is not proved because Medical Certificate were produced to show that the workman concerned was suffering with mental disorder. However since the charge of an unauthorised absence for the relevant period is proved so the delinquent workman deserves same punishment for the misconduct proved according to the gravity of the misconduct as provided in the Model Standing Order applicable to the establishment.

21. Now the only main point to be considered by the Court is to see as to how for the punishment awarded by the management is just and proper and proportionate to the alleged nature of misconduct proved against the workman concerned.

22. On the aforesaid point I heard a detailed argument was advanced by the side of both the parties. During the course of argument it was submitted by the side of the workman that it is a simple cause of an unauthorised absence for a few months and the reasons for the absence from the duty has been sufficiently explained and the reasons of absence supported with Medical Certificate have been found sufficient and convincing by the enquiry officer and on that ground a lenient punishment was also proposed by the Agent of the management. I find much force in argument of the union and I am convinced to hold that the workman concerned was absent during the relevant period under the compelling circumstance beyond his control.

23. It was also submitted by the side of union that the pleading of the management that prior to dismissal the General Manager had called for the past record in relation to the concerned workman which shows that the workman was found guilty of such an offence in several occasions for which he was charge-sheeted for the offence of unauthorised absence and was punished after enquiry has got no hearing on the merit of the case as no chit of paper has been filed from the side of the management to show that the workman concerned is a habitual absentee and has ever been held guilty for the misconduct and punishment was awarded to that effect.

24. On perusal of the record it transpires that there is no charge of habitual absence nor the enquiry officer has whispered a word even in this regard. Besides this management has got no right to consider the previous conduct of the workman for which some punishment if any awarded without issuing a charge-sheet in this regard and giving the copies of those relevant papers providing sufficient opportunity to meet the charges. Simply pleading of the facts in the W/S without any legal prove will not be taken into consideration and the punishment for the subsequent misconduct can't be imposed in the light of the previous misconduct if any for which the workman did not stand charged. Here the management having considered the misconduct if any committed previously during the entire service carrier of the workman has claimed to have passed the capital punishment in the subsequent misconduct proved against the delinquent workman which is basically illegal and against the principles of natural justice.

25. It is further apparently clear from the record and pleading itself that no second show cause notice was ever issued to the delinquent workman before passing the order of dismissal which itself is a serious lapses on the part of the management and deliberate violation of the mandate of the Apex Court which also amounts to the breach of the principles of natural justice.

26. It has been pleaded clearly in the W/S of the union that Md. Jabir is not having any source of income except employment in the E. C. L. and now he is in starving position. But this fact has been denied by the management in its pleading rather the management has taken the plea that concerned workman has been earning his livelyhood from other sources and hence he is not entitled to any relief. But this aspect of the facts of the pleading of the management has not been proved. No any witness has been examined nor any chit of paper in this regard has been filed to prove that the workman is gainfully employed anywhere. So this vague pleading of the management cannot be taken into consideration in absence of any cogent prove.

27. It appears that the management has not cared to even honour the provisions laid down in the Model Standing Order. It is clearly indicated and is the spirit of the Model Standing Order that the quantum of punishment should be decided on the basis of the period of absence and the gravity of the misconduct. According to the provision of the Model Standing Order applicable to the establishment the extreme sorts of penalty as dismissal can't be imposed in such type of simple case of unauthoirsed absence. It has been several times clearly observed by the different Hon'ble High Courts and the Apex Court as well that before imposing a punishment of dismissal it is incumbent for the disciplinary authority to consider socio-economic background of the workman, family back ground, length of service put in by the employee, his post and other surrounding circumstances including the nature of the misconduct and the last one the compelling circumstances to commit the misconduct. These are the relevant factors which must have to be kept in mind by the authority at the time of imposing the punishment which is not done by the management.

28. The workman concerned is an illiterate man and is a member of the weaker section of the society. He is financially weak and poor who has suffered a lot for about ten years and he had never been gainfully employed anywhere during the period after his dismissal.

29. The attention of the Court was drawn by the union towards the provision u/s. 27(1) (page-15) of the Model Standing Order applicable to the establishment where various minor punishments have been prescribed to be awarded according to the gravity of the misconduct. I fail to think as to why only maximum punishment available under the said clause should be awarded in the present facts and circumstances of the case. It has been observed by the Apex Court, the highest Court of justice in India that justice must be tempered with mercy and that the delinquent workman should be given an opportunity to reform himself and to be loyal and disciplinary employee of the management. However, I am of the considered view that the punishment of dismissal for an unauthorised absence for a few months under the compelling circumstances and without any mala fide intension is not just and proper rather it is too harsh a punishment which is totally disproportionate to the alleged misconduct proved. Such a simple case should have been dealt with having taken a lenient view by the management. In this view of the matter I think it just and proper to modify and substitute the same exercising the power under Section 11(A) of the I.D. Act, 1947 to meet the ends of justice.

30. As such the impugned order of the dismissal of the concerned workman is hereby setaside and he is directed to be re-instated with the continuity of the service and in the light of the facts, circumstances and the misconduct for which the punishment of dismissal was imposed on the workman concerned I think it appropriate that the workman is imposed a punishment of stoppage of two increments, without cumulative effect. It is further directed that the workman will be entitled to get only 50% of the back wages which will serve the ends of justice. Accordingly it is hereby ordered that. Let an award be and the same is passed. Secretary is directed to send the copies of the award to the Ministry of Labour for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

MD. SARFARAZ KHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

का. आ. 338.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, ई. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल (संदर्भ संख्या 7/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/18/2003-आई. आर. (सीएम-II)]
एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th December, 2004

S.O. 338.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 7/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of M/s. ECL, and their workmen, which was received by the Central Government on 27-12-2004.

[No. L-22012/18/2003-IR(CM-II)]
N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT :

Md. Sarfaraz Khan, Presiding Officer.

Reference No. 7 of 2004

PARTIES :

The Agent,
Chora O. C. P Kenda Area of M/s. E. C. L.,
P. O. Bahula,
Distt. Burdwan (WB). . Management.

Vs.

Sri Uma Shankar Singh, Trade Apprentice,
represented by the General Secretary,
Koyala Mazdoor Congress,
Gorai Mansions, Asansol.
Distt. Burdwan (WB). . . . Workman.

REPRESENTATIVES :

For the Management	.	Sri P. K. Das, Advocate.
For the Workman (Union)	:	Sri S. K. Pandey, General Secretary of K. M. C.

Industry : Coal State : West Bengal

Dated . 19-10-2004

AWARD

In exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), Government of India through the Ministry of Labour vide its Order No. L-22012/18/2003-IR (CM-II) dated 19-01-2004 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by the Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Chora O. C. P. under Kenda Area of M/s. ECL in dismissing Sri Uma Shankar Singh, Trade Apprentice from the service is legal and justified ? If not, to what relief the said workman is entitled ?

2. In pursuance of the said order of reference, summons were issued to the respective parties through the Registered Post. On summons both the parties appeared through their representatives and filed their respective written statements in support of their claims.

3. In brief compass the case of the workman as per his written statement is that Sri Uma Shankar Singh was employed as Trade Apprentice at Chora O. C. P. of M/s. ECL. He became sick at Colliery Dispensary on 27-2-1996 and continued his treatment in the Dispensary for five days. But having found no improvement, he was shifted outside for treatment and after being declared fit the workman reported to the management but he was not allowed to resume his duty. The workman was simply informed that his service has been terminated.

4. The further case of the workman is that he had informed to the management about his sickness even then he was chargesheeted for alleged unauthorised absence from duty. The workman was neither served with the copy of the chargesheet nor any notice of enquiry etc. which amounts to violation of the principles of natural justice. The dismissal of the workman under the circumstances has been challenged to be illegal and unjustified for which a relief of reinstatement in the service with all the full back wages alongwith the consequential benefits have been sought.

5. On the other hand the case of the management in short as per its written statement is that the instant reference is claimed to be bad in the eye of law and the dispute referred by the union over the dismissal of Sri Uma Shankar Singh is entirely a misconceived one.

6. The main defence from the management is that the workman concerned was absent from his duty w.e.f. 7-12-95 without prior permission or grant of leave without any satisfactory cause for more than 10 days and for which he was chargesheet by the management for his unauthorised absence from duty on 8-7-1996. The chargesheet was sent to the workman at his home address but he did neither turn up nor sumbit any written explanations for the chargesheet. Ultimately a domestic enquiry was held for the alleged chargesheet by an independent enquiry officer. It is further alleged that the noices of enquiry was duly sent to the home address of the workman but even on receipt of the notice the workman deliberately avoided to appear before the enquiry officer due to which an ex parte enquiry was held and an enquiry report was submitted against him under clause 17(1)(n) and 17(1)(d) of the Model Standing Order holding the workman guilty for the misconduct.

7. It is denied that the management was ever informed about the sickness of the workman and he was not allowed to resume his duty. It is also denied that he was not served with a copy of chargesheet or notice of enquiry etc. were also not served upon him.

8. It is further claimed by the management the workman was issued a second show cause notice before imposing punishment and a copy of the enquiry report was also sent to the workman but he failed to submit any explanation in support of his defence and as such the action taken by the management against the workman is totally justified and accordingly the workman is not entitled to any relief sought for.

9. It is apparent from the ordersheets of the record that on 19-10-2004 a hearing on the preliminary point was made. The fairness and validity of the enquiry proceeding was not challenged by the workman and accordingly the enquiry proceeding was held to be valid and fair and as per the joint submissions of the parties the case was finally heard on merit and the award was kept reserved for order.

10. In para 1 & 2 of the pleadings of the written statement the management has taken the plea that the instant reference is bad in the eye of law and the dispute does not come under the scope of the Industrial Dispute Act. But the aforesaid plea or issue was neither raised nor pressed during the course of hearing of the case. The management has not either examined any witness or tendered even a chit of paper in support of its plea. I do not find any defect in the maintainability of the reference and the facts of the dispute very well comes under the scope of the Industrial Dispute Act. The Government of India through the Ministry of Labour has rightly referred the dispute to this Tribunal for its adjudication and accordingly this issue is decided against the management.

11. It is apparent from the record that none of the parties has examined any person as oral witness. Some Xerox copy of the documents have been filed by the side of the management. They are the copy of chargesheet claimed to have been issued to the workman on 26-12-96. Three sets of notices of enquiry issued by Registered Post. Copy of enquiry proceeding and its report. Second show cause notice, order of dismissal. These all documents are matters of record which have not been challenged by the side of the workman, so their legality and genuineness can't be questioned. It is the admitted fact that the delinquent workman was absent from his duty w.e.f. 7-12-95 to 8-7-96 i.e. about eight months. It has been pleaded in para 3 & 6 of the written statement filed by the union that the workman became sick and reported at colliery dispensary on 27-2-96 and continued his treatment at the dispensary for five days and having found no improvement he was taken outside for treatment. It is further pleaded that the workman kept informed to the management about his absence even then he was chargesheeted for alleged unauthorised absence from duty. But these facts of the pleadings have no any base to support. None has been either examined as a oral witness

or any chit of paper has been filed to show that the workman had informed to the management about his absence from duty. None has come forward to say that the workman had reported at colliery dispensary on 27-2-96 where he continued his treatment for five days. There is not even a chit of paper in this regard to show the treatment either at colliery dispensary or outside was made. As such I do not find any force in the aforesaid defence of the workman.

12. In view of the above fact circumstances, documents filed by the management and the materials available on the record I find that the workman concerned was absenting himself from duty with effect from 7-12-95 to 8-7-96 continuously without seeking prior permission or confirmation and without any sufficient cause and as such the concerned workman has rightly been found guilty for the misconduct by the enquiry officer for which deserves punishment by the management.

13. Now the only point to be considered by the Court is to see as to how for the punishment awarded by the management is proper just and proportionate to the alleged nature of the misconduct proved against the concerned workman ?

14. In course of argument it was submitted by the union side that it is a simple case of unauthorised absence for about 8 months which cannot be said be a gross misconduct. The attention of the Court was drawn towards the provision of Model Standing Order applicable to the establishment where the extreme punishment prescribed is dismissal as per the gravity of the misconduct and accordingly it is claimed that the extreme penalty can't be imposed upon the workman in such a minor case of misconduct for an unauthorised absence. It was further submitted that the workman has got unblamish record of his service and had never been ever held guilty for the unauthorised absence from his duty. I do find some force in the argument advanced by the side of the workman. It has been observed by the Apex Court that before imposing punisiument of dismissal it is necessary for the disciplinary authority to consider the very family background, economic background of the workman, length of service put in by the employee, his past records and other surrounding circumstances including the nature of the misconduct proved against the workman. The concerned workman is a very poor and illiterate man who had never been gainfully employed anywhere during the period after dismissal and has suffered a lot for more than eight years. Besides this when the Model Standing Order provides various minor punishment under Section 27(1) (page-15) why then the only maximum punishment available under the said clause should be awarded in case of an unauthorised absence. It has been observed by the Supreme Court that justice must be tampered with mercy and that the erring workman should be given an opportunity to reform himself and prove to be a loyal and disciplined employee of the management.

15. In the facts circumstances and the discussion made above I am of the view that the punishment of dismissal for an unauthorised absence for a few months without any ulterior motive is too harsh which is totally disproportionate to the gravity of the misconduct proved. Such a simple and plain case should have been dealt with by taking a lenient view by the management. In that view of the matter I think it necessary to modify the penalty imposed by the management to meet the ends of justice. And as such the impugned order of the dismissal of the concerned workman is hereby setaside and he is directed to be reinstated with the continuity of service. In the light of the facts circumstances and the bases on which the punishment of dismissal was imposed on the workman concerned I think it appropriate that the workman be imposed a punishment of stoppage of two increments without cumulative effect. It is further directed that the delinquent workman will be entitled to get only 30% of the back wages which will serve the ends of justice. Accordingly it is hereby ordered that let an award be and the same is passed. Secretary is directed to send the copies of the award to the Ministry of Labour for information and needfull.

MD. SARFARAZ KHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

का. आ. 339.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, ई. सी. एल. प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, आसलसोल के पंचाट (संदर्भ संख्या 70/1995) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-22012/206/1995-आई. आर. (सी-II)]
एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th December, 2004

S.O. 339.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 70/1995) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of ECL, and their workman, which was received by the Central Government on 27-12-2004.

[No. L-22012/206/1995-IR(C-II)]
N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT :

Md. Sarfaraz Khan, Presiding Officer.

Reference No. 70 of 1995

PARTIES :

The Manager,
Neamatpur Central Workshop,
ECL., P.O. Sunderchak,
Dist. Burdwan. . . . Management

Vs.

Sri R. S. Jaswara, Security Guard,
Represented by Sri Ranjit Banerjee,
Secretary, West Bengal Khan
Mazdoor Sangh, (UTUC). . . . Workman

REPRESENTATIVES :

For the Management : Sri P. K. Das, Advocate.

For the Workman (Union) : Sri Ranjit Banerjee, Secretary of the Union.

Industry : Coal State : West Bengal

Dated : 9-10-2004

AWARD

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), Government of India through the Ministry of Labour vide its Order No. L-22012/206/95-IR (C-II) dated 16/22-11-95 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Neamatpur Central Workshop in not paying idle period wages to Sh. R. S. Jaswara, Security Guard from 17-11-93 to 23-8-94 is justified ? If not, what relief the workman concerned is entitled to ?"

2. After receipt of the above reference from the Govt. of India, Ministry of Labour, summons were issued to the parties through the Registered Post with A/D. In pursuance of the summons both the parties appeared and filed their respective written statement in support of their claims. It is further clear from the record that an affidavit of the workman concerned was also filed by the union. But subsequently the union left taking any step in this case on behalf of the workman since 19-3-2002. Even after issue of fresh summons by registered post the workman did not appear in the Court to take any step in this case. A service report of the summons issued to the workman was received as the summon was personally served upon the union and 9-10-2004 was the date fixed for appearance of the union.

3. On perusal of the record it transpires that a petition dated 22-9-2004 was filed on behalf of the union represented by one Ranjit Banerjee [West Bengal Khan Mazdoor Sangh, (UTUC)] mentioning therein that the matter in respect of the said reference has already been mitigated with the higher authority of E. C. L. and there is no further claim for whatsoever a No Dispute Award may kindly be passed. This petition was put up on the date fixed i.e. 9-10-2004. The learned lawyer for the management also conceded that the matter has been settled so necessary order may be passed.

4. Perused the record, it transpires that this was the reference in respect of the payment of idle wages to Sri R. S. Jaswara, Security Guard from 17-11-93 to 23-8-94 by the management. Since the claim of the workman concerned has been settled with the management, no step was having taken by the union. Now the matter has been settled and no further claim is pending any more. It is necessary to disposed of the reference in view of the settlement. As such it is hereby ordered that let a 'NO DISPUTE AWARD' be passed and the same is passed in view of the submission by the sides of both the parties. The aforesaid reference is accordingly disposed of. Let a copy of the award be sent to the Ministry of Labour for information and needful.

MD. SARFARAZ KHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2004

का. आ. 340.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, ई. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचाट (संदर्भ संख्या 22/1999) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 27-12-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-22012/177/1998-आई. आर. (सीएम-II)]
एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th December, 2004

S.O. 340.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 22/1999) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of ECL, and their workman, which was received by the Central Government on 27-12-2004.

[No. L-22012/177/1998-IR(CM-II)]
N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT :

Sri Mohd. Sarfaraz Khan, Presiding Officer.

Reference No. 22 of 1999

PARTIES :

The Agent,
Shyamsunderpur Colliery,
M/s. ECL., P.O. Ukhra,
Dist. Burdwan. ... Management

Vs.

Sri Ramjee Rajbar,
Driller. ... Workman

REPRESENTATIVES :

For the Management	:	Sri P. K. Das, Advocate.
For the Workman (Union)	:	Sri S. K. Pandey, General Secretary, Koyala Mazdoor Congress, Asansol.

Industry : Coal State : West Bengal

Dated : 27-10-2004

ORDER

Sri P. K. Das, Advocate of the management and Sri S. K. Pandey, General Secretary of the union for the workman are present in the Court. A petition has also been filed by the learned lawyer of the management praying therein to direct the management to refer the age dispute of the concerned workman to the Apex Medical Board. The union has also endorsed by putting his no objection to the prayer.

From perusal of the record it transpires that the present reference is in respect of rectification of the date of birth of Sri Ramjee Rajbar, Driller as 8-6-1949 instead of 11-7-1946. Both the parties in pursuance of the summons appeared and filed their respective written statements in support of their claims. The record was fixed for adducing evidence from the side of the management and in the mean time the said petition was filed by the management side.

Heard both the sides on the point of determination of the age of the concerned workman. Both sides conceded that the matter may be referred for the determination of the age to the Apex Medical Board. Besides this it is admittedly clear from the records and the concerned documents that there is a clear cut variation in the age recorded in the records i.e. Form 'B' Register GM CMPF records and identity cards issued by the management which requires the reference of the matter in issue to the Apex Medical Board of the Company in the light of the provision of implementation instruction No. 76 issued by the JBCCI under NCWA-II, III & IV. As such the management is hereby directed to refer the age dispute of the delinquent workman Sri Ramjee Rajbar, Driller to the Apex Medical Board for determination of the age within one month from the date of receipt of order and as such the reference is accordingly disposed of. Let the copy of the order be issued to the management at once for the compliance of the direction as per order.

MD. SARFARAZ KHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2004

का. आ. 341.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, ई. सी. एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचाट (संदर्भ संख्या 56/1999) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-22012/413/1998-आई. आर. (सीएम-II)]
एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 30th December, 2004

S.O. 341.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 56/1999) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of ECL, and their workman, which was received by the Central Government on 30-12-2004.

[No. L-22012/413/1998-IR(CM-II)]
N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT :

Sri Md. Sarfaraz Khan, Presiding Officer.

Reference No. 56 of 1999

PARTIES :

The General Manager,
Satgram Project Area of M/s. ECL.,
P. O. Devchandnagar,
Dist. Burdwan. ... Management

Vs.

Sri Barun Chatterjee,
Cap Lamp Mazdoor. ... Workman

REPRESENTATIVES :

For the Management : None.

For the Workman : None.

Industry : Coal State : West Bengal

Dated : 08-12-2004

AWARD

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Government of India through the Ministry of Labour vide its Order No. L-22012/413/98-IR (CM-II) dated 25-05-1999 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by the Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Satgram Incline of M/s. ECL in not regularising Sh. Barun Chatterjee, Cap Lamp Mazdoor as Cap Lamp Issue Clerk is legal and justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. After receipt of the aforesaid reference from the Ministry of Labour, the summons were issued by the Registered Post to the parties concerned. In pursuance to the summons none of the parties appeared in the Court. The record goes to show that several adjournments for the appearance of the parties were given. But when they did not appear twice fresh notices by Registered Post with A/D were issued to the respective parties. It is clear from the endorsement of the parties in the A/D that personal service of the notice was made but even then none of the parties cared to appear in the Court to defend their case.

3. The facts, circumstance and the record go to show that none of the parties has got any interest to pursue the case and it is not advisable to keep the record pending any more as the case itself is pending since the year 1999 without any progress. As such it is hereby ordered that let a "NO DISPUTE AWARD" be and the same is passed and the reference is accordingly disposed of. Let the copy of the award be sent to the Ministry of Labour for information and needful.

MD. SARFARAZ KHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2004

का. आ. 342.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, ई. सी. एल. प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचाट (संदर्भ संख्या 48/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-22012/479/1999-आई. आर. (सीएम-II)]

एन. पी. केशवन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 30th December, 2004

S.O. 342.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 48/2000) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of M/s. Eastern Coalfields Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 30-12-2004.

[No. L-22012/479/1999-IR(CM-II)]

N. P. KESAVAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, ASANSOL

PRESENT :

Sri Md. Sarfaraz Khan, Presiding Officer.

Reference No. 48 of 2000

PARTIES :

The Agent,
Lachipur Colliery of M/s. Eastern Coalfield Ltd.,
P. O. Siarsole-Rajbari,
Distt. Burdwan (WB). . . . Management.

Vrs.

Sri Raju Bhuia, U. G. Trammer,
represented by General Secretary,
Koyala Mazdoor Congress,
Gorai Mansions, G. T. Road,
Asansol (West Bengal). . . . Workman.

REPRESENTATIVES :

For the Management : Sri P. K. Das, Advocate.

For the Workman : Sri Rakesh Kumar, General Secretary of K. M. C. Asansol.

Industry : Coal State : West Bengal

Dated : 25-11-2004

AWARD

In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Government of India through the Ministry of Labour vide its Order No. L-22012/479/99-IR (CM-II) dated 28-6-2000 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Lachipur Colliery of M/s. ECL in dismissing Sh. Raju Bhuia, U. G. Trammer from services is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. After receipt of the aforesaid order of reference summons were issued to the respective parties through the registered post. Having received the summons both the parties appeared in the Court and filed their separate sets of written statement in support of their respective claims.

3. In brief compass the case of the workman concerned as per his written statement is that Raju Bhuia, U. G. Trammer is the permanent employee of the company. The workman concerned absented from duty with effect from 21-9-97 to 8-12-97 on medical ground and the circumstances were such that he had to remain absent which was beyond his control.

4. The further case of the workman concerned is that though he did not reply the charge but he participated in the enquiry proceeding and explained about his illness due to which he could not attend his duty. He also submitted the treatment papers and the medical certificate granted by the Doctor in support of his illness but his request once the explanation were not considered by the management. Since the workman got his treatment at S. D. Hospital, Asansol, the medical certificate so granted by the Doctor of the said Hospital should have been considered but the workman failed to understand as to why the cognizance of that certificate was not taken by the enquiry officer.

5. It is also the case of the union that the punishment of dismissal for an unauthorised absence of about three months only is extreme one and the same is disproportionate to the nature of misconduct alleged against him. The management has violated the guidelines of CIL and ignored even the directives of the Supreme Court. Raju Bhuia belongs to Scheduled Caste Community and being illiterate is ignorant of the rules and regulations of the company and could not properly inform the management nor could take the help of the Co-worker. It is prayed that he may be reinstated in the service with all the full back wages and consequential benefits.

6. On the other hand the defence case of the management as per its written statement is brief is that the instant reference is bad in the eye of law and the very dispute is entirely a misconceived one.

7. The main case of the management is that the delinquent workman was charge-sheeted on 8-12-97 for his unauthorised absence from duty w.e.f. 21-9-97 as per the provisions of 17(n) of the Model Standing Order applicable to the establishment. The workman in spite of receipt of the charge sheet did not submit any reply and consequently a domestic enquiry was held to enquire the said charges levelled against the workman. The enquiry officer submitted his report against the workman holding his guilty for the alleged misconduct. The appointing authority considering the gravity of the charge established against the workman and considering his past record was pleased to pass an order of dismissal from his service.

8. It is denied by the management that the workman Raju Bhuia remained absent from his duty on medical ground under the compelling circumstances. The story of availing treatment at S. D. Hospital, Asansol is beyond the knowledge of the management. The dismissal of the workman is claimed to be just and proper in view of the gravity of the misconduct and the same is not disproportionate to the nature of misconduct proved.

9. It is lastly prayed that the workman concerned is not at all entitled to sick any relief sought for by the Tribunal and the action of the management be held to be justified.

10. The record goes to show that on 6-10-2004 a hearing on the preliminary point was made. The validity and fairness of the enquiry proceedings was not challenged by the concerned workman as he had duly participated in the enquiry proceeding. So the enquiry proceeding was held to be fair and valid and accordingly the date for final hearing of the dispute on merit were fixed. The final hearing was made on 25-11-2004 and the award was kept reserved for order.

11. In view of the pleadings of the parties and the materials available in the record I do found certain facts which are admitted by the respective parties so before entering into the discussion of the merit of the case I would like to mention the facts which are admitted one.

12. It is the admitted fact that Raju Bhuia, U. G. Trammer is the permanent employee of Lachipur Colliery of M/s. Eastern Coalfield Ltd.

13. It is the further admitted fact that delinquent workman was absent from his duty with effect from 21-9-97 to 8-12-97 without any prior permission and information of the management.

14. It is also the admitted fact that the workman was charge-sheeted on 8-12-97 for his unauthorised absence from duty w.e.f. 21-9-97 and admittedly he did not submit any reply to the chargesheet.

15. It is the next admitted fact that a domestic enquiry was conducted by an enquiry officer and the workman had duly participated in the enquiry proceeding and sufficient opportunity was given to defend himself and in the domestic enquiry the delinquent workman was held guilty as the only charge of an unauthorised absence

for the relevant period amounting to misconduct under clause 17(n) of the Model Standing Order was duly established. It is also apparent from the record that there is no chargesheet against the workman for being habitual absentee. It is the settled principles of law that the facts admitted need not be proved. Since these all the aforesaid facts are admitted one. So do not think proper to discuss the same in detail.

16. The management in para 1 of its written statement has taken the plea that the instant reference is bad in the eye of law as the same is not legally maintainable. It is also claimed that in view of the facts and circumstances of the case the dispute is misconceived one. But the aforesaid issue was neither raised nor pressed by the management during the course of hearing of the reference. The management has not examined any oral witness nor tendered even a chit of paper in support of its plea. As such I do not find any defect in the maintainability of this reference and the facts of the case very well comes under the purview of Industrial Dispute Act. The Govt. of India through the Ministry of Labour has rightly referred the dispute to this Tribunal for its adjudication and as such the issue is decided against the management.

17. On perusal of the records it transpires that none of the parties has examined any oral witness in support of their case rather they have filed some Xerox Copies of some documents. The management has filed the Xerox copy of the charge sheet. Copy of order of the dismissal and copy of the enquiry proceedings alongwith the reports of the enquiry officer. These all the documents are admitted one as the genuineness of the same has not been challenged by the union.

18. Likewise the union has also filed same xerox copy of the documents in support of its claim. Xerox copy of the charge sheet issued on 8-12-97, xerox copy of statements of Raju Bhuia given before the enquiry officer on 16-5-98, copy of the reply of the second show cause notice, copy of the report and findings of the enquiry officer and the last one is the copy of the mercy petition to allow the workman to join his duty. Most of the documents filed by the side of the union are common and the remaining documents are also admitted one as there is no any objection or challenge by the management.

19. It is clear from the enquiry proceedings and its report that the workman concerned had received the charge sheet and had participated in the proceedings. He has categorically admitted in his statement that he did not send any written information to the management about his illness due to being illiterate. He has further admitted that he was absent from his duty since 21-9-97 due to illness and during the relevant period he was undergoing treatment at S. D. Hospital, Asansol. Besides this the enquiry officer has also categorically mentioned in his findings that Sri Raju Bhuia remained absent from his duty since 21-9-97 and as per medical certificate issued by Superintendent, S. D. Hospital, Asansol he was under treatment of S. D. Hospital, Asansol since 20-9-97 as he is a patient of Cirrhofic type of liver.

20. Having gone through the entire facts, circumstance enquiry proceedings and the findings of the enquiry officer. I find that the workman concerned was admittedly absent from his duty since 21-9-97 to 7-12-97 i.e. more than two and half months continuously without any prior permission and information of the management. The enquiry officer has rightly held him guilty for an unauthorised absence under clause 17(1)(n) of the Model Standing Order applicable to the establishment and in view of the aforesaid prevailing facts the delinquent workman deserves some suitable punishment for the alleged misconduct proved as provided in the Model Standing Order applicable.

21. Now the only main point for consideration before the Court is to see as to how for the punishment awarded to the delinquent workman by the management is just on proper and is proportionate to the alleged nature of misconduct proved ?

22. Heard both the parties on the aforesaid point in question. It was admitted by the side of the workman that it is a simple case of an unauthorised absence only for two and half months and the absence from duty during the relevant period is duly explained and the reasons of absence has been supported with medical certificate have been found sufficient and relevant one by the enquiry officer and that is why the enquiry officer in his finding has not even whispered a word that the unauthorised absence was without any sufficient cause. The medical certificate granted by the Superintendent of the S. D. Hospital, Asansol goes to show that the workman concerned was suffering from the liver problem and that fact finds support in the findings of the enquiry officer as well. I find much force in the argument of the union side on this point and I am convince to hold that the workman was absent during the relevant period under the compelling circumstances beyond his control.

23. It was further submitted during the argument that the delinquent workman has get an unblamish record during his service tenure and since there has not been any complain of any misconduct either by unauthorised absence or any other sorts of. The management has also not charge sheeted him for habitual absence nor any chit of paper in this regard has been filed in the Court nor there is any pleading in this regard as well. So it can very well be concluded that it is the first offence of the workman which has been sufficiently explained and supported by the medical certificate indicating the compelling circumstance beyond the control of the concerned workman.

24. It was also argued out by the side of the union that it is a simple case of an unauthorised absence for a few months i.e. 2 month's 17 days, which can not be said to be gross misconduct. The attention of the Court was drawn towards the provision of the Model Standing Order where the extreme punishment prescribed is dismissal as per the gravity of the misconduct and it was claimed that the extreme penalty can not be imposed upon the workman in such a minor case of alleged misconduct of an unauthorised absence. The submission of the union side has got enough force on the factual point.

25. It has been several times clearly observed by the different Hon'ble High Courts and the Apex Court as well that before imposing a punishment of dismissal it is necessary for the disciplinary authority to consider socio-economic background of the workman is family back-ground, length of service put in by the employee, his past record of other surrounding circumstanes including the nature of the misconduct and lastly the compelling circumstance to commit the misconduct. These are the relevant factors which must have to be kept in mind by the authority at the time of imposing the punishment which is not done by the management in this case.

26. Admittedly the workman concerned is an illiterate man of Bhuyan by Caste who is the member of the Scheduled Caste being the member of the weaker section of the society. He is no doubt financially weak and poor who has suffered a lot for about eight years and he had never been gainfully employed any where during the period after his dismissal. The attention of the Court was drawn by the union since towards the provision of the Model Standing Order laid down under Clause 27(1) (page-15) where various minor punishment have been prescribed to be awarded according to the gravity of the misconduct. I fail to think as to why only maximum punishment available under the said clause should be awarded in the present facts and circumstance of the case. It has been observed by the Apex Court that justice must be tempered with mercy and that the delinquent workman should be given an opportunity to reform himself and to be loyal and disciplinary employee of the management. However, I am of the considered view that the punishment of dismissal for an unauthorised absence for about 2 and half months under the compelling circumstances and without any mala fide intention is not just and proper rather it is too harsh a punishment which is totally disproportionate to the alleged misconduct proved. Such a simple case should have been dealt with leniently by the management. In this view of the matter, I think a just and proper to modify and substitutes, the same exercising the power under Section 11(A) of the Industrial Disputes Act, 1947 to meet the ends of justice and as such the impugned order of dismissal of the concerned workman is hereby set aside and he is directed to be reinstated with the continuity of the service and in the light of the fact, circumstances and the misconduct for which the punishment of dismissal was imposed on the workman concerned, I think it appropriate that the delinquent worker be imposed a punishment of strict warning not to repeat the same misconduct in future. It is further directed that the workman will be entitled to get only 50% of the back wages which will serve the ends of justice. Accordingly it is hereby.

ORDERED

that let an award be and the same is passed. Secretary to send the copies of the award to the Ministry of Labour for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

MD. SARFARAZ KHAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2004

का. आ. 343.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 4/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/134/1999-आई. आर. (बी. II)]
सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 30th December, 2004

S.O. 343.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 4/2000) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur (U.P.) as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 30-12-04.

[No. L-12011/134/1999-IR(B-II)]
C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT/LOK ADALAT, SARVODAYA NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 4 of 2000

In the matter of dispute between :

Vice President,
Punjab National Bank Employees Congress,
S 581, Yashoda Nagar.
Kanpur.

AND

Punjab National Bank,
The Sr. Regional Manager,
Punjab National Bank,
59/29, Regional Office,
Birhana Road, Kanpur.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide notification No. L-12011/134/99-IR (B-II) dated 21-1-2000 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal :

> "Whether the action of the management of Punjab National Bank, Kanpur, in transferring Sri Ashok Kumar handicapped workman from Azad Nagar Branch to RSDC Branch is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to ?"

2. The present industrial dispute was identified to be decided through LOK ADALAT and for this purposes the case was taken up for discussions with the representative for the management as well as with the concerned workman and his representative. Various sittings in the case were held in the pretrial meetings of the LOK ADALAT and finally during the course of pretrial meeting held on 12-10-04, the representative for the management Sri V.K. Sinha submitted before the tribunal that the management is agreeable to resolve the grievance of the Union and will issue transfer orders by the date of final LOK ADALAT to be held by this tribunal on 16-10-04.

3. On 16-10-04 the case was again taken up in the final LOK ADALAT when representatives of the contesting parties appeared in the case. Management filed the transfer order No. RMK : STF : PF : 2944 dated 15-10-04 indicating therein that the services of the workman has been decided to be utilised at Branch Office Jageshwar, Kanpur of the Punjab National Bank.

4. Therefore from the above it is abundantly clear that now there remains nothing to be decided in the present dispute as the demand of the union has been resolved by the management of the Punjab National Bank. Hence the reference is decided to be in terms of the Bank's order dated 15-10-04 which has been duly accepted by the workman without any demur.

5. Accordingly, it is held that now there remains no dispute between the parties and the demand of the union stands fully satisfied. Result is that the reference is liable to be decided in terms of order dated 15-10-04 of the management and it is decided accordingly.

16-10-04

SURESH CHANDRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2004

का. आ. 344.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.-2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 41/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/130/1998-आई. आर. (बी. II)]
सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 31st December, 2004

S.O. 344.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 41/99) of the Central Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi No. II as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Central Bank of India, and their workmen which was received by the Central Government on 30-12-2004.

[No. L-12012/130/1998-IR(B-II)]
C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, RAJENDRA BHAWAN, GROUND FLOOR, RAJENDRA PLACE, NEW DELHI

I. D. No. 41/99

R.N. Rai, Presiding Officer

In the matter of :

Sh. Nanak Chand,
E-157, New Ranjit Nagar,
New Delhi-08.

VERSUS

Central Bank of India,
The Regional Manager, CBI,
Regional Office-A,
IMA House, IP Marg,
New Delhi-01.

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-12012/130/98 IR-(B-II) Central Government Dt. 27-1-1999 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder :

> "Whether the action of the management of CBI in dismissing Sh. Nanak Chand, peon from service from 26-8-93 is just fair and legal ? If not what relief the concerned workman is entitled to, and from what date ?"

The claimant has filed statement of claim. In the statement of claim, it has been stated that the workman was initially appointed as a temporary part time safai Karamchari in Central Bank of India on lump sum wages of Rs. 100 per month. That subsequently in terms of a settlement reached between the management of the Central Bank of India and their workmen represented by Central Bank Staff Union (Delhi), for regularisation of services of temporary part time safai Karamchari as permanent part time safai Karamcharis, the services of the workman were regularised as a permanent safai Karamchari on one-third of the scale of wages of a member of subordinate staff at Bank's Ram Tirath Nagar, New Delhi Branch w.e.f. 20-1-84 vide appointment letter dated 16-2-84.

That at the time of being issued the appointment letter dated 16-2-84, the workman was required to submit an application on the bank's prescribed form together with documentary proof of his educational qualifications. Accordingly the workman had submitted the required application on the prescribed form dated 24-2-84.

That at the time of his permanent appointment as a part time safai Karamchari w.e.f. 20-1-84, the educational qualification of the workman was 5th class pass in support of which he had submitted his school leaving certificate dated 29-7-81 from Baba Saheb Ambedkar Madhyamik Vidyalaya, New Delhi in which he was studying in 6th class at the time he left the said school.

That as the date of birth of the workman was wrongly entered in the school records as 6-1-67 instead of the actual date of his birth i.e. 19-10-63, he had submitted his horoscope in support of his actual date of birth to the bank, which was accepted by the bank and accordingly, the date birth of the workman was entered as 19-10-63 in his service record on the basis of his horoscope.

That after the workman had worked for a few years as a permanent part time safai Karamchari on one-third of the scale of wages he was brought on one-half of the scale wages of a member of subordinate staff as per his seniority among the permanent part time safai Karamcharis drawing one-third of the scale wages in Delhi.

That on coming to know in September, 1990 that the bank was going to make appointments in the posts of full time peons from amongst the existing permanent part time safai Karamcharis who were eligible for such appointment, the workman also submitted an application for such appointment and on being found successful in the interview held by the bank on 10-12-90, he was appointed as a full time on probation for six months by a letter dated 7-1-91 issued by the zonal office of the bank, New Delhi.

That when after his appointment as a full time peon w.e.f. 21-1-91, the workman was working at Lajpat Nagar, New Delhi branch of the bank, he was given a memo dated 15-10-91 issued by bank's Regional Manager, Regional Office-A, New Delhi, alleging therein that the workman had submitted a false/forged certificate in connection with his services in the bank.

That on receipt of the above memo dated 15-10-91, the workman requested the bank to furnish to him a photostat copy of the alleged false/forged school leaving certificate, which was referred to in the said memo, but the management declined the above request of the workman by a letter dated 13-11-91, stating the original of the said school leaving certificate must be with himself.

That without any thing more happening after the banks above letter dated 13-11-91, the bank served on the workman a charge sheet dated 10-9-92 simultaneously instituting a departmental enquiry against him by an order in the said charge sheet itself and without giving him opportunity of submitting his explanation as to the charge framed against him in the said charge sheet.

That the departmental enquiry which was commenced by the equiry officer on 18-1-92 was concluded on 30-1-93, followed by submission of their respective written arguments of the parties to the enquiry officer.

The charge sheeting disciplinary authority who initiated disciplinary action against the workman vide charge sheet dated 10-9-92 did not comply with the legal requirement of clause 19.1 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66 inasmuch as that he instituted enquiry against the workman by an order in the charge sheet itself without giving to the workman any opportunity of giving his explanation to the charge framed against the workman by him.

The management has not filed written statement. The management appeared on 16th May, 2004 but did not file written statement and even did not file application to set aside the ex parte order. The last opportunity was given by the predecessor court to file written statement but it was not filed. The cost imposed was not paid recalling for ex parte order. The predecessor court on 10-06-2002 closed the opportunity of the management for filing the written statement and ordered that the case will proceed ex parte. It indicates that the management has been present previously and has filed application for recalling the ex parte order, cost of Rs. 250 was imposed but the management did not pay the cost and filed written statement so the opportunity for filing of the written statement was closed and the case was again ordered to proceed ex parte. The representative was present on 22-01-2004 but no written statement was filed. The case has been proceeded ex parte. Heard arguments from the

side of the workman applicant. It was submitted from the side of the workman applicant that the management has not filed written statement despite several opportunities given. The management intends to harass the workman applicant. There is nothing on the record to disbelieve the pleadings of the statement of claim of the workman applicant.

From perusal of the record, it transpires that the enquiry was held against the workman applicant and he was dismissed thereafter but there is no written statement to repudiate the pleadings of the statement of claim. As such, enquiry is not fair and according to the principles of natural justice. The workman applicant has made out his case. The workman has filed affidavit. His affidavit will prevail as no counter affidavit has been filed by the management.

The reference is replied thus :

The action of the management of the CBI in dismissing Sh. Nanak Chand, peon from service from 26-8-93 is neither just nor fair and nor legal. The workman applicant is entitled to be re-instated w.e.f. 26-08-1993 alongwith 100% back wages. The management is directed to re-instate the workman applicant within one month after the publication of the award and pay him back wages as ordered. In case of default, the workman will be entitled to get interest @ 12% per annum on the entire back wages.

The award is given accordingly.

Dt. 28-12-2004 R.N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2005

का. आ. 345.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नेशनल एल्यूमिनियम कं. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के पंचाट (संदर्भ संख्या 35/02) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-2004 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-43012/15/2001-आई. आर. (विविध)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd January, 2005

S.O. 345.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 35/02) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Bhubaneswar as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of National Aluminium Co. and their workman which was received by the Central Government on 30-12-04.

[No. L-43012/15/2001-IR(M)]
B.M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, BHUBANESWAR

PRESENT :

Shri N.K.R. Mohapatra, OSJS,
Presiding Officer, C.G.I.T.-cum-Labour Court,
Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 35/2002

Date of Passing Award—30th November 2004

BETWEEN :

The Management of the General
Manager, Project, (IAPL), NALCO,
Nalco Nagar, Angul,
Orissa-759 145 ... 1st Party-Management

AND

Their Workman Shri Basanta Kumar Nayak,
C/o. Benudhar Nayak, SBI Main Branch,
Unit-I, Bhubaneswar, Orissa. ... 2nd Party-Union.

APPEARANCES :

P.K. Rath, Manager, Law ... For the 1st Party-Management

Prabhat Kr. Sahoo, Advocate ... For the 2nd Party-Workman.

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of Powers conferred by Clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) have referred the following dispute for adjudication vide their Order No. L-43012/15/2001/IR (M), dated 06/02/2001 :

"Whether the action of the management of NALCO (Smelter), Angul, by not absorbing Shri B.K. Nayak along with other employees of IAPL as per list of Annexures I & II is justified ? If not, what relief the disputant is entitled to ?"

2. Consequent upon the above reference the following three Issues were framed.

ISSUES

(i) Whether the disputant is a workman under the definition of the Industrial Disputes Act ?

(ii) Whether the action of the Management of NALCO (Smelter), Angul by not absorbing Shri B.K. Nayak, along with other employees of IAPL, as per the list is justified ?

(iii) If not, to what relief the disputant is entitled to ?

But in the midst of hearing the 1st Party-Management NALCO moved a petition challenging the jurisdiction of this Tribunal by placing reliance on a finding of the Hon'ble High Court of Orrisa in Writ Petition (C) No. 3425/2002 disposed of on 4-12-2002. In support of the contention in reliance was also placed on a letter No. 11(21)/2002-Met.I, dated 23-5-2002 issued by the Government of India, Ministry of Coal & Mines, Department of Mines. Pursuant to the above petition the following Additional Issue was framed on 5-11-2004 and the same was taken up as a preliminary issue and hence the Award.

ADDITIONAL ISSUE

(iv) Whether the Reference is maintainable ?

3. Admittedly, International Aluminium Products Ltd. was merged with the NALCO some times during the year 2001. It is alleged by the 2nd Party-Workman that before the above merger, he was working as a caretaker in the company guest house of IAPL at Bhubaneswar but while taking over the IAPL, the NALCO did not deliberately consider him as an employee of the erstwhile IAPL Company and in consequence refused employment though others were taken as per the list furnished by the merger company.

4. The 1st Party-Management, NALCO on the other hand alleged that, there was no guest-house at IAPL at Bhubaneswar and therefore the question of the workman working there does not arise. In regard to the present petition relating to the jurisdiction of this Tribunal it is also submitted by the Management of NALCO that, in view of the findings of Hon'ble Supreme Court in Steel Authority of India Ltd. & Others-Versus-National Union Water Front Workers & Others, reported in AIR (2001) SC 3527 followed by a finding of Hon'ble High Court of Orissa in Writ Petition (C) No. 3425/2002, under section 10 of the Industrial Disputes Act the Central Government can not be the appropriate Government in respect of NALCO and as such the reference is bad.

5. Referring to a plethora of earlier decisions the Hon'ble Apex Court while dealing with a similar matter, have observed in relation to Section 10 of the Industrial Disputes Act and Section 2 of the C.L.R.A. Act in the case between Steel Authority of India Limited & Others *Versus* National Union Water Front Workers & Others reported in AIR (2001) SC 3527 that where the authority to carry on any industry for or on behalf of the Central Government is conferred with a Government company any undertaking by the statute under which it is created no further question arises as to who would be the appropriate Government. But in the absence of a statute under which a company is created the question is to be examined on the facts and circumstances of each case. Their lordships have observed at Para-46 of the above judgement that, in the case of a Central Government company/undertaking, an instrumentality of the Government, carrying on an industry, the criteria to determine whether the Central Government is the appropriate Government within the meaning of the CLRA Act, is that the industry must be carried on by or under the authority of the Central Government and not that the company/undertaking is an instrumentality or an agency of the Central Government for purposes of Article 12 of the Constitution; such an authority may be conferred either by a statute or by virtue of relationship of principal and agent or delegation of power and this fact has to be ascertained on the fact and the circumstrances of each case. Besides while considering a similar question as who would be the appropriate Government in respect of the NALCO the Hon'ble High Court of Orissa in Writ Petition (C) No. 3425/2002 have also held in the light of the observation of the Hon'ble Supreme Court, that in respect of NALCO the Central Government can not be the appropriate Government either under Section 10 of the Industrial Disputes Act or under Section 2 (1)(a) of the CLRA Act, 1970. Added to all these the Government of India, Ministry of Coal & Mines, Department of Mines, vide their Letter No. 11(21)/2002-Met.I, dated 23-5-2002 have also issued a letter to the Chairman-cum-Managing Director, NALCO, Bhubaneswar clarifying that "the State Government will be the appropriate Government for the NALCO Smelter Expansion Project, Angul and for the employees of the marketing establishment, both under the Industrial Disputes Act and the Contract Labour Act, 1970, the Central Government would, however, be the appropriate Government for the employees of the establishment of NALCO in mines and its precincts and also for the workers engaged in the major Ports by NALCO under the Industrial Disputes Act and the Contract Labour Act, 1970". Since, in the instant case the workman claims that, he was earlier engaged as a caretaker in the guest house of the erstwhile IAPL which was subsequently merged with NALCO, it follows from the above discussion that the Central Government is not the appropriate Government in respect of NALCO (Smelter) Angul as held by the Hon'ble Orissa High Court in W.P. (C) 3425/2002 and as such the reference is found to be bad. Accordingly, Issue No. IV is answered.

6. In view of the above findings on Issue No. IV there is no need of separate findings on other Issues. The reference is answered accordingly.

N.K.R. MOHAPATRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2005

का. आ. 346.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु मिनरल्स लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक

अधिकरण, चेन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या 94, 428, 432, 433, 457, 458, 459/01) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-04 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29012/7,6,8,9,10,11/97-आई. आर. (विविध)]
[सं. एल-29012/175/98-आई. आर. (विविध)]
बी.एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd January, 2005

S.O. 346.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. Nos. 94, 428, 432, 433, 457, 458, 459/01) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Tamil Nadu Minerals Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 30-12-04.

[No. L-29012/6,7,8,9,10,11/97-IR(M)]
[No. L-29012/175/98-IR(M)
B.M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHENNAI

Monday the 26th April, 2004

PRESENT : K. Jayaraman, Presiding Officer

S. No.	TNID No.	I.D. No.	Reference No. & Date	I Party/ Workman	II Party/ Management
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	44/99	94/2001	L-29012/175/98 IR(M) 01-03-99	Sri R. Paul Vincent	The Chairman & Managing Director, Tamil Nadu Minerals Ltd. Chennai
2.	32/97	428/2001	L-29012/7/97 IR(Misc) -14-05-97	Sri R. Dhass	The Divisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd., Salem
3.	40/97	432/2001	L-29012/10/97 IR(Misc) 19-06-97	Sri K. Perian-nan	The Divisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd., Salem
4.	41/97	433/2001	L-29012/9/97 IR(Misc) 19-06-97	Sri I. Kolan-daiswamy	The Divisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd., Salem
5.	104/97	457/2001	L-29012/6/97 IR(Misc) 24-10-97	Sri S. Arumugam	The Divisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd., Salem
6.	105/97	458/2001	L-29012/8/97 IR(Misc) 24-10-97	Sri I. Mathaiyan	The Divisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd., Salem
7.	106/97	459/2001	L-29012/11/97 IR(Misc) 24-10-97	Sri K. Selvaraj	The Divisional Manager, Tamil Nadu Minerals Ltd. Salem

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14) of 1947), between the Mangement of Tamil Nadu Minerals Ltd. and their workmen).

APPEARANCES :

For the Claimant : M/s. D. Hariparanthaman, V. Ajoy Khose, P. Vijendran, Advocates

For the Management : M/s. Muthumani Doraisami, Advocate

AWARD

I.D. No. 94/2001

The Central Government, Ministry of Labour vide order No. L-29012/175/98/IR(M) dated 01-03-1999 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication. The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 44/99 and after the constitution of this Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 94/2001. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

> "Whether the action of the management of Tamil Nadu Minerals Ltd. in dismissing Shri R. Paul Vincent from services w.e.f. 29-12-94 is legal and justified ? If not to what relief the workman is entitled" ?

3. The allegations of the Petitioner in the Claim Statement are briefly as follows :

The Petitioner was employed as a semi-skilled worker in the Yelikkaradu quarry in Mettur Dam. The conditions of service of workmen in Yelikkaradu quarry is pathetic. Though about 250 workmen were employed

in production of granite stones in Yelikkaradu quarry, no workman was permanent. When the workmen were continuously working in production from its inception, they were not made permanent. There was a settlement under Section 12(3) on 7-11-89 before the RLC (Central) Chennai regarding the quantum of bonus for 1988-89. When the disbursement took place, the Respondent/ Management only paid bonus to chiselemen and not the ex-gratia as provided in settlement to chiselmen. This led to strike by all chiselemen from 8-11-89. Then the dispute was taken before RLC and on his advice on 15-12-89 the workmen should withdraw the strike and report for duty on 16-12-89. They reported for duty on 16-12-89. The management has refused employment to chiselmen. When the chiselmen were denied employment, other workmen were pressurized to do the work of chiselmen. But the other workmen could not do the work of chiselmen because it was highly skilled work. Therefore, the management suspended three workmen on 8-2-90 who were taking leadership positions for the solidarity shown in favour of the chiselmen. When the management was not successful in their pressure tactics to make the workmen to carry out the work of chiselmen even after the suspension of three workmen, they went on harassing the workmen on various ways. Even for the workmen who suffered injuries in accident which arises out of and in the course of employment, injury leave was denied and the workmen were marked absent. When this was protested on 22-5-90, the management was still more aggressive and placed 15 workmen including the Petitioners under suspension on 24-5-90. Further, the management falsely implicated in a criminal case of assault causing simple injuries. The criminal case was that as a retaliation to the suspension of 15 workmen and others had beaten the seven staff. This is the subject matter of disciplinary action also. Six months after suspension, a charge memo dated 4-1-91 was served making allegations that the group of 13 workmen including the Petitioner had beaten the seven staff with sticks and also caused damage to the property. The criminal trial ended in acquittal by a judgement dated 10-7-91. But the management issued another charge memo dated 6-6-92 in which it was alleged that the 15 workmen and also others had beaten the seven staff with pungam sticks causing injuries to them and also causing damage to the properties. This time instead of 13 persons, 15 persons were issued with charge sheet. Even after their explanation, the departmental enquiry was ordered to be conducted. In the charge memo, it was not specifically stated what were misconducts under the clause mentioned in the charge memo. The charge sheet is vague and the Petitioners were denied opportunity to put forth their explanation and defence specifically. The enquiry conducted against the Petitioner and others was not fair and he was not given reasonable opportunity and the same is violative of principles of natural justice. The enquiry was conducted at Madras and not at Mettur and there was no valid reason to hold at Madras instead of Mattur. The Respondent/Management has been represented by its representative who is a B.L. graduate and legally trained person. When the Petitioners asked for assistance from Trade union, it was declined by the Enquiry Officer. The conduct of the enquiry is undue hastily and is an unfair labour practice. Though the notice of enquiry provided a schedule and it was stated that there would be an independent enquiry for each workman, the schedule given by the management was breached by itself. The FIR and wound certificates pertaining to other employees were not marked through author or any of the persons concerned with the documents. The management has no jurisdiction to proceed departmentally after the acquittal by the criminal court and therefore, they are estopped from conducting the departmental enquiry. The findings of the Enquiry Officer is cryptic. Further, the witnesses who have examined in the enquiry have not given legal evidence to sustain the guilt of an individual. The Enquiry Officer relied on the materials which are not marked in the enquiry rendering his findings perverse. There was no report from any of the seven staff who were alleged to have been assaulted except the FIR registered with the police. The FIR was registered against 13 persons but the charge memo was issued in the domestic enquiry against 15 persons. The charge sheet makes allegations about causing of grievous hurt but the wound certificates marked in the enquiry states that injuries were simple. The charge sheet makes the allegation that properties were damaged but the FIR did not say so. The reasoning given by the Enquiry Officer is perverse. Further, even though a common charge sheet against 15 workmen was issued, even though a common finding of guilt against 15 persons, reinstating of seven workmen out of 15 and dismissing the eight workmen including Petitioners is a clear case of discrimination. When the charges and findings against all the workmen are same, there is justification or reason to reinstate some of the workmen and denying reinstatement to others including the Petitioners. Further, the order of dismissal from the date of suspension for which there is no provision in the Standing Orders. Therefore, the dismissal is withiout any jurisdiction. Hence, for all these reasons, the Petitioner prays that this Tribunal may be pleased to pass an award directing the Respondent to reinstate the Petitioner with continuity of service and other attendant benefits with costs.

4. As against this, the Respondent in its Counter Statement alleged that though it is admitted that the workmen in this case was semi-skilled worker who was paid on daily rated wages and the non-employment of the Petitioner was consequent upon the order of dismissal passed against pursuant to the disciplinary proceedings initiated according to law. The chiselmen engaged by the respondent in various quarries are not the direct employees of the respondent. Hence, the chiselmen did not report

for work from 18-11-89 in Yellikkaradu quarry. Since the chiselling and quarrying work were affected, the regular workers of the respondent management were directed to do the work. The workers except those affiliated to the INTUC, have refused to do the chiselling work. Even the INTUC workers who came forward to do the chiselling work obstructed from doing the work and were threatened by a section of workers and hence for want of proper security, they did not do the chiselling work. Therefore, the management informed that their refusal to do the job would result in being marked as absent for the half a day. Consequent upon this incident, the workers gheraoed the mines staff till 9.00 pm. and did not allow them to move apart from threatening the officials with dire consequences. There was a continuous labour unrest in the quarry as a chain reaction. The workers raised the issue of attendance to one worker, who reported for work on 22-5-90 after being absent. When the mines foreman insisted on the production of medical certificate for the period of absence, the workers mobbed the mines foreman and threatened him with dire consequences. They refused to do the work and indulged in obstructing others from reporting for work. For this, the petitioners and 14 others were suspended pending enquiry on 24-5-90. Suddenly, the workers mobbed the mines office with sticks and forcibly broke open the windows and closed doors. Further, the workers violently assaulted the Divisional Manager, Mines Foreman, Minesmate, other staff and operators with lethal blows causing bleeding injuries. The officials were hospitalised with bleeding injuries for a long time as inpatients. The Petitioner was one of the workers who participated in the gruesome acts of violence. For this, domestic enquiry was conducted for all the charges mentioned above. In the domestic enquiry, the petitioner and others were given full opportunity to cross-examine the witnesses and to put forth their case. The order passed in the domestic enquiry is legal, valid and it was proceeded by a duly conducted domestic enquiry in which the petitioner was given full and fair opportunity to participate and to put forth his case. The management cannot be blamed for taking action against employees who indulged in acts of indiscipline. It is false to allege that the workmen also suffered injuries in accident arising out of and in the course of employment. It is well settled that departmental proceedings and criminal trial can be conducted side by side and the respondent is well within the rights to impose the punishment commensurate with the gravity of the misconduct proved irrespective of the verdict of criminal court. The acquittal by criminal court does not prevent the respondent from proceeding with enquiry and arriving at its own conclusion and imposing appropriate punishment based on misconduct. The decree of capability of each worker varies from person to person notwithstanding the uniformity of charges and hence the allegation of discrimination is untenable on facts and unsustainable in law. Unequal cannot be treated equally and workers whose involvement in the misconduct varies depending upon the nature of involvement cannot be imposed the same penalty. The imposition of penalty is solely relatable to the decree of capability in respect of the charges proved against them. For all these reasons, the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs.

5. In these circumstances, the points for my determination are :

(i) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ?"

I.D. No. 428/2001 :

6. The Central Government, Ministry of Labour vide order No. L-29012/7/97/IR(M) dated 14-05-1997 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication. The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 32/97 and after the constitution of this Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 428/2001.

7. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

"Whether the action of the management of M/s. Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam P.O. Salem District is justified in dismissing the services of Shri R. Dhass w.e.f. 24-5-90 ? If not what relief the workman is entitled to ?"

8. The Petitioner in this dispute has raised more or less similar allegations as that of made in the I.D. No. 94/ 2001.

9. The respondent in this dispute also has raised similar contentions as that of in I.D. No. 94/2001.

10. In these circumstances, the points for my determination are :

(i) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?"

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ?"

I.D. No. 432/2001 :

11. The Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L-29012/10/97/IR(M) dated 19-06-1997 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication. The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 40/97 and after the constitution of this Central

Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 432/2001.

12. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

"Whether the action of the management of M/s. Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam P.O. Salem District is justified in dismissing the services of Shri Periannan K. w.e.f. 09-02-90 ? If not to what relief the workman is entitled ?"

13. The Petitioner has raised more or less similar allegations as that of made in the I.D. No. 94/2001.

14. The Respondent also has raised similar contentions as that of in I.D. No. 94/2001.

15. In these circumstances, the points for my determination are :

(i) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ?"

I.D. No. 433/2001 :

16. The Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L-29012/9/97/IR(M) dated 19-06-1997 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication. The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 41/97 and after the constitution of this Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 433/2001.

17. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

"Whether the action of the management of M/s. Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam P.O. Salem District is justified in dismissing the services of Shri I. Kolandaiswamy w.e.f. 24-5-90 ? If not to what relief the workman is entitled ?"

18. The Petitioner has raised more or less similar allegations as that of made in the I.D. No. 94/2001.

19. The Respondent also has raised similar contentions as that of in I.D. No. 94/2001.

20. In these circumstances, the points for my determination are :

(i) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ?"

I.D. No. 457/2001 :

21. The Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L-29012/6/97/IR(M) dated 24-10-1997 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication. The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 104/97 and after the constitution of this Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 457/2001.

22. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

"Whether the action of the management of M/s. Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam P.O. Salem District is justified in dismissing the services of Shri S. Arumugam w.e.f. 24-5-90 ? If not to what relief the workman is entitled ?"

23. The Petitioner has raised more or less similar allegations as that of made in the I.D. No. 94/2001.

24. The Respondent also has raised similar contentions as that of in I.D. No. 94/2001.

25. In these circumstances, the points for my determination are :

(i) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ?"

I.D. No. 458/2001 :

26. The Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L-29012/8/97/IR(M) dated 24-10-1997 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication. The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 105/97 and after the constitution of this Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 458/2001.

27. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

"Whether the action of the management of M/s. Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam, P.O., Salem District is justified in dismissing the services of Shri I. Mathaiyan w.e.f. 24-5-90 ? If not to what relief the workman is entitled ?"

28. The Petitioner has raised more or less similar allegations as that of made in the I.D. No. 94/2001.

29. The Respondent also has raised similar contentions as that of in I.D. No. 94/2001.

30. In these circumstances, the points for my determination are :

(i) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ?"

I.D. No. 459/2001 :

31. The Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L-29012/11/97/IR(M) dated 24-10-1997 has earlier referred this industrial dispute to Tamil Nadu State Industrial Tribunal for adjudication. The Tamil Nadu State Industrial Tribunal has taken the same on its file as I.D. No. 106/97 and after the constitution of this Central Govt. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, the said industrial dispute was transferred to this Tribunal and after the receipt of records of this dispute, it was renumbered as I.D. No. 459/2001. The schedule mentioned dispute in the order of reference is hereunder :

"Whether the action of the management of M/s. Tamil Nadu Minerals Ltd. Mettur Dam, P.O,. Salem District is justified in dismissing the services of Shri K. Selvaraj w.e.f. 4-6-90 ? If not to what relief the workman is entitled ?"

32. The Petitioner has raised more or less similar allegations as that of made in the I.D. No. 94/2001.

33. The Respondent also has raised similar contentions as that of in I.D. No. 94/2001.

34. In these circumstances, the points for my determination are :

(i) "Whether the action of the Respondent/ Management in dismissing the Petitioner from service is legal and justified ?

(ii) "To what relief the Petitioner is entitled ?"

Point No. 1 :

35. All these seven industrial disputes are tried jointly, in view of the joint memo filed by both sides. In all these cases, after the disputes have been numbered, the Petitioners contended that the domestic enquiry held against them were not just and proper and on the preliminary issue, this Tribunal has passed an order that the domestic enquiry held by the Respondent/ Management was not just and proper and therefore, the Respondent/Management was order to conduct enquiry before the Tribunal and as such the Respondent/ Management has examined two witnesses and the Petitioners have examined three witnesses on their side.

36. The case of the Respondent/Management is that during 1989, a tri-partie agreement under section 12(3) has been arrived at on 7-11-89 and as per that terms, ex-gratia payment of Rs. 500 was agreed to be paid by the Respondent/Management to workmen during Deepavali, pending approval of the Govt. When the disbursement took place, the management has clarifed that chiselmen were not entitled for the ex-gratia and this was protested by them and the chiselmen in Elikkaradu quarry refused to commence work, protesting for non-payment of ex-gratia to them and this was affected the production. But the management decided to go in alternative on 25-11-89. Subsequently, the dispute was taken to Regional Labour Commissioner and the Regional Labour Commissioner (Central), Chennai gave an advice on 15-12-89 that the workmen should withdraw the strike and report for duty on 16-12-89 and the dispute regarding the ex-gratia would be sorted out through conciliation. But, according to the workmen, the Respondent/Management refused to employ the chiselmen when they reported for duty on 16-12-89. When the chiselmen were denied employment, other workmen were pressurized to do the work of chiselmen. According to the Petitioner/Workmen., the work of chiselmen being highly skilled in nature, the other workmen could not do the same. Therefore, the management suspended three workmen dated 8-2-90, who were taking leadership position in the solidarity shown in favour of chiselmen. When the management was not successful in their pressure tactics, even after the suspension of three workmen, they went on harassing the workmen on various reasons. According to the Petitioners, even for the workmen suffered injuries which arose out of and during the course of employment, injury leave was denied and the workmen were marked absent. When this was protested on 25-2-90, the management was still more aggressive and 15 workmen including the Petitioners herein were placed under suspension on 25-4-90 and they also given complaint against the Petitioner/Workman and a criminal case of assault causing simple injury etc. According to the management the workmen and others beaten up seven staff of the management. The same was the subject matter of the disciplinary enquiry also. After six months of suspension, the charge memo dated 4-1-91 was served against the Petitioner. Not satisfied with the explanation submitted by the Petitioners, departmental enquiry was ordered by the Respondent/Management. But, in the criminal case against the Petitioners, they were acquitted and even after that the management has taken departmental action and proceeded with the enquiry. Though seven Petitioners/Workmen were involved in this case, only against five workmen action was taken with regard to the incident on 22-5-90 and 24-5-90. With regard to Mr. K. Periannan and Mr. K. Selvaraj namely the Petitioners in I. D. Nos. 432/2001 and 459/2001, charges were framed for the incidents on 27-12-1989, 28-12-1989, 09-11-1990, 21-11-1990 and 15-12-1990. Since all the

persons were employed by the Respondent/Management as semi-skilled workers and skilled workers, these seven cases were jointly tried and a common evidence was taken in I. D. Nos. 94/2001. Though the management has examined two witnesses, the two witnesses even though have given evidence with regard to the incident took place on 22-5-90 and 24-5-90, they have not stated anything about the alleged occurrence that had taken place on 27-12-1989, 28-12-1989, 09-11-1990, 21-11-1990 and 15-12-1990. Further, on the side of the Respondent/ Management, no explanation was given for non-examination of any witness to speak about the incident that alleged to have been taken place on 27-12-1989, 28-12-1989, 09-11-1990, 21-11-1990 and 15-12-1990. Even with regard to the incident that alleged to have been taken place on 22-5-90 and 24-5-90, the Respondent/ Management alleged out of 15 persons against whom suspension orders have been issued, on 24-5-1990 only 13 persons were present and they approached them for serving the same. At the first instance, they have refused to receive the same and subsequently, they have received the same at 12.00 noon. Under the leadership of Mr. I. Kolandaisamy, they have broken sticks of Pungan tree and formed an unlawful assembly and attacked the officers of the management and staff of the management and they threatened the officers of the management to withdraw the suspension order against the 15 persons and failing which they threatened that they would endanger the life of the Divisional Manager Mr. Mohan Raj and others. But, surprisingly the management even though alleged that only 13 persons and other workmen were involved in that incident, they have taken departmental action against 15 persons. But they have not stated any reason for taking action against the remaining two persons and further, they have not given any evidence with regard to how they have involved in the incident on 24-05-1990. Further, from the documents produced by either side, it is clear that criminal action was taken only against 13 persons, but, surprisingly, they have taken action against 15 persons in the departmental enquiry. Apart from that to see as to whether the management has established the charges against the Petitioners, I find it is not so. Even though the management has examined one Mr. Selvin, the Senior Foreman and also one Mr Mahalingam, Minesmate during that period, they have not established by their evidence how the incident has taken place and how the Petitioners have involved in the incident. They alleged that the Petitioners and other workers namely 100 persons have threatened the officers of the management to withdraw the suspension order issued to them and they also threatened to endanger the life of Divisional Manager and other staff members and it is the evidence of the management witnesses that the Petitioners and others have broken the branches of Pungam tree and attacked the staff members and they have not given any details with regard to the injury they have caused to them. Though the management has produced wound certificates given by the Doctor, it was not established before this Tribunal through a medical evidence. Further, the witnesses examined on the side of the management have not stated how the injuries have caused to them and by whom they were caused, except the allegation that the Petitioners and other workers have pelting stones and have caused injuries. They have not given any details how the wounds have caused to them by the Petitioners. Further, the management witnesses alleged that due to these injuries, they have fallen on the ground and further it is their evidence that they have caused grievous injuries to them. But from their evidence itself, it is clear that the injuries are minor in nature and the Petitioners have chosen only because they have been issued with suspension order.

37. At this juncture, the learned counsel for the Petitioner argued that the First Information Report with regard to wound certificate of employees were not marked through the author or the persons concerned with the documents and the said documents were marked in the manner not known to the law. Further, even for the same incident, the management has filed a criminal complaint, under such circumstances, the management has no jurisdiction to proceed departmentally after the acquittal by the Criminal Court. They having waited for the completion of criminal trail, the management is estopped from conducting the departmental enquiry. Even though there is a consensus of judicial opinion on a basic principle that proceedings in a criminal case and departmental proceedings can go on simultaneously except where departmental proceedings and criminal case are based on the same set of facts and the evidence in both the proceedings is common. Basis for this proposition is that proceedings in criminal case and departmental proceedings operate in distinct and different jurisdictional areas. In this case, the departmental proceedings and the criminal case are based on the same facts and both the proceedings is common when they are being and therefore, the management is estopped from conducting the departmental enquiry. Any how, there is no iota of evidence to prove that the Petitioners were involved in the incident alleged to have been taken place on 22-5-90 and 24-5-90 except the fact that they have not served with suspension order. Even though the MW1 and MW2 have deposed that the incident alleged to have taken place on 22-5-90, their evidence is contradictory and there is no specific allegation against individual petitioners. Their allegation is bald without any proof and without any corroboration. Under such circumstances, it cannot be said that the management has proved the charges framed against the Petitioners. Further, on behalf of the Petitioners, it was argued that in the FIR and also in the evidence of MW1 and MW2, they have not given the details as to which workman beat which person and they have also not stated which person caused which injury. Except the document

of FIR, there is no other proof to show that the incident has happened as alleged by the Respondent/Management. Though the management has alleged that properties were damaged, even in the FIR they have not stated this vital aspect with regard to damages of the property. In this case, it is the evidence of the management that large number of persons including the Petitioners have caused the incident. There is no clear proof against the Petitioners. Further, though the management has charge sheet against 15 persons, they have reinstated seven workmen and dismissed the eight workmen including the Petitioners, which is a clear case of discrimination. It is also discriminatory in picking and choosing six workmen out of fifteen is still worse and practicing discrimination as unfair labour practice under the Industrial Disputes Act and therefore, the discriminatory action would render the dismissal illegal and unlawful. Further, on behalf of the Petitioners it is contended that out of 15 persons who have been charged by the Respondent/Management, against six persons no order of dismissal was passed and only against the nine persons, the order of dismissal was passed and the above said six person are continuously in employment. Even out of the nine persons, three persons were given employment subsequently. S/Shri Shanmugam, Chandran and Kunjappan have been given employment by reinstating them and refixing their pay by the Respondent/ Management and hence it is a clear case of discrimination and therefore, the order of dismissal passed against the Petitioners are to be set aside. The learned counsel for the Petitioner relied on the rulings reported in 2001 3 LLN 269 Coimbatore and Periyar, District Dravida Panchalai Thozilalar Munnettra Sangam *Vs.* Management of Pionner Mills Ltd. and Another wherein the Division Bench of the High Court has held that "the main submission of the counsel for the appellant is that with regard to first charge sheet dated 18-10-79, and findings on that basis, 11 out of 9 workmen were taken back. In reference to the 2nd charge sheet dated 4-12-79, wherein two workmen namely R. Damodaran and Kolandaiswamy were involved, Kolandaiswamy was let off with a minor punishment of suspension. The management having reinstated 9 workers involved in the first charge sheet, the other except Mr. Damodharan having abandoned his claim and in reference to the 2nd charge sheet the other worker having been given a lesser punishment, the management is not justified in dismissing R. Damodaran alone and therefore, it is case of clear discrimination." In that the High Court has held that it is a clear case of discrimination and further held that "Labour Court has failed to consider that all the workers except the two in reference to the first charge were taken back into service. Therefore, the question of leading an illegal and unjust strike and indulging in violent activities causing extensive damage to the properties cannot be attributed to R. Damodaran alone and therefore, it held that "the dismissal order passed against one workman Sri Damodaran is not justifiable." Again the learned counsel for the Petitioner placed reliance on 1989 11 LLN 319 India Cements Ltd. Sankari *Vs.* Labour Court, Coimbatore and Others, wherein the division Bench of the High Court held that "dismissal of 19 workmen by the management and when the case referred to the Labour Minister the Minister recommending reinstatement of only 14 of the 19 workmen and upholding dismissal of remaining 5 workmen and after the Minister has concluded that as against all of them there is a case for severe disciplinary action in the absence of any different material existing for these five workmen, they could not have been differently treated from the other 14 workmen and all these are well within the knowledge of the management and the Minister had dealt with the case of five workmen differently and had not indicated as to why the other 14 workmen should be leniently dealt with the management having not sought for clarification from the Minister for this differential approach it cannot turn round and claim that it has not practised discrimination. On this ground also, the order of dismissal necessarily fails". Relying on these decisions, the learned counsel for the Petitioner contended that out of 15 workmen except the petitioners, seven persons, all of them have been reinstated and their salary was refixed. But the Respondent/Management has not given any reason for their reinstatement and they have not stated that any settlement was arrived at between them and the other workmen. They cannot give any reason why they have entered into a settlement with those persons. Under such circumstances, it cannot be said that they have not shown any discrimination.

38. As against this, the learned counsel for the Respondent argued that these petitioners are leaders of the group and only on their instigation the other workers were involved in these incidents and the other workers have admitted their guilt and therefore, they were given minor punishment and they have been reinstated into service.

39. But, I find there is no truth in this contention because even the Enquiry Officer appointed by the Respondent/Management has given a finding that all the fifteen persons are found guilty of the charges framed against them. It cannot be said that these Petitioners alone are the leaders of the gang and only on their instigation the other workers were involved in these incidents. With regard to the two Petitioners namely Mr. Periannan and Mr. Selvaraj, though the management has framed charges against them that they have indulged on 27-12-1989 causing injuries to officers and staff of Yellikaradu quarry and later on 28-12-89 they came to the Divisional Office along with Mr. Paulraj and Mr. Joseph to attack the mines Foreman Mr. V. Kalyanasundaram and causing injuries and further they have disturbed the industrial peace by preventing the lorries movement in Yellikkaradu quarry and on 15-12-90. There is no evidence by the management

witnesses and there is no material record to prove that the two Petitioners namely Mr. Periannan and Selvaraj were involved in the alleged incidents and no documentary proof was produced before this Tribunal to substantiate their claim.

Point No. 2

The next point to be decided in this case is to what relief the Petitioners are entitled ?

40. In view of my foregoing findings that the action of the Respondent taken against the Petitioners is not legal, I find the Petitioners are to be reinstated in service. Therefore, I direct the Respondent to reinstate the Petitioners with continuity of service and other attendant benefits. The Petitioners are in non-employment from the year 1990. Under such circumstances, I find twenty five percent (25%) of the back wages to the Petitioners is a justifiable one. No costs.

41. All the seven references are answered accordingly.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 26th April, 2004).

K. JAYARAMAN, Presiding Officer

Witnesses Examined :

For the I Party/Workmen	:	WW1 Sri K. Periannan
		WW2 Sri S. Arumugam
		WW3 Sri K. Selavraj
For the II Party/ Management	:	MW1 Sri R. Selavaraj
		MW2 Sri G. Mahalingam

Common Documents Marked :

For the I Party/Workmen :

Ex. No.	Date	Description
W1	04-01-91	Xerox copy of the charge memo issued Petitioner
W2	08-02-91	Xerox copy of the explanation submitted by Petitioner
W3	06-06-92	Xerox copy of the charge memo isssued by Respondent/Management.
W4	02-05-93	Xerox copy of the findings of the enquiry.
W5	18-12-93	Xerox copy of the 2nd show cause notice issued by respondent to Petitioner.
W6	30-09-94	Xerox copy of the letter from Respondent to Mr. Paulraj.
W7	30-09-96	Xerox copy of the letter from respondent to Joseph.
W8	23-11-98	Xerox copy of the 12(3) settlement.
W9	10-07-91	Xerox copy of the judgement in S.C. No. 26/91.
W10	Nil.	Xerox copy of the details regarding punishment and date of reinstatement.
W11	30-09-96	Xerox copy of the order reinstating Mr. Shanmugam.
W12	Nil.	Xerox copy of the order refixing the pay of Shanmugam.
W13	30-09-96	Xerox copy of the order reinstating Mr. Chandran.
W14	Nil.	Xerox copy of the order refixing pay of Chandran.
W15	30-09-96	Xerox copy of the order reinstating Mr. K. Kunjappan
W16	Nil.	Xerox copy of the order refixing pay of Kunjappan.
W17	03-05-93	Xerox copy of the findings of Enquiry Officer with regard to Kaveri and Selvaraj.

For the II Party/Management :

Ex. No.	Date	Description
M1(7)	Nil	Xerox copy of the wound certificate of R. Selvaraj & others issued by Doctor.
M2	26-05-90	Xerox copy of the FIR bearing No. 192/90.
M3(5)	Nil	Xerox copy of the photograph of the place of incident.
M4(7)	06-06-92	Xerox copy of the charge memo issued to Petitioner.
M5(7)	05-01-94	Xerox copy of the explanation submitted by Petitioner.
M6(7)	18-12-93	Xerox copy of the 2nd show cause notice issued to Petitioners.
M7(7)	22-06-92	Xerox copy of the explanation given by Petitioners.
M8(7)	29-11-94	Xerox copy of the order of the Disciplinary Authority.

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 347.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 2/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 03-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/436/2000-आई. आर. (बी.-I)]
सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 347.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 2 of 2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 03-01-05.

[No. L-12012/436/2000-IR(B-I)]
C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA, H. J. S., PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, 117/9 SARVODAYA NAGAR, KANPUR, U.P.

Industrial Dispute No. 2 of 2001

In the matter of dispute between :

The President,
State Bank of India Karamchari Sangh,
K-46 Kidwai Nagar,
Kanpur-208004

And

The Regional Manager,
State Bank of India, Region IV,
Zonal Office The Mall,
Kanpur-208001

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide Notification No. L-12012/436/2000/IR (B-I) dt. 19-3-01 has referred the following dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of India in not paying the full wages of Sri Prakash Maniel subordinate staff w.e.f. January 1995 is justified ? If not, for what relief he is entitled and from what date ?"

2. After the exchange of pleadings between the parties the instant case was identified for decision through LOK ADALAT. The case was taken up in the pretrial meeting for discussion with the parties concerned on 11-8-04 at camp Agra and during the course of discussion the representative for the workman after examining the documents submitted before the Tribunal that the workman concerned is being paid full wages from the date of joining as such there is no dispute to be resolved at the hands of the Tribunal. In view of submissions made by the workman virtually there remains no dispute to be resolved. The submission made above by the authorised representative for the workman has also been accepted by the representative for the management.

3. In the end in view of the foregoings, the tribunal is left with no other option but to hold that the workman is not entitled for any relief pursuant to the present reference made to this tribunal. Hence reference is answered accordingly against the workman and in favour of the Bank management.

SURESH CHANDRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 348.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को. को. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 73/96) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 03-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/303/95-आई. आर. (सी.-I)]
एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 348.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 73/96) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-I now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 03-01-05.

[No. L-20012/303/95-IR(C-I)]
S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10(1) (d) (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 73 of 1996

PARTIES :

Employers in relation to the management of Ropeways, Bhulanbararee of M/S. B. C. C. Ltd.

And

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. Prasad, Presiding Officer

APPEARANCES :

For the Employers : None.

For the Workmen : None.

State : Jharkhand. Industry : Coal

Dated, the 22nd December, 2004

AWARD

By Order No. L-20012/303/95-IR (Coal-I) dated 26-9-96 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-sec. (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the demand of the Union for promotion of Shri Ramgati Ram Rajak in Category-VI w.e.f. 1979 and as Assistant Foreman from 1988 on the ground that his juniors were promoted superseding him is justified ? If so, to what relief is the concerned workmen entitled ?"

2. A petition has been filed jointly signed by the concerned workman and the Vice President, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, stating therein that the local administration of the management have assured the workman concerned to consider the matter upon dropping the case in litigation. In the circumstances, the workman has prayed before this Tribunal to close the case and also to pass award in this case.

3. Since there exists no dispute between the parties, I render a 'No Dispute Award' in this case.

S. PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 349.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पो. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली-II के (संदर्भ संख्या 29/93) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-12-04 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/2/92-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 349.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Corrigendum on (Ref. No. 29/93) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi-II as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Warehousing Corpn. and their workman, which was received by the Central Government on 30-12-04.

[No. L-42012/2/92-IR(M)]

B. M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, RAJENDRA BHAWAN, GROUND FLOOR, RAJENDRA PLACE, NEW DELHI

R. N. Rai, Presiding Officer

I.D. No. 29/93

In the matter of :

Sh. D. K. Singh
C/o Sh. Y. Kr., F-17, Mother Dairy,
Patparganj,
New Delhi

Vs

Central Warehousing Corporation.

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L-42012/2/92 IR (MISC) CENTRAL GOVERNMENT DT. 18-3-93 has referred the following points for adjudication.

The point runs as hereunder :—

"Whether the action of the management of the central warehousing corporation in terminating the services of Sh. D. K. Singh, w.e.f. Feb. 88 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled".

The claimant has filed statement of claim. In the statement of claim, it has been stated that the workman

was appointed through employment exchange as daily rated lower division clerk on temporary basis @ Rs. 17.75 per day by the employer vide appointment order No. CWC/CC IRPB/85/394 dated 21-6-85. That though the appointment of the workman was shown in Annexure-I to be for 89 days he continued to be in the employment of the employer with artificial breaks of a day or so and was in continuous service for more than 240 days. It is therefore clear that showing his initial employment for 89 days only in the appointment letter (Annexure-I) was *mala fide*.

That in fact the workman was engaged on work of regular nature of a LDC throughout the period of his employment with the central warehousing corporation till his illegal and unjustified termination on 18-8-88. That while the workman continued to perform his assigned work efficiently diligently and sincerely the employer surreptitiously and in furtherance of his *mala fide* intentions started showing the workman as WAG-II (LDC on daily wages).

That though his initial appointment as LDC did not require the workman to pass a typing test yet the workman was directed by the Regional office of the employer in the year 1986 to appear in a written and typing test. Though the workman passed the written test conducted by the Regional office he could not qualify in the typing test on account of the fact that the workman was neither mentally prepared for such a test nor he was informed initially that he has to undergo such a test.

That all of a sudden and without any notice the service of the workman was arbitrarily and illegally terminated vide office order No. CWC/CC/I/Est. I/88-89/1099 dated 18-8-1988 with retrospective effect from February, 1988 on the purported grounds that the workman failed to qualify in the typing test which is compulsory. A copy of the said office order is annexed hereto and marked as Annexure-III.

That the employer has recruited fresh daily rated LDC in his establishment without giving an opportunity of re-employment to the workman in utter violation of section 25-H of the ID Act, 1947. That the entire action of the employer right from inception in giving artificial breaks in service showing him as WAG-II rather than LDC and in terminating the services of the workman with retrospective effect being totally arbitrary manifestly illegal nakedly *mala fide* a clear case of unfair labour practice *ab initio* void and invalid in the eyes of law. The workman challenges the same on the following among other grounds.

The order dated 18-8-88 terminating the service of the workman with retrospective effect from February, 1988 is illegal unlawful and invalid whether the employee is permanent or temporary. The condition of qualifying the typing test was not stipulated in the original office order of the appointment of the workman but the typing test qualification has been imposed on him subsequently.

It has been held by the Hon'ble Supreme Court that termination of service of a workman for not qualifying in a test amounts to retrenchment [in the case of Santosh Gupta V/s State Bank of Patiala (1980 II LLJ 72 (SC)]. Non payment of retrenchment compensation and non-compliance of section 25 F of the ID Act, 1947 entitles the petitioner workman to reinstatement and to a declaration that his termination was unlawful.

The management has filed written statement. In the written statement, they have stated that he was engaged on temporary basis as regular recruitment could not be made within time and according to the rules, the knowledge of typing is essential for the post of LDC. Only those candidates who have knowledge of typing according to norms laid down can be regularised. 89 days appointment was given to the workman applicant but it was done so in urgency and it was clearly mentioned in the appointment letter that this post is purely temporary and the workman applicant knew very well that typing knowledge is very essential for the work of LDC. It is obligatory on the part of the candidate for recruitment/appointment as WAG-II LDC that he should be at least Matric with minimum typing speed of 30 words per minute. He was given appointment of a daily wager and he did not raise any objection. The work in construction cell is of periodical nature depending on the construction programme of a particular project, as such, the workman worked for small spells with breaks according to exigencies of the work in the construction cell. He was engaged as daily rated LDC in the construction cell for a short period and his appointment was for a specific purpose. The management knew that he did not know typing. Section 25(F) of the ID Act is not attracted as he was given opportunities two times to qualify the typing test but he did not qualify the test so he could not be regularised against the rules prescribed for recruitment. The workman applicant has filed rejoinder. In his rejoinder, he has reiterated the averments of his statement of claim and the management has denied almost all the paragraphs of the statement of claim.

It was submitted from the side of the workman that the applicant workman has worked from 21-6-1985 to 18-8-1998 which is almost less than 3 years work. He has been given appointment letter on 21-6-1985 for 89 days and again he has been given appointment letter for 89 days, the copies are annexed with the record.

It was submitted from the side of the management that in view of his work, in compliance with the Head Office letter dt. 11-8-1988, his services were terminated as he failed to qualify the typing test which is compulsory as per CWC Staff Regulation Act for the recruitment of WAG-II. Since he has completed 240 days, he was paid

one month's pay by way of compensation under Section 25 (F) (D) of the ID Act, 1947. He has been given compensation so Section 25(F) of the ID Act is not attracted. So far as Section 25(H) is concerned, he was given opportunities to qualify the type test but he failed twice. The workman/applicant has admitted in his cross-examination that it was correct that he was given opportunity to appear for typing test before termination and he appeared twice. The test was conducted by outside agencies but he could not qualify. As such he has been given opportunity to qualify typing test, but he did not qualify and he has been given compensation so section 25 (F) of the ID Act and Section 25 (H) of the ID Act are not applicable. The law cited by the workman is not applicable in the facts and circumstances of this case as he has been paid due compensation and he has been offered opportunities for regularisation..

The reference is replied thus :—

The action of the management of the Central Warehousing Corporation in terminating the services of Sh. D. K. Singh. w.e.f. Feb. 88 is justified. The workman is not entitled to get any relief as prayed for.

The award is given accordingly.

Dt. 10-11-2004 R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 350.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को.को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-I के पंचाट (संदर्भ संख्या 73/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 03-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/334/99-आई. आर. (सी.-I)]
एस.एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 350.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 73/2000) of the Central Government Industrial Tribunal Labour Court, Dhanbad-I now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 03-01-05.

[No. L-20012/334/99-IR(C-I)]
S.S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO I, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 73 of 2000

Employers in relation to the management of Western Jharia Area of M/s. Bharat Coking Coal Ltd.

Vs.

Their Workmen.

PRESENT :

Shri S.Prasad, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri H. Nath, Advocate.

For the Workman : Shri Badri Rajwar, Concerned Workman.

State : Jharkhand. Industry : Coal

Dated, the 21st December, 2004

AWARD

By Order No. L-20012/334/99-(C-I) dated 28-1-2000 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

> "Whether the action of the management of Western Jharia Area of M/s. BCCL, Dhanbad, in not regularising Shri Badri Rajwar as a Drillman is just and proper ? If not to what relief the concerned workman is entitled and from what date ?"

2. The dispute has been settled amicably by both the parties outside the Tribunal. A memorandum of settlement has been filed duly signed by both the parties. I have gone through the terms of settlement and find that the same are fair and reasonable.

3. Accordingly, I pass an award on the basis of terms and conditions laid down in the memorandum of settlement. The memorandum of settlement shall form part of the award.

S. PRASAD, Presiding Officer

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 DHANBAD

Ref. No. 73/2000

PARTIES :

Employers in relation to the management of Western Jharia Area of BCCL.

AND

Their Workman.

The humble petition on behalf of the parties to the above reference.

Most respectfully sheweth :

1. That the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi, vide Notification No. L-20012/334/99 (C-1) dated 28-1-2000 has been pleased to refer the present Industrial Dispute to this Hon'ble Tribunal for adjudication with the following Schedule.

"Whether the action of the Mgt. of Western Jharia Area of M/s. BCCL, Dhanbad in not regularising Sri Badri-Rajwar as a Drillman is just and proper ? If not, what relief the concerned workman is entitled and from what date ?"

2. That without prejudice to the respective contention of the Parties, the dispute has been amicably settled on the following terms and conditions :

(i) That Sri Badri Rajwar M/Loader will be regularised as General Mazdoor in Cat-I under NCWA VI.

(ii) That Medical fitness from Area Medical Board is to be done.

(iii) That he will not be entitled for any wages nor he will claim anything for the period from 22-12-99 to subsequent resuming duty and the intervening period will be construed as—dies-non. However, the continuity of service will be taken for the purpose of Gratuity only.

(iv) That the person concerned will abide by the Coal Mines Pension Scheme 1998 and contribution thereof as applicable. That in view of the aforesaid settlement no dispute subsists for adjudication.

Under the above circumstances it is humbly prayed that the terms of settlement may kindly be accepted as fair and proper and an award may kindly be passed in terms of the settlement.

For the Employers	For the Workmen
Sd./-	Sd./-
1. (D.K. SRIVASTAVA) Dy. Chief Personnel Manager WJA : Moonidih	1. (BADRI RAJWAR) Concerned Workman
Sd/-	Sd/-
2. (N.K. JHA) Personnel Manager (IR), WJA : Moonidih	2. (S.P. VERMA) Union Representatives

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 351.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को.को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 11/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 03-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/172/98-आई. आर. (सी.-I)]
एस.एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 351.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 11/99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 03-01-05.

[No. L-20012/172/98-IR(C-I)]
S.S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO II, AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Biswas, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

Reference No. 11 of 1999

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kusunda Area of M/s BCCL and their workman

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : None

On behalf of the employers : Mr. R.N. Ganguly, Advocate.

State : Jharkhand. Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 17th December, 2004

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/172/98-IR (C-I), dated the 16th December, 1998.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Kusunda Area of BCCL in demoting Sri Hetlal B.P. and 12 others as per annexure enclosed of Kusunda Colliery without completing the formalities under Section 9A of the I.D. Act in the year 1983 is justified ? If not, what relief the workmen are entitled ?

ANNEXURE

	Name	Designation
1.	Hetlal B.P.	B/Fireman
2.	Mathura Bhogta	B/Trammer
3.	Jaglal Dusadh	P/Mistry
4.	Farid Mia	B/Trammer
5.	Allaudin Mia	-do-
6.	Dirgpal Kurmi	-do-
7.	Chandradip Yadav	-do-
8.	Ram Balak Yadav	-do-
9.	Kishun Rabidas	-do-
10.	Nebu Rajwar	B/Fireman
11.	Ramnath Modi	-do-
12.	Bhuneshwar Bhuia	-do-
13.	Sibu Modi	-do-

2. The case of the concerned workmen according to the Written Statement submitted by the sponsoring Union on their behalf in brief is as follows :—

The sponsoring Union submitted that the concerned workmen are permanent employees of Kusunda Colliery under Kusunda Area of M/s. BCCL. In the year 1983 the Hard Coke Ovens were suddenly closed by the management. As a consequence of that closure the workmen engaged in manufacturing of Hard Coke were declared surplus. Thereafter management engaged those workmen in different alternate jobs of the colliery without asking for their option for a particular job and the said alternate job offered to them carried lower time scale. As a result the service condition of those workmen were changed and such change over was not to their benefit. Even the Colliery management did not issue any notice to the concerned workman and their representing Union under Section 9A of the I.D. Act, 1947 before effecting the change in the vital service condition. They submitted that whole process of changing the service condition was done unilaterally. Subsequently those workmen were regularised in the lower scale and at reduced basic wages vide office order No. A-6/P-4/Categorisation/TR/Kusunda/86/1839 dt. 30-9-86. Accordingly the union took up the matter for discussion with the G.M. of Kusunda Area during the same year and in course of their discussion the G.M. considering the loss sustained by those workmen agreed on 10-9-87 to give pay protection to those workmen enjoyed by them immediately before their regularisation in higher scale. They alleged that in spite of such approval made by the G.M. Kusunda Area the workmen were deprived of getting pay protection. Moreover, those workmen also were deprived of the benefit of service linked increment and service linked upgradation. As the management did not take any step for giving pay protection to the concerned workmen they raised an industrial dispute for conciliation which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication. The sponsoring Union accodingly submitted prayer to pass Award directing the management to protect the basic pay of those workmen as enjoyed by them immediately before their regularisation in lower time scale on 30-9-86.

3. Management on the contrary after filing Written Statement-cum-rejoinder have denied all the claims and allegations which the sponsoring union asserted in the Written Statement submitted on behalf of the concerned workmen. They disclosed that in the year 1983 the Hard Coke Oven where the concerned workmen were engaged closed down and for which those workmen rendered surplus to the requirement of the management. Accordingly the concerned workmen were liable to be retrenched from service of the company for the said reason. However as a gesture of cooperation and sympathy and in order to save the workers from retrenchment with consequential hardship they deployed them in the jobs where vacancies existed at the relevant time. Those workmen thereafter joined in their new post as deployed by the management without any objection and they also were provided with proper wages for the jobs performed by them. They further submitted that for long 13 years the workmen concerned had been working in the jobs mentioned above without any protest which clearly

signifies that they accepted the job and also the wages paid to them. They further submitted that the wages of the concerned workmen were fixed as per rules and accordingly they did not commit any illegality in saving the concerned workmen from their retrenchment. In view of the facts and circumstances, the management submitted that the concerned workmen are not entitled to get any relief in view of their prayer, and accordingly their claim is liable to be rejected.

4. POINTS TO BE DECIDED

"Whether the action of the management of Kusunda Area of BCCL in demoting Sri Hetlal B.P. and 12 others as per annexure enclosed of Kusunda Colliery without completing the formalities under Section 9A of the I.D. Act in the year 1983 is justified ? If not, what relief the workmen are entitled ?"

FINDING WITH REASONS

5. It transpires from the record that in course of hearing neither the concerned workmen nor the sponsoring Union appeared before this Tribunal. Even they did not consider necessary to adduce any evidence with a view to substantiate their claim. Management also failed to adduce any evidence in support of their claim. Now on the face of the record let me consider how far the claim of the concerned workmen stand on cogent footing.

It is admitted fact that the concerned workmen were engaged in Hard Coke Oven under the management of Kusunda Area. It is also admitted fact that the said Hard Coke Oven was declared closed by the management in the year 1983. It is also admitted fact that as a consequence to that closure the said workmen who were engaged in the manufacturing of Hard coke were rendered surplus. It is the contention of the management that as a result of the closure of said Hard Coke Oven the concerned workmen were liable to be retrenched from the service of the company. But as a gesture of cooperation and sympathy and in order to save the workers concerned from retrenchment with consequential hardship they deployed them in the jobs where vacancies existed at the relevant time. It is their further contention that accepting such offer those workmen started working in different jobs provided to them and offered wages as per the posts. It is their further contention that accepting the said offer those workmen for long 13 years worked in their respective post and during the said period they did not raise any dispute. On the contrary the contention of the sponsoring union is that before providing the concerned workmen to other jobs management did not give any notice to them under Section 9A of the I.D. Act., 1947. Moreover, the alternate jobs offered to them carried lower time scale and as a result of which they sustained financial loss. Accordingly they entered into discussion with the G. M. Kusunda Area with a prayer for giving pay protection to those workmen. They disclosed that after hearing the G. M. on 10-9-87 agreed to provide pay protection to those workmen immediately before their regularisation in lower time scale. They disclosed that in spite of giving assurance management did not consider necessary to give any pay protection to them as per assurance of the G. M. Kusunda Area. Considering the submission of the sponsoring union as per Written Statement it therefore transpires that they did not agitate the issue of giving notice to the concerned workmen under Section 9A of the I.D. Act, 1947. They only were interested about the pay protection of the concerned workmen in the present scale where they were provided after they were rendered surplus when the said Hard Coke Oven was declared closed. As per Written Statement it is the contention of the management that they provided alternate jobs to the concerned workmen as per rules of the company with a view to save them from retrenchment and in doing so they did not commit any illegality. It is their further contention as per the Written Statement that within the period of long 13 years neither the concerned workmen nor the sponsoring union raised any voice about their pay protection. They submitted further that long after 13 years of the absorption of the concerned workmen in different post the sponsoring union raised the present industrial dispute. Considering the record it transpires that the present dispute was initially raised before the ALC(C) Dhanbad in the year 1998 i.e. after a lapse of long 15 years. The sponsoring union had the scope to produce relevant papers to show that they immediately after closure of the said Hard Coke Oven entered into discussion with the G.M. of Kusunda Area when the concerned workmen were rendered surplus. They also had the scope to produce relevant paper to show that G. M. Kusunda Area assured the sponsoring Union to give pay protection to the concerned workmen in view of discussion held on 10-9-87. Therefore, in absence of cogent paper just relying on the facts disclosed in the Written Statement I find it very hard to accept the contention of the sponsoring union that assurance was given by the G. M. Kusunda Area to give pay protection to the concerned workmen who were rendered surplus after closure of the said Hard Coke ovens. No satisfactory explanation on the part of the sponsoring union is forthcoming to show why they remained silent for such long years when the management failed to give pay protection to the concerned workmen whom alternate jobs were provided after rendering closure of the said Hard Coke Oven. Therefore, if the facts and circumstances are taken into consideration there is sufficient reason to believe that management with a fiew to save the concerned workmen from the grip of retrenchment provided alternate jobs and they without raising any dispute accepted the same for their survival. Silence on the part of the concerned workmen or on the part of the sponsoring union for long years will expose that they accepting the wages started working in different alternate jobs. It further transpires

from the Written Statement of the management that subsequently those workmen were regularised in their respective alternate job provided to them. Therefore, if all these aspects are taken into consideration there is scope to say that with full consent those workmen accepted the alternate jobs as per existing scales. Therefore, by lapse of time the demand placed by the sponsoring union should be considered as a stale demand for consideration. On the contrary there is sufficient reason to believe that management with good wishes to save the concerned workmen from retrenchment provided alternate jobs for their benefit. Apart from all the facts discussed above I further hold that the facts disclosed in the Written Statement cannot be considered as substantive piece of evidence when the same was not corroborated by adducing cogent evidence. Record shows that ample opportunities were given to the sponsoring union to substantiate their claim in question, but they have lamentably failed to avail the same. They even did not consider necessary to take any step in course of hearing. Therefore, relying on the facts disclosed in the Written Statement I find it very hard to consider the claim of the sponsoring union and for which they are not entitled to get any relief in view of their prayer.

In the result, the following Award is rendered :

"The action of the management of Kusunda Area of BCCL in demoting Sri Hetlal B.P. and 12 others as per annexure enclosed of Kusunda Colliery without completing the formalities under Section 9A of the I.D. Act in the year 1983 is justified. Consequently, the concerned workmen are not entitled to get any relief."

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 352.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को.को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 120/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 03-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/197/98-आई. आर. (सी.-I)]
एस.एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 352.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 120/99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 03-01-05.

[No. L-20012/197/98-IR(C-I)]
S.S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 2, AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. BISWAS, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

Reference No. 120 of 1999

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workman : Mr. S. C. Gaur, Advocate.

On behalf of the employers : Mr. D. K. Verma, Advocate.

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 16th December, 2004

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/197/98-IR (C-I), dated the 29th Jan, 1999.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Lodna Colliery of M/s. BCCL in dismissing Sri Sitaram Bhuiya, M/Loader from the services of the company w.e.f. 26-5-97 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The case of the concerned workman according to the Written Statement submitted by the sponsoring Union on his behalf in brief is as follows :

The sponsoring Union submitted that the concerned workman due to sad demise of his father received a serious mental shock and consequent to that became a patient of nervous breakdown and for which he remained himself absent from duty with effect from 22-8-95 to 19-12-96. On 20-12-96 he intended to resume his duty but he was not allowed to join. They submitted that the concerned workman being a member of Tribal community and also

an illiterate person was not aware of the procedure for taking leave etc., and as a result of which he could not inform the management about the reasons of his absence. They alleged that the management issued a chargesheet to the concerned workman on 21-12-96 i.e. after he reported for duty. The concerned workman submitted his reply to the chargesheet but management without accepting his reply started a departmental proceeding against him through Enquiry Officer and the said Enquiry Officer illegally, arbitrarily and violating the principle of natural justice submitted his report holding the concerned workman guilty of the charges. Relying on the said report the Disciplinary Authority also illegally, arbitrarily and violating the principle of natural justice dismissed him from service with effect from 26-5-97. They submitted that the punishment inflicted on the concerned workman by the Disciplinary Authority was disproportionate in relation to the misconduct committed by him and for which the said order of dismissal is liable to be set aside. As the management did not consider the prayer for reinstatement of the concerned workman they raised an industrial dispute before the ALC(C) which ultimately resulted reference to this Tribunal for adjudication. The sponsoring Union submitted prayer for passing Award directing the management to reinstate the concerned workman to his service with effect from the date of dismissal along with full back wages.

3. Management on the contrary after filing Written Statement-cum-rejoinder have denied all the claims and allegations which the sponsoring Union asserted in the Written Statement submitted on behalf of the concerned workman. They submitted that the concerned workman was appointed as Miner/Loader on 15-2-94, but in the year 1994 he worked for 20 days and in the year 1995 he worked for 38 days. Thereafter he started absenting himself from duty unauthorisedly with effect from 22-8-95 without any information or obtaining any permission from competent authority. On 21-12-96 accordingly management issued a chargesheet against the concerned workman with the allegation for committing misconduct on the ground of absenteeism under clause 26.1.1 of Certified Standing order. The concerned workman on receipt of the said chargesheet submitted his reply on 17-1-97. As the reply given by him was not satisfactory the Disciplinary Authority decided to hold domestic enquiry against him and accordingly appointed the Enquiry Officer. They further submitted that during hearing of the enquiry proceeding full opportunity was given to the concerned workman to defend his case. They further submitted that the Enquiry Officer conducted the said enquiry fairly, properly and in accordance with the principle of natural justice and after completion of the enquiry submitted report holding the concerned workman guilty to the charges. Thereafter considering all aspects and also considering report submitted by the Enquiry Officer the Disciplinary Authority dismissed the concerned workman from his service. They categorically denied the fact that the Disciplinary Authority dismissed the concerned workman illegally, arbitrarily and violating the principle of natural justice and accordingly they submitted further that the concerned workman, in the circumstance, is not entitled to get any relief in view of his prayer.

4. POINTS TO BE DECIDED

"Whether the action of the management of Lodna Colliery of M/s. BCCL in dismissing Sri Sitaram Bhuiya, M/Loader from the services of the company w.e.f. 26-5-97 is justified ? If not, to what relief the workmen is entitled ?"

5. FINDING WITH REASONS

It transpires from the record that before taking up hearing of the instant case on merit it was taken into consideration as a preliminary issue whether domestic enquiry held against the concerned workman was fair, proper and in accordance with the principle of natural justice. The said issue was decided in favour of the management vide order No. 13 dt. 13-6-2002. Therefore, at this juncture there is no scope to re-open the said issue further in disposing of the case on merit. Here the point for consideration is whether the management have been able to substantiate the charge brought against the concerned workman and if so whether the concerned workman is entitled to get any relief U/S. 11A of the I.D. Act, 1947.

It is the specific allegation of the management that the concerned workman started remaining himself absent from duty with effect from 22-8-95 without giving any intimation or taking any prior permission from the authority and accordingly on 21-12-96 a chargesheet was issued to the concerned workman which during evidence of MW-1 was marked as Ext. M-1. The concerned workman in his Written Statement admitted the fact of his remaining absent from duty w.e.f. 22-8-95 to 19-12-96. It is his contention that on 20-12-96 when he came to his place of work he was not allowed to resume his duty. On the contrary on 21-12-96 a chargesheet was issued to him. It is the contention of the sponsoring union that on receipt of the said chargesheet the concerned workman submitted his reply denying the charges brought against him. The reply during evidence of MW-1 was marked as Ext. M-2. I have considered the reply given by the concerned workman which shows that as his father expired he could not attend his duty during the period in question. It is admitted fact that the concerned workman remained himself absent from duty for more than one year 3 months. In course of hearing of the enquiry proceeding opportunity was given to the concerned workman to defend his case. But in spite of giving opportunity the concerned workman failed to assign any cogent reason why he failed

to give any intimation to the management about the reason of his absence. It is the contention of the sponsoring Union that the concerned workman was a member of Tribal community and also an illiterate person and for which he was not aware of the procedure how to take leave. This plea taken by the sponsoring union cannot be considered as sufficient ground to accept the ground for remaining himself absent for such a long period. On the contrary it is the specific claim of the management that the concerned workman was appointed as Miner/Loader on 15-2-1994 and in the year 1994 he worked for 20 days while in the year 1995 he worked only for 38 days. This picture will expose clearly that the concerned workman was in the habit of remaining himself absent from duty as of his choice. However, as this fact was not included in the chargesheet. I find no scope to take it into consideration as a ground for misconduct committed by the concerned workman. According to the chargesheet the concerned workman remained himself absent with effect from 22-8-95 and as such unauthorised absence amounted to misconduct for which management issued a chargesheet against him on 21-12-96. I have already discussed above that the concerned workman remained himself absent from duty for more than one year 3 months. Though in his reply he assigned the ground of his absence during hearing has failed to substantiate the same reasonably. Such unauthorised absence of the concerned workman amounted committal of misconduct as per clause 26.1.1 of the Certified Standing Order applicable to the employees of the management. Onus absolutely is on the concerned workman to establish his claim that he did not commit any misconduct on the ground of his remaining absence from duty for such long period. Accordingly after careful consideration of all the facts and circumstances I hold that the management on cogent footing issued chargesheet against the concerned workman for committing misconduct under clause 26.1.1 of the Certified Standing Order. The enquiry report during evidence of MW-1 was marked as Ext. M-4. The Enquiry Officer in his report assigned the ground before he came to his conclusion why the concerned workman was found guilty to the charges brought against him. On the basis of the report submitted by the Enquiry Officer and also considering all other aspects the Disciplinary Authority dismissed the concerned workman from his service and the said order of dismissal during evidence of MW-1 marked as Ext. M-6. After careful consideration of all the facts and circumstances I hold that management have been able to substantiate the charge brought against the concerned workman.

Now the point for consideration is whether the said order of dismissal was disproportionate to the misconduct committed by the concerned workman and also whether the said order of dismissal was passed illegally, arbitrarily and violating the principle of natural justice. Section 11A of the I.D. Act, 1947 speaks as follows :—

> "Whether an industrial dispute relating to the discharge of dismissal of a workman has been referred to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal for adjudication and, in the course of the adjudication proceedings, the Labour Court, Tribunal or National Tribunal, as the case may be, is satisfied that the order of discharge or dismissal was not justified, it may, by its award, set aside the order of discharge or dismissal and direct reinstatement of the workman on such terms and conditions, if any, as it thinks fit, or give such other relief to the workman including the award of any lesser punishment in lieu of discharge or dismissal as the circumstances of the case may require."

As per this provision of law it is to be taken into consideration whether the order of dismissal passed by the management was justified or not ? In course of hearing learned Advocate for the management submitted categorically that the concerned workman was so negligent that he did not consider necessary to give any intimation to the management for his remaining absent from duty continuously. Learned Advocate further submitted that the concerned workman also in spite of getting opportunity did not consider necessary to produce death certificate of his father in support of his claim. Referring all these facts learned Advocate further submitted that in the industry if discipline is not maintained properly in that case production for economic growth will be hampered seriously. Learned Advocate for the management further referring the judgement passed by the Hon'ble High Court, Patna in C.W.J.C. No. 7047 of 1994 submitted that over similar ground Hon'ble Court dismissed the Writ Petition filed by one workman Nageshwar Ram. I have considered the decision of the Hon'ble Court and it definitely has supported the claim of the learned Advocate for the management. It is not expected that a workman ignoring the discipline at the place of work should be indulged to act whimsically as of his choice. If for argument's sake it is taken into consideration that he started remaining himself absent from duty owing to death of his father in that case there is no scope to say that for the said reason he would remain himself absent for such a long period. The representative of the concerned workman submitted that as a result of the death of his father the concerned workman became a patient of nervous breakdown. The plea which has been taken by the sponsoring union was not ventilated in the reply to the chargesheet submitted by the concerned workman. Therefore, there is reason to believe that new fact was added for the cause of the workman by the sponsoring union and for which the same cannot be relied on without cogent evidence. Absence of such long period without assigning any cogent reason should be amounted to gross misconduct as per clause 26.1.1 of the Certified Standing Order. Accordingly there

is no scope to say that the order of dismissal passed by the management was absolutely disproportionate to the misconduct committed by him. I also do not find any reason to say that the said order of dismissal issued against the concerned workman by the management was either illegal, arbitrary or it violated the principle of natural justice.

In view of the facts and circumstances discussed above I hold that the concerned workman is not entitled to get any relief. In the result, the following Award is rendered :—

"The action of the management of Lodna Colliery of M/s. BCCL in dismissing Sri Sitaram Bhuiya, M/Loader from the services of the company w.e.f. 26-5-97 is justified. Consequently, the concerned workman is not entitled to get any relief."

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 353.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 12/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/86/2003-आई. आर. (सी-1)]
एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 353.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 12/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CCL and their workman, which was received by the Central Government on 3-1-2005.

[No. L-20012/86/2003-IR(C-I)]
S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Biswas, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 12 of 2004

PARTIES :

Employers in relation to the management of Amlo Project of M/s. CCL and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workman : None

On behalf of the employers : Mr. D. K. Verma, Advocate.

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 15th December, 2004

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/86/2003-IR(C-I), dated the 17th December, 2003.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of CCL Amlo Project in awarding punishment of stoppage of one increment with cumulative effect to Shri H. K. Choudhary, Sr. Clerk is just and fair ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. In this case neither the concerned workman nor his representative appeared. Management side, however, made appearance through their authorised representative. It transpires from the record that in spite of issuance of repeated notices the concerned workman or his representative did not consider necessary to appear to take steps in connection with this case. This is a case of 2004 and since then it is pending for disposal. Considering the conduct of the sponsoring union/workman it shows clearly that they are not interested to proceed with the hearing of this case. In the circumstances, there is no justification to adjourn the case suo moto for days together by this Tribunal. Hence, the case is closed and a 'No dispute' Award is passed in this reference presuming non-existence of any industrial dispute between the parties.

B. BISWAS, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 354.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को.को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 289/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/105/99-आई. आर. (सी-1)]
एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 354.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 289/99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour

Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 3-1-2005.

[No. L-20012/105/99-IR(C-1)]
S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Biswas, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 289 of 1999

PARTIES :

Employers in relation to the management of Sijua Area of M/s. BCCL and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workman : None

On behalf of the employers : Mr D. K. Verma, Advocate.

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 15th December, 2004

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/105/99-IR(C-I), dated the 3rd August, 1999.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Tetulmari Colliery of M/s. BCCL in dismissing Sri Chhota Haridas, M/Loader from the services of the company w.e.f. 30-7-1988 on the ground of unauthorised absence from duty is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. In this reference neither the concerned workman nor his authorised representative appeared. Management, however, made appearance through their learned Advocate. It reveals from the record that the instant reference is pending since 1999 for disposal. It also further transpires that in spite of issuance of consecutive notices neither the concerned workman nor the sponsoring union considered necessary to submit Written Statement in the instant case. Gesture of the workman/sponsoring union if is taken into consideration will expose clearly that neither the concerned workman nor the sponsoring union is interested to proceed with the hearing of the case. Therefore, this Tribunal also finds no ground to adjourn the case suo moto for days together. Hence, the case is closed. Under the circumstances, a 'No dispute' Award is rendered and the instant reference is disposed of on the basis of 'No Dispute Award, presuming non-existence of any industrial dispute between the parties.

B. BISWAS, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 355.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को.को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 127/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/157/2003-आई. आर. (सी-1)]
एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 355.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 127/2003) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 3-1-2005.

[No. L-20012/157/2003-IR(C-1)]
S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Biswas, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 127 of 2003

PARTIES :

Employers in relation to the management of Lodna Area of M/s. BCCL and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workman : None

On behalf of the employers : Mr. D. K. Verma, Advocate.

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 14th December, 2004

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/157/2003-IR(C-I), dated the 10th November, 2003.

SCHEDULE

"Kya Bharat Coking Coal Ltd. Lodna Kshetra Dwara Karmkar Shri Sib Kumar Dusadh Ko Driver Cat-V Key Pad Par Niyamitakaran Key Samya Vetan Nirdharan Kartey Huye Nichley Pad Par Unhey Diya Ja Rahey Spra Ka Lav Na Diya Jana Uchit Evam Nayasangat Hai ? Yadi Nahi to Karmkar Kis Rahat Key Patra Hai ?"

2. In this case neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal. Management, however, made appearance through their learned Advocate. Record shows that in spite of issuance of consecutive notices neither the concerned workman nor the sponsoring union considered necessary to submit Written Statement in the instant case. The attitude of the concerned workman/sponsoring union if is taken into consideration will expose clearly that neither the concerned workman nor the sponsoring union is interested to proceed with the hearing of the case. Under such circumstances, this Tribunal finds no ground to keep pending this case for days together only for appearance of the concerned workman/union. Hence, the case is closed. Accordingly a 'No dispute' Award is rendered and the instant reference is disposed of on the basis of 'No dispute' Award presuming non-existence of any industrial dispute between the parties.

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 356.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को.कों.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 126/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/166/2003-आई. आर. (सी-I)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 356.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 126/2003) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 3-1-2005.

[No. L-20012/166/2003-IR(C-I)]

S. S. GUPTA, Under Secy

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Biswas, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 126 of 2003

PARTIES :

Employers in relation to the management of Amlabad Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workman : None

On behalf of the employers : Mr. U.N. Lall, Advocate.

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 14th December, 2004

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/166/2003-IR(C-I), dated the 10th November, 2003.

SCHEDULE

"whether the action of the management of BCCL, Amlabad Colliery in dismissing Sri Taiyyab Amsaro w.e.f. 1-2-2003 is justified ? If not to what relief is the workman entitled ?"

2. In this reference neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal. Management, however, made appearance through their authorised representative. It transpires from the record that in spite of issuance of consecutive notices neither the concerned workman nor the sponsoring union considered

necessary to submit Written Statement in the instant case. The attitude of the concerned workman/sponsoring union if is taken into consideration will expose clearly that neither the concerned workman nor the sponsoring union is interested to proceed with the hearing of the case. Under such circumstances, this Tribunal finds no ground to keep pending this case for days together only for appearance of the concerned workman/union. Hence, the case is closed. Accordingly a 'No dispute' Award is rendered and the instant reference is disposed of on the basis of 'No dispute' Award presuming non-existence of any industrial dispute between the parties.

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 357.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 10/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/85/2003-आई. आर. (सी-I)]
एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 357.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 10/2004) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CCL and their workman, which was received by the Central Government on 3-1-2005.

[No. L-20012/85/2003-IR(C-I)]
S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Biswas, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 10 of 2004

PARTIES :

Employers in relation to the management of Amla Project of M/s. CCL and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workman : None

On behalf of the employers : Mr. D. K. Verma, Advocate.

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 14th December, 2004

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/85/2003-IR(C-I), dated the 17th December, 2003.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of CCL, Amla Project in awarding punishment of stoppage of one increment with cumulative effect on Shri B. K. Singh, Sr. Clerk is just and fair ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. In this reference neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal. Management side, however, made appearance through their authorised representative. It transpires from the record that in spite of issuance of repeated notices the concerned workman nor his representative did not consider necessary to appear with a view to take steps in connection with this case. This is a case of 2004 and since then it is pending for disposal. Considering the conduct of the sponsoring union/workman it shows clearly that they are not interested to proceed with the hearing of this case. In the circumstances, there is no justification to adjourn the case *suo moto* for days together by this Tribunal. Hence, the case is closed and a 'No dispute' Award is passed in the reference presuming non-existence of any industrial dispute between the parties.

B. BISWAS, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 358.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.सी.एल. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 52/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/16/2002-आई. आर. (सी-I)]
एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 358.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 52/2002) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of CCL and their workman, which was received by the Central Government on 3-1-2005.

[No. L-20012/16/2002-IR(C-1)]
S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Biswas, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 52 of 2002

PARTIES :

Employers in relation to the management of Giridih Kshetra of CCL and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workman : None

On behalf of the employers : Mr. D. K. Verma, Advocate.

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 14th December, 2004

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/16/2002-IR(C-I), dated the 15th July, 2002.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Giridih Area of M/s. CCL in not regularising the services of S/Sri Parmeshwar Shaw, Rajendra Dusadh and Karoo Ansari in the Time Rated job is fair and justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled and from what date ?"

2. In this case neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal. Management, however, made appearance through their authorised representative. Record shows that the instant reference is pending since 2002 for disposal. It also further transpires from the record that in spite of issuance of consecutive notices neither the concerned workman nor the sponsoring union considered necessary to submit Written Statement in the instant case. The attitude of the concerned workman/sponsoring union if is taken into consideration will expose that neither the concerned workman nor the sponsoring union is interested to proceed with hearing of the case. Under such circumstances, this Tribunal finds no ground to keep pending this case for days together only for causing appearance of the concerned workman/union. Hence, the case is closed. Accordingly, a 'No dispute' is rendered in this reference and the instant reference is disposed of on the basis of 'No dispute' Award presuming non-existence of any industrial dispute between the parties.

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2005

का. आ. 359.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा.को.को.लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, धनबाद-II के पंचाट (संदर्भ संख्या 118/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-30012/524/2000-आई. आर. (सी-I)]
एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 4th January, 2005

S.O. 359.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 118/2001) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Dhanbad-II now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 3-1-2005.

[No. L-30012/524/2000-IR(C-I)]
S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri B. Biswas, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 118 of 2001

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman.

APPEARANCES :

On behalf of the workman : None

On behalf of the employers : Mr. S. P. Sinha, Advocate.

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 15th December, 2004

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-30012/524/2000-(C-I), dated, the 29th March, 2001.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. BCCL in not regularising the services of Excvn. Grade-D w.e.f. 18-8-1996 and the Grade 'C' w.e.f. 22-2-2000 of the workman Sri Ramjit Bhuiya, O.B.R. (Miner) Ghanoodiih Colliery under Bastacolla Area is justified legal and proper ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

2. In this reference neither the concerned workman nor his representative appeared before this Tribunal. Management side, however, made appearance through their learned Advocate. Record shows that the instant reference is pending since 2001 for disposal. It also further transpires from the record that in spite of issuance of consecutive notices neither the concerned workman nor the sponsoring union considered necessary to submit Written Statement in this case. The attitude of the concerned workman/sponsoring union if is taken into consideration it will expose that neither the concerned workman nor the sponsoring union is interested to proceed with hearing of the case. This Tribunal finds no ground to adjourn the case suo moto for days together only for causing appearance of the concerned workman/union. Hence, the case is closed. Under the circumstances, a 'No dispute' Award is rendered and the instant reference is disposed of on the basis of 'No dispute' Award presuming non-existence of any industrial dispute between the parties.

B. BISWAS, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2005

का. आ. 360.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलिकॉम रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण नं. II, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 124/91) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/49/91-आई. आर. (डी.यू.)]
कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th January, 2005

S.O. 360.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 124/91) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, No. II, New Delhi now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Telecom Railway Electrification and their workman, which was received by the Central Government on 5-1-2005.

[No. L-40012/49/91-IR(DU)]
KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, NEW DELHI

I.D. No. 124/91

R. N. Rai, Presiding Officer.

Shri Janki Prasad S/o. Shri Deep Chand,
C/o. Shri Surender Singh,
2/236, Namner, Agra-282001.

Versus

The Asst. Engineer,
Telecom Railway Electrification,
1/13, Vibhav Nagar, Agra-282001.

AWARD

The Ministry of Labour by its letter No. L. 40012/49/91-IR(DU) Central Government dated 27-09-1991 has referred the following points for adjudication.

The point runs as hereunder :—

"Whether the DET/Railway Electrification, New Delhi and Asstt. Engineer Telecom, Railway Electrification, Agra are justified in terminating the services of Shri Janki Prasad w.e.f. 1-3-1989 and also not assigning proper seniority ? If not, what relief the workman concerned is entitled to."

The claimant has filed statement of claim. In the statement of claim, it has been stated that the services of the workman was terminated on 1-3-1989 in violation of Section 25-F of the ID Act. He has worked under the management from June 1988 to February 1989 and he has worked for more than 240 days. He was issued certificate for work on Telecom Railway Electrification

Project on 6-3-1989. Many other workmen alongwith the workman applicant were terminated from services though they have completed 240 days. Their services have been terminated illegally, unjustifiably without paying any compensation so they deserve to be regularised.

The management has filed written statement. In the written statement, it has been stated that the Court has no jurisdiction as the Telecom Department is not an industry and the CAT has held so. The scheme prepared by the Department in pursuance of the judgement of the Hon'ble Court in AIR 1987 SC 2342 was approved by the Hon'ble Supreme Court in 1990 (SUPP) SCC 113. The workman applicant is not entitled to get back wages as judicial pronouncement is in the nature of fresh rule elaborated by the court in the interest of justice. SLP No. 17907/191 has been filed by the Union of India *Vs.* Munim Singh and the Hon'ble Supreme Court on 13-10-1991 has granted stay and issued notice to the respondents on 9-12-1991. Hence, the workman should wait for the judgement of the Hon'ble Supreme Court. The workman applicant is daily rated worker so he is not entitled to be regularised. He was working on the project in that view of the matter also. He is not entitled to be regularised.

The workman has filed rejoinder and in his rejoinder he has reiterated the averments of his statement of claim.

The workman has not been turning up so notice was sent to him. Despite receiving notice he did not turn up for cross-examination. As such cross-examination was closed. The management has filed affidavit.

It was submitted from the side of the management that the Railway Electrification is not an industry. It has been held by the Hon'ble Supreme Court in the Bangalore Water Supply that Telecom Department is an industry. There are several other judgements in which the Railway has been declared to be an industry so the management is an industry and the Court has jurisdiction to decide the case.

It was further submitted from the side of the management that the workman worked on a project and when the project was completed he was surplus so he was retrenched. His services have not been terminated arbitrarily. The workman applicant has not been turning up in the Court and he has not been cross-examined on the facts stated in the statement of claim and rejoinder so his plea cannot be said to be established. The affidavit of management will prevail. The workman applicant is not entitled to get any Relief as prayer for.

The reference is replied thus :—

The DET/Railway Electrification, New Delhi and Asstt. Engineer Telecom, Railway Electrification, Agra are justified in terminating the services of Shri Janki Prasad w.e.f. 1-3-1989. The workman applicant does not deserve to get any relief as prayed for.

The award is given accordingly.

Dated : 29-12-2004 R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2005

का. आ. 361.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 37/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/424/99-आई. आर. (डी. यू.)]
कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th January, 2005

S.O. 361.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 37/2000) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Post and their workman, which was received by the Central Government on 5-1-2005.

[No.L-40012/424/99-IR(DU)]
KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, SARVODAYA NAGAR, KANPUR, U. P.

Industrial Dispute No. 37 of 2000

In the matter of dispute between :

Sri Ram Saran Gupta,
C/o O. P. Mathur,
117/36, 'K' Sarvodaya Nagar,
Kanpur.

AND

Sr. Superintendent of Post Offices,
Dak Mandal,
Bareilly, U. P.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide notification No. L-40012/424/99 IR (DU),

dated 2-3-2000 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal :—

> Whether the claim of Sri Ram Saran Gupta in regard to his employment as an Extra Departmental Agent or for the post of packer in the department of Sr. Suptd. of Post Office, Bareilly is legal and justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?

2. In the present case after exchange of pleadings between the parties the case was taken up for evidence. On the date fixed in the case none appeared in the case from either side as a result of which parties have been debarred from adducing their respective evidence. The case was taken up for final arguments in the case when once again none appeared from either side.

3. Therefore from the above it is quite clear that it is a case of no evidence and the tribunal under these circumstances is handicapped for answering the reference in favour of either of the parties. As a result of which since the workman failed to adduce evidence in support of his claim it is held that the workman is not entitled for any relief pursuant to the present reference.

4. Lastly it is held that the workman is not entitled for any relief for want of evidence. Reference is answered accordingly in favour of the management and against the workman.

SURESH CHANDRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2005

का. आ. 362.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तरी रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ आई.डी. संख्या 58/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-41012/150/98-आई. आर. (बी. 1)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 5th January, 2005

S.O. 362.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (I. D. No. 58 of 99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Kanpur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway and their workman, which was received by the Central Government on 04-01-2005.

[No.L-41012/150/98-IR(B. 1)]
B. M. DAVID, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, SARVODAYA NAGAR, KANPUR, U. P.

Industrial Dispute No. 58 of 99

In the matter of dispute between :

Sri Dinanath Tiwari,
Divisional Organisation Secretary,
Uttar Rly. Karamchari Union,
119/74, Quarter No. 61,
Naseemabad, Kanpur.

AND

Northern Railway,
The Divisional Rly. Manager,
Allahabad.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide notification No. L-41012/150/98-IR dated 15-3-99 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal :—

> KYA MANDAL RAIL PRABANDHAK UTTAR RAILWAY, ALLAHABAD DWARA MANDAL SANGHATHAN MANTRI, UTTAR RAILWAY KARAMCHARI UNION DWARA HARTAL NOTICE DINANK 24-7-97, SAMBANDHIT KARAMCHARI SRI RAM GOPAL PUTRA SRI RAM BARAN KO 1-4-81 SE LOHAR AVAM PAD VETANMAN I AVAM SENIORITY TATHA DOCTORY PARIKSHA PRAMAN PATRA SANKHYA DWARA 7-1-97 DWARA B-I, B. II CATEGORIES MEIN AYOGYA GHOSHIT KARANA NYAYOCHIT HAI YA NAHI ?

2. In the instant case the contesting parties to the present dispute have been debarred from adducing their respective evidences in support of their cases as they palpably failed in adducing their respective evidence on the respective dates fixed in the case though pleadings between the parties have already been exchanged. Both contesting parties to the present dispute have also filed photocopies of certain documents in support of their respective claims but photocopies of the documents cannot be read in evidence unless proved by originals.

3. Therefore from the above position it is clear that it is a case in which both parties have failed to adduce their respective evidence in support of their claims resulting that the tribunal is left with no other alternate but to reject the claim of the workman for want of evidence. Accordingly the claim of the workman is liable to be rejected and is hereby rejected holding that the workman

is not entitled for any relief pursuant to the present reference made to this tribunal.

SURESH CHANDRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2005

का. आ. 363.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, कोल्लम के पंचाट (संदर्भ संख्या 1/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 05-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-12012/226/1999-आई. आर. (बी. II)]

सी. गंगाधरण, अवर सचिव

New Delhi, the 5th January, 2005

S.O. 363.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1/2000) of the Industrial Tribunal, Kollam as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between to the management of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 05-01-2005.

[No.L-12012/226/1999-IR(B-II)]

C. GANGADHARAN, Under Secy.

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, KOLLAM

(Dated, this the 2nd day of December, 2004)

PRESENT :

Sri C. N. Sasidharan

INDUSTRIAL TRIBUNAL

IN

Industrial Dispute No. 1/2000

BETWEEN :

The Regional Manager,
Central Bank of India,
P. B. No. 98, Gopal Building,
Thyvila Road,
Trivandrum. ... Management

(By Sri R. Kunjukrishnan Potti, Advocate, Trivandrum)

AND

Sri B. Premkumar, Thodiyil Veedu,
Thamarathottom,
Kaikulangara North,
Kollam. ... Workman

(By Sri M. S. Vijayachandra Babu, Advocate, Trivandrum)

AWARD

The Government of India, by Order No. L-12012/226/99/IR (B-II) dated 20-12-1999, have referred this industrial dispute to this Tribunal for adjudicating the following issue.

> "Whether the action of the management of Central Bank of India in terminating the service of the workman Sri B. Premkumar, temporary peon, Kadappakkada branch w.e.f. 23-8-1997 is legal and justified ? If not; to what relief the workman is entitled to ?"

2. The case of the workman Sri Prem Kumar is that he was a temporary Peon in the Kadappakkada branch of the management bank in the sub-staff category and had worked for the period from 10-9-1991 to 23-8-1997. While working so, his service had been terminated on 23-8-1997 without any reason or notice. The action of the management in doing so is illegal. He has worked from 10-9-1991 to 21-3-1997 as temporary peon and out of this period the duty attended by him from 1993 to 1997 was continuous in nature and without any break. Hence the management has no right to terminate him from service. Further during the period 1993 to 1997 there was a vacancy of peon in that branch and the workman was attended the duties in that vacancy. He has attended the duties of regular sub-staff of bank and the manager of the bank directed the workman before Government Institution and other Banking Institution with authorisation for collecting cash and other valuable documents. He had attended more than 240 days attendance in each year from 1994 onwards and he was paid wages through voucher which was credited in the Savings Bank Account of him in that branch. The management has never levelled any charge against the workman and his termination is hence illegal and arbitrary. The management has not complied the conditions stipulated in Sec. 25-F of the Industrial Disputes Act ('the Act' for short) while terminating his service. There is no justification for the action of the management and hence he is eligible for reinstatement in service with all legal benefits. It is also stated that ever since the date of termination, he is remaining unemployed and hence eligible for backwages.

3. The management while opposing the claim of the workman has stated that he had worked only as a casual labourer on certain days and never worked continuously as claimed. The maximum number of days worked by him in an year was 55 days and he was never employed for 240 days in an year at any time. He was never employed in any of the vacancy in management of that particular branch but only as a casual labourer. The branch manager never allowed the workman to appear before Government Office or other banking institutions etc. for attending regular nature of official work. As he

was only a casual employee, there was no termination and the issuance of notice is also unnecessary. Hence there is no necessity to serve notice or pay compensation. As he has never worked for a continuous period not less than one year, he cannot claim benefit of Sec. 25-F of the Act. Hence the question of reinstatement in service with benefits does not arise.

4. The evidence consists of both oral and documentary. The Senior Manager of the concerned branch of the bank has filed proof affidavit in lieu of chief examination and was cross examined as MW1. Exts. M1 and M2 have been marked on the side of the management. The workman examined himself as WW1 and Exts. W1 to W3 have been marked in support of his claim.

5.

0.1. The workman is claiming reinstatement in service contending that his service had been terminated by the management Bank illegally. Admittedly the workman was in the service of the management Bank from 1991 to 1996 though the employment was on certain days on casual basis. But according to the workman he had attended duty as a Peon for the period from 10-9-1991 to 23-8-1997 and for the period from 1993 to 1997 his service was continuous as his engagement was in the vacancy of a Peon. The workman as WW1 has deposed in support of his claim and proved Exts. W1 to W3. During cross-examination he has categorically stated that he had worked in the vacancy of one of the three posts of Peon in that branch while the Peon Sri Muraleedharan was on long leave due to his illness. This categoric statement is not rebutted by the management by any evidence. Ext. W2-series are copies of letters of the manager of the particular branch entrusting with the work of attending other office/banks for collecting money, documents etc. and the workman is described as sub-staff in some of the letters. Ext-W3-series show that the workman has participated in All India Bank Employees Competitions held at Kollam. According to him he deposited his wages in his S. B. Account evidenced by Ext. W1-series passbooks which also shows payment made continuously.

0.2. Admittedly no appointment order was given to the workman by the management and payment was effected to him through vouchers. As he was engaged temporarily he was not made to sign attendance register or any other documents. The definite case of the workman is that he had attended full duty in the years 1994-95 and 1996-97 but wages were paid in different names which were signed by him alone as insisted by the chief cashier. In order to prove this and his continued employment, the management was called upon to produce vouchers during the years 1994 to 1997 and the corresponding Day Book. But the management has not produced the same inspite of specific direction from this Tribunal at the instance of the workman without any explanation whatsoever. The management has not even filed an affidavit stating the difficulties if any in producing those documents. MW1, the witness examined on the side of the management has not stated that the management is not in possession of these documents. Hence it can only be concluded that the management purposely failed to produce those documents, because if produced, those would prove against the case of management and in support of the claim of the workman. Hence necessary adverse inference has to be drawn against the management for hiding such material documents. In the nature of the contentions of the parties those are very crucial documents also. The evidence of the workman supported by Exts. W1 to W3 considered along with the non-production of material documents by the management, fully establish the case of the workman that he was employed by the management continuously for more than 240 days during the years 1993 to 1997.

6. No doubt the management has disputed the claim of the workman and in support that the manager has given evidence as MW1. But MW1 has admitted that the workman was in service from 1991 to 1996 but of course on certain days on casual basis only. According to the management the maximum days of work of the workman in a year is only 58 days. But in support of this the only documents produced and marked are Exts. M1 and M2 which only prove the amount of wages paid in two days in the year 1994. As stated above the management has kept away the relevant documents inspite of specific direction from this Tribunal. Therefore the evidence of MW1 supported by Exts. M1 and M2 alone would not substantiate the case pleaded by the management particularly in the light of the case established by the workman.

7. As I have found above the workman was in the service of the management continuously for more than 240 days and he is not in the service of the management after 1997. According to the workman the management has terminated his service w.e.f. 23-8-1997. The management has no case that there is no vacancy of Peon in which post the workman was employed. There is also no case that the workman was chargesheeted for any misconduct and there was any punishment after disciplinary action. Further there is no case of any voluntary retirement, retirement on attaining the age of superannuation of termination of services on the ground of continued ill health. That being the position, the termination of the workman from service is a clear case of retrenchment. Admittedly the management has not given him any notice, notice pay or compensation as provided under Sec. 25-F of the Act. Therefore the termination from service is unjust, illegal and the workman is entitled to be reinstated in service. There is nothing on record to show that the workman was employed

anywhere after his termination from the Bank. Hence he is eligible to get backwages as well.

8. It is now well settled that Sec. 25-F of the Act is applicable to termination of even daily rated workman who had continuously worked for the requisite statutory minimum period as held by the Supreme Court in the following decisions. In Rattan Singh v. Union of India (1998 LIC 170) held that Sec. 25-F of the Act is applicable to termination of even a daily rated workman having continuous statutory minimum period in a year and hence termination of service of such a workman without complying with Sec. 25-F of the Act is illegal. The Apex court in Deep Chandra v. State of UP ['01 (1) LLJ 742] held that violation of procedure prescribed in Sec. 25-F in case of employee having put in service for more than 240 days each year for several years, is illegal and the employee is to be reinstated in service on same conditions as before termination.

The above pronouncement of the Supreme Court fully support the view taken by me above.

9. In view of what is stated above, an award is passed holding that the action of the management of Central Bank of India in terminating the service of the workman Sri V. Prem Kumar temporary Peon, w.e.f.23-8-1997 is illegal and unjustified and hence he is entitled to be reinstated in service with all attendant benefits.

C. N. SASIDHARAN, Industrial Tribunal

APPENDIX

Witness examined on the side of the Management

MW1. Sri B. S. Chandra Mohan.

Witness examined on the side of the Workman

WW1. Sri Prem Kumar.

Documents marked on the side of the Management

Ext. M1. Photocopy of voucher dated 18-10-1994

Ext. M2. Photocopy of voucher dated 11-12-1994.

Documents marked on the side of the Workman

Ext. W1-series (2 nos.) Saving Bank Pass Book Account No. 13396.

Ext. W2-series (6 nos.) Photocopies of letters addressed to managers State Bank of Travancore, State Bank of India, Central Bank of India Regional Office. Stationary Department, Indian Overseas Bank etc. from the manager, Kadadappakkada branch of the management bank on various dates.

Ext. W3-series (4 nos.) Photocopies of certificate of merits in All India Bank Employees Association Dist. Meeting, Kollam awarded to the workman Sri Prem Kumar dated 23-11-1996.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 364.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि., जयपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (नं. सी. आई. टी.-95/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं-एल-29011/10/89-आई. आर. (विविध)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 364.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CIT-95/89) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd., Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005.

[No.L-29011/10/89-IR(Misc)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 95/89

रैफरेंस :

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल-29011/10/89 (आई. आर.)(विविध) दि. 19-9-89

राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डेकोटा ... प्रार्थी

बनाम

जयपुर मिनरल डैवेलपमेंट सिन्डीकेट प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। ... अप्रार्थी

उपस्थित :

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एंच. जे. एस.।

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

1. केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने निम्न विवाद इस अधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया है :

"Whether the action of the management of M/s. Jaipur Mineral Development Syndicate (P) Ltd., Jaipur in dismissing the services of 14 workmen

namely S/Sh Bhanwar Lal, Sarwan, Ramshi Meena, Juntha, Chhaju, Godu, Gheesa, Kalya, Ram Pratap, Mataddin Kalya S/o Parsa, Sheo Ram, Sitaram and Kishna vide their letter dt. 7-10-88 is justified ? If not, what relief are the workmen concerned entitled to ?"

2. प्रार्थी यूनियन की ओर से विवाद के संबंध में वाद-पत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार विवाद में अंकित उपरोक्त सभी श्रमिकगण अप्रार्थी संस्थान के स्थाई श्रमिक हैं तथा किसी की भी सेवाएं संस्थान में 20 वर्ष से कम नहीं हैं। सभी का काम संतोषजनक रहा है उसके बावजूद भी उपरोक्त सभी श्रमिकगण को सेवापृथक कर दिया गया। उनको सेवा मुक्त करने से पूर्व न तो उनके विरुद्ध कोई जांच कार्यवाही की गई न ही श्रमिकगण के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध हुए, इस प्रकार अनुचित व अवैध तरीके से श्रमिकगण को सेवा पृथक किया गया है। श्रमिकगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप पूर्ण रूप से दुर्भावनापूर्ण, अवैध व अनुचित श्रम नीति है। विपक्षी संस्थान का एक जरनल रैफरेंस अधिकरण के समक्ष विचाराधीन था जिससे सभी श्रमिकगण संबंधित श्रमिक हैं किन्तु धारा 33(2)(बी) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे औद्योगिक अधिनियम संबोधित किया गया है) के अन्तर्गत अधिकरण से अपूलन लेना आज्ञापक था जो नहीं लिया गया है न ही अनुमति अधिकरण से ली गई है इस प्रकार श्रमिकगण को सेवामुक्ति अधिनियम की धारा 25-एफ, जी व एच तथा धारा 33(2)(बी) के उल्लंघन में की गई है। श्रमिकगण को सेवामुक्ति से पहले न तो कोई आरोप-पत्र दिया गया न ही कोई जांच की, न छंटनी का मुआवजा या नोटिस अथवा नोटिस पे का भुगतान किया। यूनियन का कथन है कि श्रमिकगण संघ के सक्रिय सदस्य हैं अत: उनकी यूनियन गतिविधियों के कारण उन्हें सेवा से अलग किया गया है जो अवैध व अनुचित है। जिन श्रमिकगण ने प्रार्थी यूनियन को छोड़ दिया और समझौता कर लिया इन्हें सेवा में रख लिया गया है बाकी उपरोक्त 14 श्रमिकों को सेवामुक्ति के दण्ड से दण्डित किया गया है। श्रमिकगण के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। अत: यूनियन की प्रार्थना है कि सभी श्रमिकगण को समस्त पिछले वेतन व लाभ सहित सेवा में बहाल किया जावे।

अप्रार्थी ने वाद-पत्र का जवाब दावा पेश किया है जिसमें प्रारंभिक आपत्ति ली गई है कि प्रार्थी यूनियन ने संबंधित श्रमिकों का अधिकार पत्र तथा विवाद प्रस्तुत करने के लिए अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण प्रार्थी यूनियन का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

4. गुणावगुण पर अप्रार्थीगण ने जवाब दिया है कि प्रस्तुत विवाद केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया अनाधिकृत तौर पर प्रस्तुत किया गया है, संबंधित श्रमिकों का कार्य कभी भी संतोषप्रद नहीं रहा, अप्रार्थी संस्थान के पास इन श्रमिकों के विरुद्ध गंभीर दुराचरण एवं अनुशासनहीनता की शिकायत थी, वे हमेशा तोड़-फोड़, मारपीट एवं भय तथा आतंक का वातावरण उत्पन्न करने एवं संस्थान के वफादार कर्मचारियों को अनुशासनहीनता व हिंसक कार्यवाही में लिप्त करने व संस्थान के विरुद्ध उकसाने व भड़काने में अग्रणी रहे हैं जिसके लिए उन्हें पूर्व में भी गंभीर दुराचरण के आरोप पत्र दिये गये हैं। दिनांक 16-9-88 को करीब 4.45 बजे शाम ये श्रमिकगण अन्य 25-30 व्यक्तियों के साथ अवैध रूप से कुल्हाड़ी, सरिये, पत्थर व लाठियां लेकर जबर्दस्ती संस्थान के खान के ऑफिस का फाटक खोलकर दाखिल होने लगे। ऑफिस के फाटक पर लगी पुलिस गार्ड ने इन श्रमिकों को पहचान लिया और मना किया तो घासी धानका ने बक्शसिंह हैड कान्सटेबल के सिर पर पाईप को मारी जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े, इतनी ही नहीं ऑफिस में कार्यरत वी. सी. श्रीमाल माइन्स मैनेजर, हरफूल मीणा, माइन्स मेट, भुवनेश्वर माइन्स फोरमैन रामकिशन भातरा स्टोर इन्चार्ज, रणजीत कुमार भट्टाचार्य माइन्स मैट, अकाउन्टस ऑफिसर श्री रामजीलाल शर्मा, भगवान सहाय लुहार समय पालक, राधेश्याम यादव, कार्मिक ऑफिसर, अरशद अली खान मिल इन्चार्ज पर भी इन व्यक्तियों एवं इनके साथियों ने वार किया, मारपीट की और चिल्लाकर कहा इनको जान से मारेंगे, वे खून से लथपथ अपनी जान बचाने को इधर उधर भागे, कुछ गेस्ट हाउस की तरफ भाग गये और उसमें घुसकर दरवाजा बंद कर लिया तब इन श्रमिक व इनके साथियों ने गैस्ट हाऊस की खिड़कियां व दरवाजे तोड़ डाले व अंदर घुस गये व उक्त लोगों को जान से मारने के इरादे से पूरी तरह मारपीट कर लहु लुहान कर दिया। माइन्स मैनेजर वी. सी. श्रीमाल से जबर्दस्ती लिखवा लिया कि 16-9-88 को सुबह जिन 9 श्रमिकों को सस्पैंड किया गया है उनके आर्डर को निरस्त किया जाता है एवं उस दिन सुबह पाली में जिन लोगों ने कार्य नहीं किया है उनकी हाजिरी दी जायेगी। इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थान की ओर से पुलिस थाना जमुवा रामगढ़ में दर्ज कराई गई। इन लोगों ने मारपीट करने, अशांति फैलाने, संस्थान में तोड़-फोड़ करने, संस्थान में कार्यरत लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने व संस्थान को नुकसान पहुंचाने का असफल प्रयास किया और ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि इनके विरुद्ध कोई जाँच नही की जा सकी व ही कोई इनके विरुद्ध गवाही देने की हिम्मत कर सका। इसलिए ये श्रमिक संस्थान के लिए विश्वसनीय व्यक्ति नहीं रहे और इस प्रकार से संस्थान को विश्वास इन पर से उठ गया व प्रबन्धन जांच की औपचारिकता में अपने आप को असमर्थ पा रहा था तथा औपचारिक कार्यवाही पुलिस थाना जमुवारामगढ़ में तफतीश चल रही थी जिसके कारण जांच कार्यवाही किया जाना उचित एवं आवश्यक नहीं थी और जांच की औपचारिकता में प्रयास करना असंभव होने के कारण उक्त परिस्थितियों में इन श्रमिकगण का बिना आरोप पत्र दिये व बिना जांच किये सेवा मुक्त किया जाना उचित एवं वैध है व नियमानुकूल है।

5. अप्रार्थी ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि अप्रार्थी संस्थान के विरुद्ध एक अन्य रैफरेंस अधिकरण के समक्ष 4/88 लंबित था, परन्तु उस रैफरेंस में वर्णित तथ्य औद्योगिक विवाद की श्रेणी में नहीं आते और इन श्रमिकों को उक्त विवाद से संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए विपक्षी संस्थान ने धारा 33(2)(बी) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है क्योंकि इनकी सेवा मुक्ति के अनुमोदन व अनुज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्रमिकगण को दुराचरण के आरोप में निकाला गया है इसलिए धारा 25-एफ, जी व एच तथा एन एवं धारा 33 के प्रावधान लागू नहीं होते न ही संस्थान ने इनका उल्लंघन किया है और जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के वाद को खारिज किया जाये तथ नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाये।

6. दुराचरण के आरोप पर निकाले जाने के कारण संबंधित सभी श्रमिकगण को अंतरिम राहत दिलाने हेतु अंतरिम पंचाट पारित किया गया जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार पारित हुआ। विपक्षी संस्थान ने दिनांक 31-3-92 को इस अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि जो विवाद न्याय निर्णयार्थ अधिकरण को प्रस्तुत किया गया है उसमें श्रमिकों के विरुद्ध गंभीर दुराचरण के आरोप हैं। विपक्षी संस्थान में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी जो संभव नहीं हो सकी इसलिए विपक्षी को संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने की न्यायालय में इजाजत दी जावे। उनकी इस प्रार्थना पर न्यायालय ने विपक्षी संस्थान को साक्ष्य पेश करने की इजाजत दे दी। विपक्षी संस्थान ने श्रमिकों के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए साक्षी रामजी लाल शर्मा, राम किशन, भुवनेश्वर सिंह, राधेश्याम यादव तथा अर्शद अली के शपथ पत्र पेश किये हैं जिनसे अप्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है। अप्रार्थी ने प्रदर्श एम-1 लगायत एम-31 तक दस्तावेज पेश किये। इसके खण्डन में प्रार्थीगण की ओर से श्रमिक भंवर लाल, श्रवण, झूंता, राम प्रताप एवं रमसी मीणा के शपथ पत्र पेश हुए जिनसे अप्रार्थीगण ने जिरह की। प्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया। दोनों पक्षों को साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात दोनों पक्षों के विद्वान प्रतिनिधिगण की बहस सुनी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपने तर्कों में सर्वप्रथम प्रारंभिक ऐतराज उठाया है कि यह विवाद सक्षम व्यक्तियों द्वारा नहीं उठाया गया है। प्रार्थी यूनियन द्वारा जिन संबंधित यूनियन के श्रमिकों के संबंध में क्लेम पेश किया गया है उसे नियमानुसार नहीं माना जा सकता। वे इस यूनियन के सदस्य हैं या नहीं इसका कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। संबंधित श्रमिकों द्वारा यूनियन को अपना विवाद उठाये जाने बाबत कोई अधिकार पत्र भी पेश नहीं किया गया है तथा यूनियन द्वारा विवाद उठाये जाने संबंधी जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसकी प्रति भी न्यायालय में पेश नहीं की गई है इसलिए यह विवाद चलने योग्य नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने दीपक इण्डस्ट्रीज लि. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1975 लैब. आई. सी. 1153 (कलकत्ता) का प्रोद्धरण प्रस्तुत किया है।

8. इसके विपरीत प्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने तर्क दिया है कि यह विवाद श्रमिकगण के सेवा मुक्ति के संबंध में है और धारा 2-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्तिगत श्रमिक या श्रमिकों के सेवा मुक्ति के विवाद को औद्योगिक विवाद माना गया है और ऐसे विवाद को उठाने के लिए श्रमिक को भी अधिकृत किया गया है इसलिए निश्चित तौर पर चूंकि यह विवाद सेवा मुक्ति से संबंधित है और औद्योगिक विवाद है जिसको उठाने का प्रार्थी यूनियन के साथ श्रमिकों को भी अधिकार है।

9. मैंने दोनों पक्षों के इस तर्क पर गंभीरता से विचार किया और प्रस्तुत प्रोद्धरणें को आदर सहित पढ़ा। मेरे विनम्र मत में अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रोद्धरण भिन्न तथ्यों पर आधारित है और चूंकि यह विवाद श्रमिकों की सेवा मुक्ति से संबंधित है, इसलिए औद्योगिक विवाद की परिभाषा में आता है जिसको उठाने का श्रमिकों को भी अधिकार है और श्रमिकों ने अपना बयान दिया है, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि यह विवाद असक्षम व्यक्ति द्वारा उठाया गया है और अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का यह तर्क मानने योग्य नहीं है।

10. यह निर्विवाद सत्य है कि विवाद से संबंधित सभी 14 श्रमिकगण को दुराचरण के आरोप में सेवा मुक्त किया गया है। यह भी सत्य है कि इन श्रमिकों का विपक्षी संस्थान के मध्य एक अन्य विवाद इस अधिकरण के समक्ष आई. टी. 4/88 लंबित था। अप्रार्थी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि धारा 33(2)(बी) अधिनियम के अन्तर्गत इस सेवा मुक्ति की बाबत इस अधिकरण के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और धारा 33(2)(बी) अधिनियम के अन्तर्गत इस सेवा मुक्ति का कोई अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया। अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का मात्र यह तर्क है लंबित रैफरेंस औद्योगिक विवाद से संबंधित नहीं है और उपरोक्त श्रमिकगण उस रैफरेंस से संबंधित श्रमिक नहीं है। इस कारण धारा 33(2)(बी) के अन्तर्गत अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं थी और अपने तर्क के समर्थन में अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने निम्न प्रोद्धरण प्रस्तुत किये हैं :

1. 1959(1) एल. एल. जे. 282
2. 1973 लैब. आई. सी. 1002 (मैसूर) ओ. ए. औमेन/ओ. ए. अब्राहम बनाम मैनेजमेंट ऑफ हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लि.।

11. इसके विपरीत प्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने तर्क दिया है कि जो रैफरेंस लंबित था वह संस्थान के श्रमिकों एवं संस्थान के मध्य था और इस विवाद सं संबंधित श्रमिक ही उस विवाद में भी श्रमिक हैं तथा वह विवाद इन श्रमिकों की मजदूरी से संबंधित होने के कारण औद्योगिक विवाद है इसलिए ऐसे औद्योगिक विवाद से संबंधित श्रमिकों को किसी अन्य मामले में दुराचरण के आरोप में भी सेवा मुक्ति धारा 33(2)(बी) अधिनियम के अन्तर्गत इस अधिकरण के अनुमोदन के बिना नहीं माना जा सकता और इस संबंध मे अप्रार्थी संस्थान ने अनुमोदन का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया इसलिए सेवा मुक्ति अपने आप में अवैध एवं व्यर्थ है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक बनाम राम गोपाल शर्मा 2002(1) एस. सी. का प्रोद्धरण प्रस्तुत किया है।

12. मैंने इस संबंध में दोनों पक्ष के विद्वान प्रतिनिधिगण के तर्कों पर विचार किया, प्रस्तुत किये गये प्रोद्धरणों को आदर सहित पढ़ा। चूंकि विवाद श्रमिकों की मजदूरी के संबंध में है और निश्चित तौर पर औद्योगिक विवाद है तथा इन्हीं श्रमिकों के लिए होने के कारण पूर्व विवाद से ये श्रमिक संबंधित श्रमिक हैं जिन्हें दुराचरण के आरोप में सेवा मुक्त किया गया है परन्तु धारा 33(2)(बी) अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया इसलिए जैसा कि जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक बनाम राम गोपाल शर्मा के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, उसके अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को की गई यह सेवा मुक्ति पूर्णतया अवैध व शून्य हो जाती है। अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिन दोनों प्रोद्धरणों को प्रस्तुत किया है उनमें प्रतिपादित सिद्धान्त भिन्न तथ्यों पर हैं जिनसे अप्रार्थी को कोई लाभ नहीं पहुंचता।

13. प्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने मेरे समक्ष यह भी तर्क दिया है कि अप्रार्थी ने प्रार्थीगण की सेवा मुक्ति दुराचरण के आरोप में की है परन्तु न तो उन्हें कोई आरोप पत्र दिया और आरोप पत्र के बिना जांच भी नहीं की और बिना जांच के ही सेवा मुक्ति की गई जो अवैध है। अप्रार्थी की प्रार्थना पर इस अधिकरण के समक्ष जांच की गई है और अप्रार्थी ने पांच साथियों के बयान कराये हैं लेकिन ये बयान किस बाबत कराये हैं, बिना आरोप पत्र के ये श्रमिक समझने में असमर्थ रहे हैं और जब तक आरोप पत्र नहीं दिया जाता और श्रमिकगण को आरोप पत्र पढ़कर नहीं सुनाया जाता, उसके अभाव में वे अपना बचाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं है कि उनके विरुद्ध क्या आरोप है। आरोप पत्र किसी भी जांच का अनिवार्य अंग है, बिना आरोप पत्र के कोई जांच सम्पन्न ही नहीं की जा सकती इसलिए यह साक्ष्य जो अधिकरण के समक्ष पेश हुई है, पूर्णतया व्यर्थ है जिसे आरोप पत्र के अभाव में प्रार्थीगण के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता और प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई दुराचरण साबित नहीं होता। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने निम्नलिखित प्रोद्धरण प्रस्तुत किये हैं :

1. पंजाब नेशनल बैंक लि. बनाम ऑल इण्डिया पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईज फेडरेशन व अन्य, ए. आई. आर. 1960 (एस. सी.) 160

2. यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम के. वी. जानकीरमण, ए. आई. आर. 1991 (एस. सी.) 2010

3. जी. चन्द्रकान्त बनाम गुन्टूर डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स लि. व अन्य 1995 एल. एल. जे. 668 (आन्ध्र प्रदेश)

14. इसके प्रतिकूल अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का तर्क है कि यह सही है कि संबंधित श्रमिकगण को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया और अप्रार्थी द्वारा कोई जांच किये बिना सेवा मुक्ति की गई है। परन्तु संबंधित श्रमिकगण ने प्रबन्धन के अधिकारियों एवं कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट कर ऐसा वातावरण पैदा कर दिया और इतना भय व आतंक फैला दिया और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई जिस कारण आरोप पत्र दिया जाना और कोई जांच करना किसी भी प्रकार संभव नहीं था, इसके विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने न्यायालय से जमानत कराई। इस समस्त श्रमिकगण के विरुद्ध न्यायालय में गंभीर आपराधिक कृत्य का आरोप पत्र पेश हुआ जिसमें न्यायालय द्वारा विचारण किया गया और अपराध साबित पाये जाने पर दोष सिद्ध किये गये हैं। ऐसी परिस्थिति में किसी आरोप पत्र की व जांच की आवश्यकता ही नहीं थी। न्यायालय के समक्ष उक्त आरोप की जांच की गई है, इसमें भी आरोप पत्र दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अप्रार्थी ने प्रार्थीगण के वाद का जो जवाब दावा पेश किया है उसमें वे समस्त तथ्य वर्णित हैं जो आरोप पत्र का भाग माने जा सकते हैं जिनको साक्ष्य से अप्रार्थी ने साबित कराया है। इसलिए अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का यह कहना कि उन्हें आरोप का मालूम नहीं था, गलत है। अप्रार्थी ने अपनी साक्ष्य से समस्त वर्णित तथ्यों को साबित कराया है तथा श्रमिकगण के विरुद्ध दुराचरण का आरोप साबित किया है। इसलिए प्रार्थीगण का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान प्रतिनिधि ने बहुत से न्यायनिर्णय पेश किये हैं जिनको मैंने आदर सहित पढ़ा है परन्तु इन निर्णयों में किसी में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया गया है कि आरोप पत्र दिये बिना दुराचरण को साबित किया जा सकता हो।

15. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर गंभीरता से विचार किया। प्रस्तुत किये गये प्रोद्धरणों को आदर सहित पढ़ा। जैसा कि पंजाब नेशनल बैंक बनाम ऑल इण्डिया पंजाब नेशनल बैंक एम्पलाईज फैडरेशन एवं यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम के. वी. जानकीरमण के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कोई भी आपराधिक कार्यवाही या विभागीय जांच बिना आरोप पत्र के शुरू नहीं की जा सकती और आरोप पत्र दिया जाना आवश्यक है। जी. चन्द्रकान्त बनाम गुन्टूर गुन्टूर डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स लि. के मामले में माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विभागीय जांच में दोषी कर्मचारी को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्टत: संक्षिप्त में लेकिन पूर्णतया शुद्ध रूप में सुनाया जाना आवश्यक है। इन प्रोद्धरणों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी आरोप पत्र दिया जाना आवश्यक है। मैं अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि आरोप पत्र दिया जाना और जांच करना संभव नहीं था। तत्समय ऐसी परिस्थितियां पैदा हो भी गई हों तब भी अप्रार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुराचरण के संबंध में साक्ष्य की अनुमति चाही है लेकिन उस प्रार्थना पत्र के साथ भी किसी तरह का कोई आरोप पत्र बनाकर श्रमिकों को नहीं दिया गया है। मेरे विनम्र मत में किसी भी व्यक्ति को हत्या के अपराध में मृत्यु दण्ड दिये जाने से पूर्व उसका विचारण करना आवश्यक है और विचारण के लिए उसके विरुद्ध आरोप तय किया जाना अनिवार्य अंग है जो आरोप पत्र के माध्यम से ही हो सकता है। बिना आरोप सुनाये श्रमिक यह समझने में निश्चित तौर पर असमर्थ है कि उसके विरुद्ध क्या आरोप है जिसका कि उसे बचाव करना है। हस्तगत प्रकरण में श्रमिकों को कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया न उन्हें आरोप सुनाये गये न उन्हें आरोप के बारे में बताया गया बल्कि अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सीधे ही अप्रार्थी को साक्ष्य की अनुमति दे दी गई और उन्होंने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत कर दी लेकिन आरोप पत्र के अभाव में यह साक्ष्य बेमानी है जिसे दुराचरण साबित नहीं हो सकता।

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"1. सर्वश्री छाजू, घीसा व काल्या पुत्र परसा, जिन्होंने अप्रार्थी से समझौता कर प्रमाणित करा लिया और जिनके संबंध में समझौते के आधार पर पंचाट पूर्व में पारित हो चुका है, को छोड़कर शेष सभी श्रमिकगण को अप्रार्थी द्वारा 7-10-88 को सेवा मुक्त करना अनुचित व अवैध है, जिसे अपास्त किया जाता है। उक्त सभी शेष श्रमिकगण सेवा में पुन: बहाल होने के व पिछला समस्त वेतन एवं अन्य लाभ मय सेवा की निरन्तरता के प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

2. चूंकि श्रमिक गोदू की मृत्यु हो चुकी है अत: उसे विधिक वारिसान उसकी मृत्यु दिनांक तक का समस्त वेतन व अन्य आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है।

3. सर्वश्री छाजू, घीसा एवं काल्या पुत्र परसा के संबंध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाता है।"

17. उपरोक्त आशय का अवार्ड प्रकरण में पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे। अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 365.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. राजस्थान स्टेट टंगस्टन डव. कारपो. लि., जयपुर के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 22/90) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29011/39/89-आई. आर. (विविध)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 365.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (No. C.I.T. 22/90) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Rajasthan State Tungstone Dev. Corp. Ltd., Jaipur and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005.

[No. L-29011/39/89-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 22/90

रैफरैंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. सं. एल. 29011/39/89-आई. आर. (विविध) दिनांक 9 मार्च, 1990 ।

अध्यक्ष, टंगस्टन माइन्स मज़दूर संघ, डेगाना जिला नागौर। .....प्रार्थी

बनाम

महाप्रबन्धक, मैसर्स राजस्थान स्टेट टंगस्टन डैवलपमैंट कारपोरेशन लि., सी-196, उदय मार्ग, तिलक नगर,जयपुर। ....अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री एम. एफ. बेग

अप्रार्थी की ओर से : कोई नहीं

दिनांक : 13-10-2004

अवार्ड

1. केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक उपरोक्त द्वारा निम्न विवाद इस अधिकरण को अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया गया है :

"Whether the action of the management of M/s. R.S.T.D.C. Ltd., Jaipur in terminating the services of the following workmen w.e.f. the dates mentioned against each is justified If not, what relief are the workmen concerned entitled to ?

S.No.	Name	Date of termination
1.	Smt. Gyarsi/Narayan	11-12-85
2.	Smt. Patasi/Birma	11-12-85
3.	Smt. Sayari/Girdhari	11-12-85
4.	Smt. Jannat/Gaffur	11-12-85
5.	Shri Banshi/Ramrakha	11-12-85
6.	Shri Pancch/Rupa	11-12-85
7.	Shri Phusa/Purkha	11-12-85
8.	Shri Bheru/Indra	11-12-85
9.	Shri Kesha/Mangu	11-12-85
10.	Shri Rampal/Dharu	11-12-85
11.	Shri Banshi/Moda	11-12-85
13.	Mansukha/Narayan	11-12-85
14.	Lakshman/Heera	11-12-85
15.	Smt. Nathdi/Mallaram	22-12-86
16.	Shri Chhogaram/Manguram	10-7-87
17.	Shri Chunnilal/Bhaguram	7-9-87

2. उक्त रैफरैंस के अनुसार प्रार्थी यूनियन की ओर से यद्यपि सेवामुक्त किये गये 17 श्रमिकों का क्लेम पेश किया गया है परन्तु विवाद से संलग्न अनुसूची के क्रम सं. 16 पर दर्शाये छोगा राम व 17 पर दर्शाये चुन्नी लाल ने अप्रार्थी से समझौता कर लिया है और दिनांक 16-11-85 को श्रमिक सं. 16 एवं 17 के लिए नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जा चुका है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में श्रमिक सं. 16 एवं 17 का विवरण यहां नहीं दिया जा रहा है। शेष श्रमिकों के लिए प्रार्थी ने जो वाद पत्र पेश किया है उसके अनुसार श्रमिक सं. 1 से

14 की नियुक्ति अप्रार्थी संस्थान में थी और उनको अवैध तौर पर मेडीकली अनफिट बताते हुए आदेश दिनांक 11-12-85 द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया। उनको धारा 25-एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे बाद में अधिनियम संबोधित किया गया है) के अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया व नोटिस के एवज़ में कोई वेतन नहीं दिया गया। अप्रार्थी द्वारा राजकीय चिकित्सक की बजाय मनमाने तौर पर अन्य चिकित्सक का बोर्ड बनाकर उनसे मनमाने तौर पर डॉक्टरी का प्रमाण पत्र लिया गया जिनमें "अनफिट" शब्द बाद में बढ़ा लिया गया, उनकी कहीं कोई नियमानुसार डाक्टरी नहीं की गई। उनके द्वारा इस संबंध में विवाद करने पर सभी श्रमिकों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित अपीलीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हरेने के लिए कहा गया लेकिन किसी अपीलीय मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया गया। फिर राज्य के मेडीकल बोर्ड से मेडिकल कराने की अनुमति उनसे प्राप्त की गई परन्तु उनका कोई मेडिकल नहीं कराया गया और उन्हें सेवामुक्त कर दिया गया। श्रमिक सं. 15 श्रीमती नाथड़ी को एक वर्ष पूर्व ही 22-12-86 को 60 वर्ष की आयु मानते हुए सेवानिवृत कर दिया गया जो भी सेवा पृथककरण ही है व अनुचित व अवैध है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि अप्रार्थी के रजिस्टर में नाथड़ी की आयु 60 वर्ष मानते हुए सेवा मुक्ति की गई है, चिकित्सा बोर्ड द्वारा नाथड़ी की परीक्षण के पश्चात् आयु 42 वर्ष दर्शाई गई थी जिसका पत्र क्लेम के साथ प्रदर्श डब्ल्यू-II है जो जांच 29-11-85 को की गई थी। नाथड़ी द्वारा नियुक्ति के समय उसकी जन्म तिथि 28-3-40 अंकित की गई थी और इस आधार पर ही नाथड़ी की सेवा निवृत्ति 58 वर्ष की आयु होने के पश्चात् की जानी थी इससे पूर्व सेवा मुक्त करने पर नियमानुसार उसे तीन माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिये था जो नहीं दिया गया। नाथड़ी की जन्म पत्री प्रदर्श डब्ल्यू-12 है, उसके द्वारा दिया गया मांग पत्र प्रदर्श 13 है। इस प्रकार नाथड़ी की भी सेवा निवृति गलत की गई है जो छंटनी की परिभाषा में आती है और धारा 25-एफ अधिनियम की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार प्रार्थना की गई है कि इन समस्त श्रमिकों के सेवा पृथक आदेश अनुचित व अवैध घोषित किये जायें, उन्हें सेवा पृथक तिथि से ही निरन्तर सेवा में माना जाये और उन्हें बकाया वेतन दिलाया जाये। चार श्रमिकगण पांचू, भैरू, बंशी व लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है जिनकी सेवामुक्ति को अवैध घोषित किया जाकर उनकी मृत्यु होने तक समस्त आर्थिक लाभ उनके वारिसान को दिलाये जायें।

4. अप्रार्थी की ओर से उक्त वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार विधिक आपत्ति यह ली गई है कि अप्रार्थी राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लि. का संचालन दिनांक 4-6-91 से केन्द्रीय उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान ज़िंक लि. को हस्तान्तरित कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थी संस्थान अब विद्यमान नहीं है इसलिए इसके विरुद्ध वाद चलने योग्य नहीं है।

5. गुणावगुण पर वाद पत्र का जवाब पेश किया गया है जिसके अनुसार श्रमिक सं. 1 से 14 तक की सेवाएं सामयिक स्वास्थ्य परीक्षा में कार्य करने योग्य नहीं पाये जाने के कारण दिनांक 11-12-85 को समाप्त की गई हैं। नाथड़ी की सेवा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित सेवा निवृति आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत की गई हैं। नाथड़ी सेवानिवृति की आयु प्राप्त कर चुकी थी। श्रमिक सं. 1 से 14 स्वास्थ्य परीक्षण में कार्य करने योग्य नहीं थे, उनकी छंटनी नहीं की गई है इसलिए धारा 25-एफ अधिनियम की पालना का प्रश्न नहीं उठता। नाथड़ी को सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी आदि लाभ प्राप्त करने के लिए सूचित कर दिया गया। चार श्रमिक पांचू, भैरू, बंशी व लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है वे भी स्वास्थ्य परीक्षण में कार्य करने योग्य नहीं पाये गये थे। मृतक श्रमिक की ओर से प्रार्थी संघ को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इन किसी भी श्रमिक ने अपीलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कोई आवेदन नहीं किया। ऐसी स्थिति में इनका स्वास्थ्य परीक्षण स्वीकार था। श्रमिकों से अन्डरग्राउन्ड व सरफेस पर कार्य लिया जाता रहा है जिसके लिए चिकित्सकों ने उन्हें योग्य व सक्षम घोषित नहीं किया जो कि दक्ष चिकित्सक थे, इसलिए उन्हें सेवा पृथक करना आवश्यक था। इसलिए श्रमिक सं. 1 से 14 की सेवामुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर की गई है जो वैध है। नाथड़ी की आयु 60 वर्ष हो जाने से सेवानिवृत किया गया है जो भी वैध व उचित है और प्रार्थीगण किसी प्रकार की राहत पाने के अधिकारी नहीं हैं।

5. प्रार्थी संघ की ओर से श्रमिक पूरण, श्रीमती ग्यारसी, श्रीमती पतासी, श्रीमती जन्नत, पूसा, श्रीमती नाथड़ी के शपथपत्र पेश हुए हैं एवं एक अन्य शपथ पत्र प्रार्थी संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह का पेश हुआ है जिनसे अप्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है। अप्रार्थी की ओर से डाक्टर एस. आर. सोनी जिसने इन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है तथा श्री के. डी. एस. राजावत जो अप्रार्थी निगम में कनिष्ठ प्रबन्धक हैं, के शपथ पत्र पेश हुए हैं जिनसे प्रार्थीगण के विद्वान प्रतिनिधि ने जिरह की है और दोनों ओर से दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं।

6. मैंने प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया।

7. जहां तक श्रमिक सं. 1 से 14 का प्रश्न है, जिनमें चार श्रमिकों की मृत्यु भी हो चुकी है लेकिन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विवाद में मृत्यु हो जाने से विवाद उपशमित नहीं हो जाता इसलिए सभी 14 श्रमिकों की बाबत साक्ष्य का विवेचन किया जा रहा है। इन 14 श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाये जाने के आधार पर हटाया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉ. सोनी का शपथ पत्र पेश हुआ है जिससे जिरह भी की गई है। जिरह में उसने स्पष्टतौर पर स्वीकार किया है कि उसे अप्रार्थी निगम ने संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु नियुक्त किया था जिसका आदेश प्रदर्श एम-8 है एवं एक अन्य आदेश प्रदर्श एम-34 है। उसने इन श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया था जिनके बाबत प्रमाण पत्र जारी किये थे। स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श डब्ल्यू-30, 34, 5, 8, 1 है। इस परीक्षण के समय किसी भी श्रमिक का स्टूल, मूत्र, रक्त टैस्ट नहीं किया। इनका एक्सरे नहीं कराया क्योंकि एक्सरे के लिए श्रमिकों ने इनके नेता मोहन सिंह द्वारा मिसगाईड करने पर सहमति नहीं दी। ग्यारसी की आंख खराब थी जो टार्च से देखी थी जो फूटी हुई थी। दाईं आंख ठीक थी जिसका वीज़न 6/12 है परन्तु यह सर्टीफिकेट में दर्ज नहीं किया। पतासी का प्रमाण पत्र प्रदर्श डब्ल्यु-34 है, इसमें वह चल फिर नहीं सकती थी, न्यूरोलोजीकल डिफैक्ट था, इसकी ई. सी. जी. नहीं कराई। उसे चलाकर देखा तो चल नहीं सकती थी। परन्तु प्रदर्श

34 में इसका उल्लेख नहीं किया। इस तरह इस साक्षी की जिरह से स्पष्ट है कि माईन्स रूल्स 1955 के अन्तर्गत बताये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ और न ही नियमानुसार तीन प्रतियों में प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनकी एक प्रति श्रमिक को नहीं दी गई। इस प्रकार यह स्वास्थ्य परीक्षण मनमाने तौर पर किया गया है। प्रदर्श डब्ल्यू-35 में ए से बी स्थान पर "अनफिट" शब्द बाद में लिखा हुआ है, अन्य प्रमाण पत्रों में भी अनफिट शब्द ही लिखा है लेकिन इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। श्रमिकों द्वारा ऐतराज करने पर सभी 14 श्रमिकों को अपीलेट मेडीकल बोर्ड के समक्ष पेश होने के लिए पत्र दिये गये हैं जिसमें अंकित किया गया है कि यदि अपीलेट मेडीकल बोर्ड द्वारा उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया तो वे सेवा में इसी प्रकार बने रहेंगे मानो उनकी सेवा मुक्ति नहीं की गई हो। परन्तु अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार अपीलेट मेडीकल बोर्ड गठित नहीं किया गया है। फिर सभी 14 श्रमिकों को पत्र दिया गया जो अभिलेख पर हैं, कि अपीलेट बोर्ड का गठन नहीं हुआ है इसलिए राज्य सरकार के मेडीकल बोर्ड से उनके परीक्षण हेतु सहमति दी जावे जिस पर सभी श्रमिकों ने सहमति प्रदान कर दी फिर भी इनका राज्य सरकार के मेडीकल बोर्ड द्वारा कभी भी कोई स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया और इन पत्रों के आधार पर यह स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि जो पूर्व में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, उसका अस्तित्व नहीं माना गया। ऐसी सूरत में ऐसे स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उनको कार्य के लिए अयोग्य मानते हुए सेवा पृथक किया गया है वह विधिक नहीं है।

8. इसी प्रकार श्रीमती नाथड़ी को 60 वर्ष की आयु की बताकर सेवा निवृत किया गया है जबकि अप्रार्थी संस्थान में सेवा निवृति आयु 58 वर्ष ही है। एक वर्ष पूर्व किये गये चिकित्सा परीक्षण में उसकी आयु 42 वर्ष थी और नियुक्ति के समय प्रस्तुत जन्म पत्री के अनुसार नाथड़ी की जन्म तिथि 9-3-40 बताई गई है जिसके अनुसार वह 58 वर्ष की पूरी नहीं होती 58 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज़ या साक्ष्य अप्रार्थी को अभिलेख पर नहीं है, ऐसी सूरत में नाथड़ी को भी गलत सेवा निवृति की गई है जो छंटनी की तारीफ में आती है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

> "श्रमिक सं. 1 से 14 तक की स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर अप्रार्थी द्वारा की गई सेवा मुक्ति दिनांक 11-12-85 तथा श्रमिका सं. 15 श्रीमती नाथड़ी की आयु के आधार पर की गई सेवा निवृति दिनांक 22-12-86 अनुचित एवं अवैध है, जिसे अपास्त किया जाता है। समस्त श्रमिकगण सेवा में बने रहने के अधिकारी हैं तथा पिछला बकाया वेतन व अन्य सभी लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है। मृतक श्रमिकगण के वारिसान उनकी मृत्यु की तिथि तक का समस्त वेतन व भत्ते प्राप्त करने के अधिकारी है।"

10. अवार्ड आज दिनांक 13-10-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 366.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 9/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29025/6/2005-आई. आर. (विविध)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 366.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (C.I.T. 9/89) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005.

[No. L-29025/6/2005-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 9/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री गोदू पुत्र श्री छाजू मीना उम्र 49 वर्ष, निवासी ग्राम-पोस्ट बोरोदा वाया सैंथल, तहसील-दौसा, जिला जयपुर। .....प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस-प्रेम प्रकाश, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर।

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि., डग्गेता, तहसील जुमुवा रामगढ़ जिला जयपुर। .....अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. पापड़ीवाल

अवार्ड दिनांक : 6-11-2004

अवार्ड

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि., जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स, डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस में संबंधित नहीं कहा जा सकता, अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया था, अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अत: प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई।

(5) उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरैंस सं. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

(6) चूंकि अब रैफरैंस सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है और प्रार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण समस्त लाभ उसके विधिक वारिसान को दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(7) अत: प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :—

"चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी के विधिक वारिसान को समस्त आर्थिक लाभ दिलाये गये हैं, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

(8) अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 367.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 10/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29025/7/2005-आई. आर. (विविध)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 367.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. C.I.T. 10/89) of the Central Industrial Tribunal Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005.

[No. L-29025/7/2005-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 10/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री छाजू पुत्र भौरिया जोगी मीना उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम-नैतावाला, पो. नीमला वाया सैंथल तह. जमुवा रामगढ, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस-प्रेम प्रकाश, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर।

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि., डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर। ....अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवेलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि., जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स, डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उनके श्रमिकगण के मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति करने से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध एवं अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जावे एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जावे।

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए अधिनियम का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया था, अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अत: प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई।

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरैंस सं. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

6. अब चूंकि रैफरैंस सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी से समझौता कर लेने के कारण नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. अत: प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :—

> "चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी के संबंध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

8. अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 368.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि, के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 11/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29025/8/2005-आई. आर. (विविध)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 368.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (No. C.I.T. 11/89) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005.

[No. L-29025/8/2005-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 11/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री सीताराम पुत्र श्री जगन्नाथ, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम डगोता पोस्ट नीमला बाया सैंथल, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस-प्रेम प्रकाश, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर।

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि., डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर। ....अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

(1) प्रार्थी श्री सीताराम ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जावे एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जावे।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अत: प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरूद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई

उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई।

(5) उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरैंस सं. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

(6) अब चूंकि रैफरैंस केस नं. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(7) अत: प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

(8) अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 369.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी.आई.टी.-12/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-29025/9/2005-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 369.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (C.I.T.-12/89) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L-29025/9/2005-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 12/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री कल्याण पुत्र सोहन कुमार उम्र 44 वर्ष,
निवासी ग्राम-पोस्ट सैंथल, तहसील दौसा,
जिला जयपुर ... प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस—प्रेम प्रकाश, एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरैक्टर।
2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि., डगोता तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर। ... अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी.एल. हिस्सारिया, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे.के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर.सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि., जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स, डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक

सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरैंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चुंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये।

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था अत: प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेपित किया गया है, अत: अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई है।

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रेफरैंस सं. सी.आई.टी. 95/89 निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

6. अब चूंकि रेफरैंस केस नं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. अत: प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"चूंकि प्रकरण सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

8. अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी.एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 370.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमैंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी.आई.टी. 15/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29025/2/2005-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 370.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (C.I.T. 15/89) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L-29025/2/2005-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई. टी. 15/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औधोगिक विवाद अधिनियम, 1947

कल्या पुत्र परसा मीना उम्र 50 वर्ष,
निवासी कालेड़ा पो. समरा तहसील यानागाजी,
जिला अलवर . . . प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस-प्रेम प्रकाश, एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर।

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डैवलपमैन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर। . . . अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी.एल. हिस्सारिया, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे.के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर.सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषजनक रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डागौता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला। अधिकरण के समक्ष विपक्षी एवं उसके श्रमिकगण के मध्य एक जनरल रैफरैंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक हैं किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्ति करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध एवं अनुचित है। प्रार्थी चुंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जावे व उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जावे।

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था अत: प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने के प्रार्थना की गई।

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रेफरैंस सं. सी.आई.टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

6. अब चूंकि रेफरैंस सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी से समझौता कर लेने के कारण नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. अत: प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"चूंकि प्रकरण सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी के संबंध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का यह प्रर्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।"

8. अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी.एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 371.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजक और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी.आई.टी.-6/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-29025/3/2005-आई. आर. (विविध)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 371.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (C.I.T.-6/89) of the Central Industrial Tribunal Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L-29025/3/2005-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई. टी. 6/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री श्रवण पुत्र भूरा मीना, उम्र 55 वर्ष,
निवासी ग्राम-पोस्ट मंहगी, वाया आंधी, तहसील जमुवा रामगढ़,
जिला जयपुर . . . प्राथी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमैन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस—प्रेम प्रकाश, एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर।

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमैन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर। . . . अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी.एल. हिस्सारिया, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे.के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर.सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमैन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि., जयपुर के विरुद्ध औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरैंस सं. 4/88 लंबित है, जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई हो जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सैवा मुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये।

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अत:. जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अत: प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन

नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई।

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रेफरैंस सं. सी.आई.टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

6. चूंकि अब रेफरैंस सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. अत: प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"चूंकि प्रकरण सं. सी.आई.टी. 95/89 को निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

8. अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी.एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 372.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी.आई.टी.-7/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29025/4/2005-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

176 GI/05-17

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 372.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (C.I.T. 7/89) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L-29025/4/2005-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 7/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री रमसी पुत्र श्री बकसा मीना, उम्र 40 वर्ष,
निवासी ग्राम डगोता पो. नीमला वाया सैंथल, तह. जमुवा रामगढ़,
जिला जयपुर . . . प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस-प्रेम प्रकाश, एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर।
2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर। . . . अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी.एल. हिस्सारिया, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे.के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर.सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक

सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरैंस सं. 4/88 लंबित है, जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये।

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अत: प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने के प्रार्थना की गई है।

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रेफरैंस सं. सी.आई.टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

6. अब चूंकि रेफरैंस सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. अत: प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"चूंकि प्रकरण में सी.आई.टी. 95/89 को निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

8. अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी.एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 373.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी.आई.टी.-8/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29025/5/2005-आई. आर. (विविध)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 373.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (C.I.T. 8/89) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L-29025/5/2005-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 8/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

घोसा पुत्र सोन्या धानका , उम्र 54 वर्ष,
निवासी ग्राम रामपुरा पो. बारोंदा बाया सैंथल, तहसील दौसा
जिला जयपुर . . . प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि. रजिस्टर्ड ऑफिस-प्रेम प्रकाश, एस.एम.एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर।
2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर। . . . अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी.एल. हिस्सारिया, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे.के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर.सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा.लि., जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति को कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके श्रमिक के मध्य एक जनरल रैफरैंस सं. 4/88 लंबित है, जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक हैं किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जावे एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जावे ।

2. विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अत: प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने के प्रार्थना की गई है।

5. उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरैंस सं. सी.आई.टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

6. अब चूंकि रैफरैंस सं. सी.आई.टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी से समझौता कर लेने के कारण नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. अत: प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"चूंकि प्रकरण सं. सी.आई.टी. 95/89 को निस्तारण किया जाकर प्रार्थी के संबंध में नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

8. अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

पी.एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 374.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 13/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं-एल.-29025/10/2005-आई. आर. (विविध)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 374.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (C. I. T. 13/89) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L-29025/10/2005-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 13/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

रामप्रताप पुत्र रामधन मीना, उम्र 53 वर्ष, निवासी ग्राम-पोस्ट सैंथल, तहसील दौसा, जिला जयपुर . . . प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस—प्रेम प्रकाश, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलेपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जुमवा रामगढ़, जिला जयपुर . . . अप्रार्थीगण

उपस्थित :

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

(1) प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलेपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि., जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा-मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है, किन्तु उसकी सेवामुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवामुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवामुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवामुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवामुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जावे एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जावे।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया था, अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अत: प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवामुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवामुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेपित किया गया है, अत: अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम

कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई।

(5) उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरैंस सं. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

(6) अब चूंकि रैफरैंस केस नं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(7) अत: प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :—

"चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवामुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

(8) अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 375.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 3/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29025/14/2005-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 375.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (C. I. T. 3/89) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L-29025/14/2005-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 3/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री मातादीन पुत्र श्री हरबक्ष मीना, उम्र 41 वर्ष, निवासी ग्राम डगौता पो. नीमला घाया सैंथल, तह. जमुवा, रामगढ़ जिला जयपुर ... प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस—प्रेम प्रकाश, एस. एम.एस. हाईवे, जयपुर -302002 जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलेपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़ जिला जयपुर ... अप्रार्थीगण

उपस्थित :

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

(1) प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलेपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा-मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है, किन्तु उसकी सेवामुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवामुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवामुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवामुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवामुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवामुक्ति

आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया था, अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अत: प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरूद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई।

(5) उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरैंस सं. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

(6) अब चूंकि रैफरैंस केस नं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(7) अत: प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :—

"चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

(8) अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 376.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 2/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-01-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29025/15/2005-आई. आर. (विविध)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 376.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (C. I. T. 2/89) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-01-2005.

[No. L-29025/15/2005-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 2/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1957

श्री किशना पुत्र श्री प्रभु जोगी, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम किशनावाला, पोस्ट नोमला वाया सैंथल, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर . . . प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस—प्रेम प्रकाश, एस. एम.एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर।

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर . . . अप्रार्थीगण

उपस्थित :

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.।

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

(1) प्रार्थी श्री किशन ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है, किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक को कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अत: प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरूद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक की सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई।

(5) उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरैंस सं. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

(6) अब चूंकि रैफरैंस केस नं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(7) अत: प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :—

"चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

(8) अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 377.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 4/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29025/13/2005-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 377.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. C.I.T. 4/89) of the Central Industrial Tribunal Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Sundicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005.

[No. L-29025/13/2005-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 4/89

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री झुंथा पुत्र श्री रूगा मीना, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम बासडी, पोस्ट बोरोदा वाया सैंथल, तहसील दौसा, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस-प्रेम प्रकाश, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर।
2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि., डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर। ....अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

(1) प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरेंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरेंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अत: प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरेंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अत: प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरेंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई।

(5) उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरेंस सं. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

(6) अब चूंकि रैफरेंस केस नं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना पत्र, प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(7) अतः प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

(8) अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 378.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 5/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-29025/12/2005-आई. आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 378.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (No. C.I.T. 5/89) of the Central Industrial Tribunal, Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Sundicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005.

[No. L-29025/12/2005-IR(Misc.)]

B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 5/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री भंवरलाल पुत्र श्री माधो मीना, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम-पोस्ट नीमला, वाया सैंथल, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस-प्रेम प्रकाश, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर।

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि., डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर। ....अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

(1) प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अतः दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है। अतः प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अतः जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: इस प्रार्थना पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई।

(5) उक्त प्रार्थना-पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरैंस सं. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

(6) अब चूंकि रैफरैंस केस नं. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(7) अत: प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना-पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

(8) अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2005

का. आ. 379.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर मिनरल डवलपमेंट सिंडीकेट प्रा. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या सी. आई. टी. 14/89) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-1-2005 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-29025/11/2005-आई. आर. (विविध)]
बी. एम. डेविड, अवर सचिव

New Delhi, the 10th January, 2005

S.O. 379.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (No. C.I.T. 14/89) of the Central Industrial Tribunal Jaipur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Mineral Development Sundicate Pvt. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 10-1-2005.

[No. L-29025/11/2005-IR(Misc.)]
B. M. DAVID, Under Secy.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 14/89

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

श्री श्योराम पुत्र श्री हरबक्ष मीना, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम डगोता वाया सैंथल, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. रजिस्टर्ड आफिस-प्रेम प्रकाश, एस. एम. एस. हाईवे, जयपुर जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर।

2. माइन्स मैनेजर, डगोता सोप स्टोन माइन्स, जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि., डगोता, तहसील जमुवा रामगढ़, जिला जयपुर। ....अप्रार्थीगण

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री पी. एल. हिस्सारिया, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. के. अग्रवाल

अप्रार्थी की ओर से : श्री आर. सी. पापड़ीवाल

दिनांक अवार्ड : 6-11-2004

अवार्ड

(1) प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी जयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिण्डीकेट प्रा. लि. जयपुर के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे आगे अधिनियम लिखा जा रहा है) की धारा 33-ए के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वह विपक्षी संस्थान का स्थाई श्रमिक है, उसका कार्य हमेशा संतोषप्रद रहा है, वह राष्ट्रीय खनन मजदूर कांग्रेस सोप स्टोन माइन्स डगोता का सक्रिय सदस्य है तथा उसे

अचानक विपक्षी संस्थान ने दिनांक 7-10-88 को समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित कर सेवा से हटा दिया। सेवा समाप्ति से पूर्व सेवा मुक्ति का कोई कारण उसे नहीं बताया, न ही उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिकरण के समक्ष विपक्षी संस्थान एवं उसके मध्य एक जनरल रैफरेंस सं. 4/88 लंबित है जिससे प्रार्थी भी संबंधित श्रमिक है किन्तु उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व अधिनियम के प्रावधान के अनुसार न तो प्रार्थी को सेवा मुक्त करने की अनुमति अधिकरण से प्राप्त की गई, न ही धारा 33(2)(बी) अधिनियम के तहत सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन कराया गया, न ही ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया। अत: प्रार्थी की सेवा मुक्ति अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई है जो अवैध व अनुचित है। प्रार्थी चूंकि यूनियन का सक्रिय सदस्य है, अत: दुर्भावनापूर्ण रूप से उसकी सेवा मुक्ति की गई है। अत: प्रार्थी की प्रार्थना है कि उसका सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 7-10-88 अनुचित व अवैध घोषित किया जाकर अपास्त किया जाये एवं उसे समस्त पिछले वेतन व अन्य लाभ सहित सेवा में बहाल किया जाये।

(2) विपक्षी संस्थान ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्ति की है कि उपरोक्त रैफरैंस सं. 4/88 से श्रमिक किसी प्रकार संबंधित श्रमिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि धारा 33-ए का प्रार्थना-पत्र श्रमिक की कन्डीशन ऑफ सर्विस में परिवर्तन न्यायाधिकरण में रैफरैंस लंबित होने की स्थिति में करने पर ही शिकायत स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विवाद सं. 4/88 किसी भी प्रकार कन्डीशन ऑफ सर्विस से संबंधित नहीं कहा जा सकता, अत: प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवाद सं. 4/88 के संबंध में अधिकरण द्वारा 30-12-88 को ही नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित कर दिया गया था, अत: जिस दिन प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया उस दिन कोई रैफरैंस अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं था, अत: प्रार्थना-पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

(3) गुणावगुण पर अप्रार्थी का इतना ही जवाब है कि दिनांक 7-10-88 को जो सेवा मुक्ति आदेश प्रार्थी के विरुद्ध पारित किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(4) प्रकरण में विपक्षी संस्थान द्वारा 1-4-91 को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि श्रमिक को सेवा मुक्ति से संबंधित विवाद भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रेषित किया गया है, अत: इस प्रार्थना-पत्र पर कोई अग्रिम कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है, अत: उपरोक्त रैफरैंस सं. 95/89 के निस्तारण तक इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की गई।

(5) उक्त प्रार्थना-पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् आदेशिका दिनांक 13-1-92 में पारित आदेश के अनुसार इस पत्रावली को भी उपरोक्त रैफरैंस सं. सी. आई. टी. 95/89 के निस्तारित होने तक उसी पत्रावली के साथ कन्सोलीडेट कर दिया गया।

(6) अब चूंकि रैफरैंस केस नं. आई. टी. 95/89 का निस्तारण हो चुका है एवं उसमें पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को सेवा में बहाल करने एवं उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया गया है, ऐसे में यह प्रार्थना-पत्र, प्रार्थी का निष्प्रभावी होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(7) अत: प्रकरण में निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :

"चूंकि प्रकरण सं. सी. आई. टी. 95/89 का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की सेवा मुक्ति को अपास्त किया जाकर उसे समस्त लाभ दिलाये जाने का अवार्ड पारित किया जा चुका है, ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 33-ए अधिनियम निष्प्रभावी होने से अस्वीकार किया जाता है, प्रार्थी इस प्रार्थना-पत्र के जरिये कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।"

(8) अवार्ड आज दिनांक 6-11-2004 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

पी. एल. हिस्सारिया, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2005

का. आ. 380.—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उप-खण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1719 दिनांक 8-7-2004 द्वारा करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड जोकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 25 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-7-2004 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छ: मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अत: अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ़) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-1-2005 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या एस.-11017/3/91-आई. आर. (पी. एल.)]

जे. पी. पति, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th January, 2005

S.O. 380.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O.

No. 1719 dated 8-7-2004 the service in Currency Note Press, Nashik Road which is covered by item 25 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 15th July, 2004.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the provisio to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 15th January, 2005.

[File No. S. 11017/3/91-IR(PL)]
J. P. PATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 2005